वार्षिक रिपोर्ट

(1985-86)

वार्षिक रिपोर्ट

(1985-86)

NIEPA DC
D09366

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
17-बी, श्री अरबिंद मार्ग, नई दिल्ली-110016

फरवरी, 1987/पी०यू-बी०एस/ए० आर-ई
250 प्रतियां

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, 1987

LIBRARY & DOCUMENTATION Centre
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No..... D-9366
Date..... 5-12-96

हिन्दी अनुवाद : केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय,
पश्चिमी खण्ड-7, राम कृष्णपुरम, नई दिल्ली

श्री आर० पी० सक्सेना, कुल सचिव, नीपा द्वारा संकलित और श्री बालकृष्ण सेल्वराज, प्रकाशन अधिकारी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, 17-बी अरबिंद मार्ग, नई दिल्ली द्वारा टैक्स्ट डिजाइन और हरीकृष्ण प्रिंटर्स, शाहदरा, दिल्ली-110032 द्वारा मुद्रित ।

आभार ज्ञापन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, योजना आयोग, राज्य सरकारों, दिल्ली प्रशासन, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, भारतीय समाज विज्ञान परिषद्, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, इन्द्रा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद; भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली; अनुप्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, नई दिल्ली, वायु सेवा का शिक्षा अनुभाग, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली, आर्थिक विकास संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली, केन्द्रीय विद्यालय संस्थान, माध्यमिक शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड नई दिल्ली, राज्यीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राज्यीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली तथा भारतीय शिक्षा संस्थान पूना के संस्थान के क्रियाकलापों में सहयोग तथा रुचि लेने के लिए आभार प्रकट करता है।

संस्थान प्रशिक्षण के लिए आए विभिन्न विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों की उनके क्षेत्र दौरों के दौरान स्वागत करने के लिए विभिन्न विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के प्रति भी आभार प्रदर्शित करता है।

विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन में अतिथि वक्ता अथवा संसाधन व्यक्तियों के रूप में जिन विशेषज्ञों ने भाग लिया है, संस्थान उनका आभारी है।

संस्थान के कुछ कार्यक्रमों के संचालन में निम्नांकित संस्थाओं से सहयोग मिला है, संस्थान उनका आभार स्वीकार करता है। ये संस्थाएं हैं—यू० एम० डी० पी०, शैक्षिक योजना का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, पेरिस, यूनेस्को सांख्यिकी कार्यालय, पेरिस, एशिया तथा ओसियानिया के लिए यूनेस्को का क्षेत्रीय कार्यालय बैंकाक, यूनाइटिड नेशंस एशिया एण्ड पैसिफिक सेंटर, क्वालालमपुर, नेशनल एसोसिएशन फार एशिया एण्ड पैसिफिक एजुकेशन; यूनाइटिड स्टेट्स, एजुकेशनल फाउंडेशन इन इण्डिया, कामनवेल्थ फंड फार टेकनिकल क्वापरेशन, लंदन तथा विशेष कामनवेल्थ अफ्रीकन एसिसटेंस प्लान (स्केप), भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के अंतर्गत भारत सरकार के सहयोग तथा तीसरे विश्व देशों के शिक्षा अधिकारियों के लिए इण्डोर कामनवेल्थ फैलोशिप कार्यक्रमों के लिए भी संस्थान आभार प्रकट करता है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इसकी गतिविधियों में रुचि लेने के लिए और सहयोग करने के लिए

संस्थान निम्नांकित देशों की सरकारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है—अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, चीन, फीजी, घाना, इण्डोनेशिया, क्वैत, लाओस, मलेशिया, मालद्वीप, नामिबिया, नेपाल, पाकिस्तान, पपुआ तथा न्यूगिनी, फिलिपाइन्स, कोरिया गणराज्य, श्रीलंका, तनजातिया, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमरीका, वियतनाम तथा जाम्बिया।

विषय-सूची

आभार ज्ञापन			
विहंगावलोकन			9
भाग-1	:	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यक्रम	15
भाग-2	:	अनुसंधान और अध्ययन	35
भाग-3	:	परामर्शदायी, सलाहकारी और समर्थनकारी सेवाएं	50
भाग-4	:	अन्य अकादमिक क्रियाकलाप	60
भाग-5	:	शैक्षणिक एकक	65
भाग-6	:	अकादमिक आधारिक संरचना	72
भाग-7	:	प्रशासन और वित्त	79

अनुबन्ध

I	:	प्रशिक्षण कार्यक्रम	89
II	:	चालू अनुसंधान अध्ययन	112
III	:	संकाय का अकादमिक योगदान	120
IV	:	आगंतुक गण	130

परिशिष्ट

I	:	परिषद के सदस्य	135
II	:	कार्यकारिणी समिति के सदस्य	138

III	:	वित्त समिति के सदस्य	140
IV	:	कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य	142
V	:	प्रकाशन सलाहकार समिति के सदस्य	143
VI	:	संकाय तथा प्रशासनिक स्टाफ	143
VII	:	वार्षिक लेखा तथा अंकेक्षण रिपोर्ट	151

प्रशिक्षण कार्यक्रम

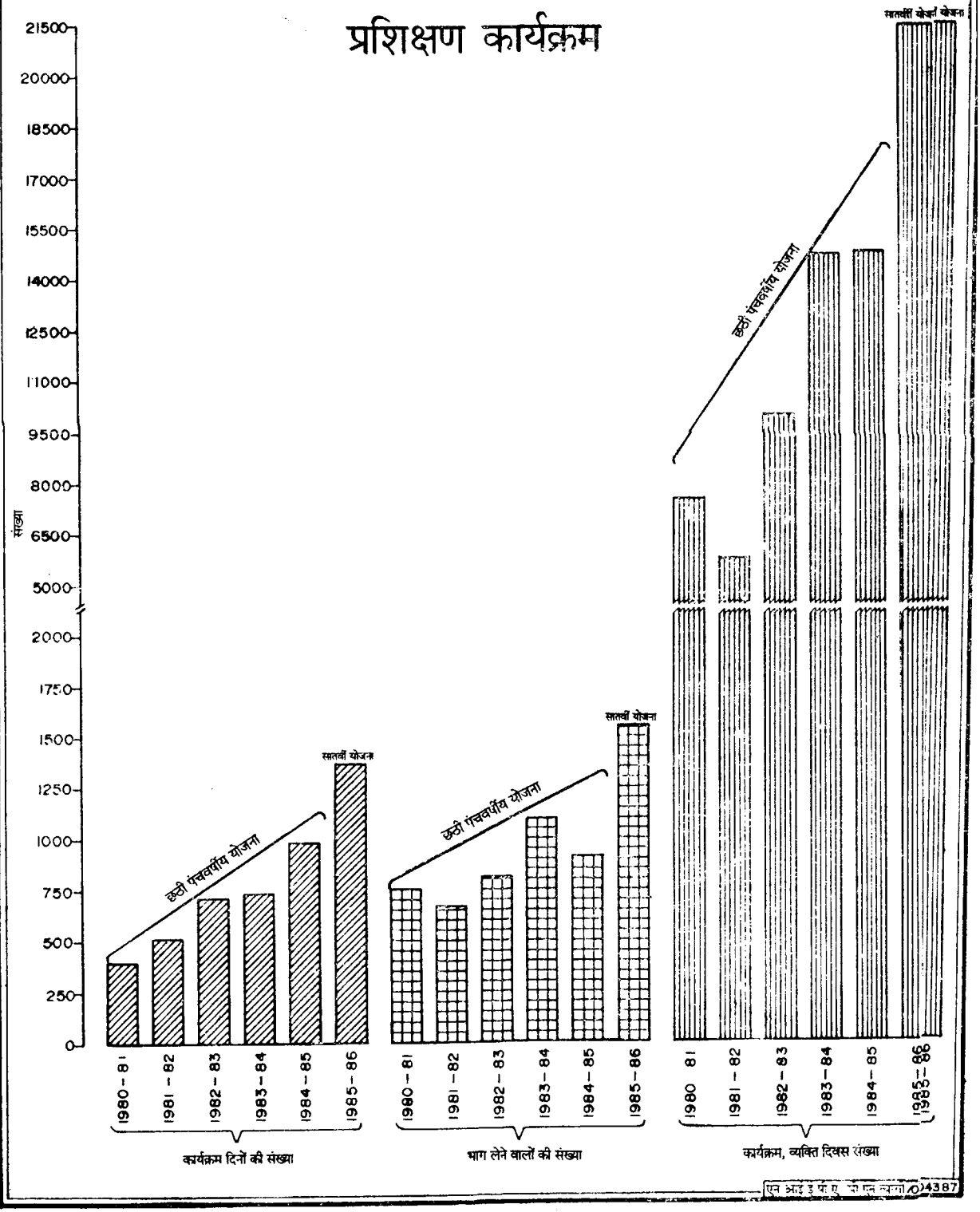

विहंगावलोकन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान की स्थापना भारत सरकार ने 1970 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की थी। इसके पहले यह संस्थान 'शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों का राष्ट्रीय स्टाफ कालेज' के नाम से जाना जाता था। 1962 में इसकी स्थापना 'शैक्षिक योजना और प्रशासन का एशियाई संस्थान' के आम से 10 वर्षीय अनुबंध के तहत यूनेस्को द्वारा की गई थी। बाद में भारत सरकार ने इसकी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी। संस्थान के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—शैक्षिक नियोजकों तथा प्रशासकों का प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्शकारी तथा सलाहकारी सेवायें तथा नवाचारों का विसरण।

इस रिपोर्ट में अप्रैल, 1985 से मार्च, 1986 तक की संस्थान की मुख्य गतिविधियों का विवरण दिया गया है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषतायें नीचे दी गई हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान संस्थान ने 57 कार्यक्रम आयोजित किये, इसके पूर्ववर्ती वर्ष में 53 कार्यक्रम संस्थान ने चलाए थे। 57 कार्यक्रमों में से 54 कार्यक्रम राष्ट्रीय तथा उप-राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित किए गए थे और शेष तीन अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम थे। इसके अतिरिक्त रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान वर्ष 1984-85 में चलाये गए तीन अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को भी पूरा किया गया। कार्यक्रमों में भाग लेने वालों तथा कार्यक्रम-व्यक्ति-दिवस क्रमश: 1,551 तथा 21,862 थे जो संस्थान के प्रारंभ होने से लेकर वर्तमान समय तक किसी एक वर्ष में रिकार्ड प्राप्ति थी।

इसमें कुल 1551 भागीदारों ने हिस्सा लिया, जिसमें 1354 लोग विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के थे, 132 लोग भारत सरकार के कार्यालयों तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के थे, तथा 65 लोग बाहर के देशों के थे।

क्षेत्रवार भागीदारी इस प्रकार थी : उत्तरी क्षेत्र से सबसे अधिक थी (647), इसके बाद क्रमश: पश्चिमी क्षेत्र (397), उत्तरी क्षेत्र (168) तथा दक्षिणी क्षेत्र (142) से। राज्यों में से सबसे अधिक भागीदारी हरियाणा (338) की थी। इसके पश्चात् क्रमश: मध्यप्रदेश (210), महाराष्ट्र (94) तथा उत्तर प्रदेश (85) थे।

वर्ष के दौरान संस्थान ने भारत के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित किए जबकि पूर्ववर्ती वर्षों में प्रत्येक में एक कार्यक्रम ही आयोजित किया

जाता रहा था। डिप्लोमा पाठ्यक्रम के कार्यक्रमों में 19 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से 55 अधिकारियों ने भाग लिया।

शैक्षिक योजना और प्रशासन में वर्ष 1984-85 के दौरान शुरू किया गया पहला अन्तर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम इस वर्ष पूरा किया गया और दूसरा डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। इन अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रमों में 11 देशों के 22 अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षा की चुनौती में उल्लिखित निम्नलिखित वरीयता क्षेत्रों पर विशेष बल दिया : माइक्रो (सूक्ष्म) स्तरीय योजना, सार्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ तथा गैर-औपचारिक शिक्षा, शैक्षिक योजना में कम्प्यूटर का अनुप्रयोग, व्यवसायीकरण का प्रबंध, शिक्षा में समता, आदिवासी क्षेत्रों में संस्थागत योजना, स्वायत्त संस्थाओं की योजना और प्रबंध, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग तथा परिवर्तन का प्रबंध। बड़े पैमाने पर समुदाय की भागीदारी के लिए कुशल कार्य नीति बनाने में पूना में आयोजित क्रिया अनुसंधान कार्यक्रम में अपनाई गई कुशल कार्य नीतियों तथा अनुभवों का भी उपयोग किया गया।

कुछ उच्चतर शिक्षा के विकास तथा योजना के लिए आधार-सामग्री प्रक्रमण तथा विश्वविद्यालय प्रशासकों के लिए विश्वविद्यालय प्रबंध पद्धति में कम्प्यूटरों के प्रबंध की आधुनिक पद्धतियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले नए क्षेत्र हैं। वर्ष 2000 में शिक्षा की अपेक्षाओं का पूर्वानुमान लगाने तथा जनांकिकीय विकास और अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों से इसकी संबद्धता तथा दीर्घावधि योजना के मामलों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया। एक अन्य नए क्षेत्र उत्पादकता और शिक्षा, को भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया।

समुदाय के सहयोग तथा भागीदारी तथा अन्य विभागों से संबद्धता के आधार पर प्रौढ़ शिक्षा में क्षेत्र स्तर की परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित कुशल कार्य नीतियां/मार्गदर्शी रूपरेखायें तैयार की गईं।

संस्थान ने राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ शिक्षा प्रशासकों, विद्यालय प्रधानाचार्यों, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वरिष्ठ कार्मिकों, विश्वविद्यालय वित्त अधिकारियों, कालेजों के प्रधानाचार्यों, कालेजों के विज्ञान विभागों के विभागाध्यक्षों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रबंध में शृंखलाबद्ध सतत कार्यक्रमों का संचालन किया।

सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतःशास्त्रीय प्रकार के थे। प्रायोगिक कार्य, सिंडीकेट कार्य, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग, कम्प्यूटर, फिल्म, विडियो तथा ओवर हैड प्रोजेक्टर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मूल थे।

प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्यतः मूल्यांकन तत्व निहित है। कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा प्रासंगिकता बनाये रखने तथा प्रशिक्षण की कुशल नीतियों के विकास के लिए संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए भी एक अध्ययन किया गया।

अनुसंधान और अध्ययन

वर्ष के दौरान अनुसंधान और अध्ययन पर सरकारी अनुदान के 2.97 लाख रुपए खर्च किए गए। संस्थान

ने विधिक अनुसंधान कार्यक्रमों के तहत 8·60 लाख की अतिरिक्त निधि का भी प्रयोग किया। अनुसंधान तथा अध्ययनों पर व्यय की जाने वाली सरकारी अन्य साधनों से प्राप्त राशि 11.57 लाख है। वर्ष के दौरान नीचे दिए गए 20 अध्ययन पूरे किए गए—

—विद्यालयों में अध्यापक-छात्र के बीच इष्टतम अनुपात का अध्ययन;
—भारत में शैक्षिक नीति तथा योजना का अध्ययन योजना आयोग की भूमिका;
—वर्तमान स्थिति तथा भविष्य परिप्रेक्ष्य;
—विकास के कुछ आयामों पर शैक्षिक स्तरों का प्रभाव—ग्रामीण गृह सेवाओं का अध्ययन।
—शिक्षा का बाह्य वित्तीयन;
—नई शिक्षा नीति के निर्माण में निवेश के रूप में, विविध दस्तावेजों/सम्प्रेषणों/रिपोर्टों के विषय-वस्तु विश्लेषण पर आधारित अध्ययन;
—भारतीय शिक्षा की पुनः संरचना की दिशा में : नागरिकों के प्रत्यक्षण (खण्ड 1 से 4)
—भारतीय शिक्षा पद्धति का सामाजिक लेखा परीक्षण;
—जनवाणी सम्प्रेषणों का एक अध्ययन;
—भारतीय शिक्षा की पुनः संरचना की दिशा में—तकनीकी संस्थाओं प्रत्यक्षण।
—भारतीय शिक्षा की पुनः संरचना की दिशा में विश्वविद्यालयों से संबंधित।
—भारतीय शिक्षा की पुनः संरचना की दिशा में शैक्षिक संस्थाओं। बोर्डों के सुझाव;
—भारतीय शिक्षा की पुनः संरचना की दिशा में गैर शैक्षिक संगठनों के विचार;
—शिक्षा के स्वायत्तता प्राप्त तथा व्यावसायिक तिकाय (खण्ड 1 तथा 2);
—नई शिक्षा नीति पर प्रेसः प्रेस कतरनों का विश्लेषण;
—भारतीय शिक्षा की पुनः संरचना की दिशा में प्रेस के दृष्टिकोण;
—नई शिक्षा नीति : उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में;
—भारतीय शिक्षा की पुनः संरचना की दिशा में : राज्य स्तर के विचार-विमर्शों का विश्लेषण;
—भारतीय शिक्षा की पुनः संरचना की दिशा में राज्यों के प्रत्यक्षण (विचार);
—वर्ष 2000 में भारतीय शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत किये गए चार पूरे अध्ययन—दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य;
—भारत में प्राथमिक शिक्षा—कुछ परिगणना साक्ष्य;
—शैक्षिक योजना और प्रबंध के लिए प्रतिरूपण माडलों के प्रयोग के लिए प्राथमिक शिक्षा;
—भारत सें प्राथमिक शिक्षा : एक वृद्धि विश्लेषण;
—भविष्य-विकास के लिए शिक्षा की योजना-समस्यायें तथा विकल्प;

18 अध्ययन प्रगति पर हैं और 4 नए अध्ययनों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसमें जिला गुड़गांव के पुनहाना खंड के 20 ग्रामों के समूह सें प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में नवाचारी अभ्यासों, अनुसंधान तथा कालेजों के विकास तथा कुशलतापूर्ण कार्य करने पर आधारित दो क्रिया अनुसंधान अध्ययन सम्मिलित हैं। 'भारत में आदिवासी साक्षरता : क्षेत्रीय आयाम' तथा 'भारत में शिक्षा की लागत का विश्लेषण' विषयों पर दो प्रासंगिक पत्र भी प्रकाशित किए गए।

सलाहकारी, परामर्शकारी तथा समर्थनकारी सेवाएं

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुरोध पर तथा उनके सहयोग से राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने कई अनुसंधान अध्ययन और कार्यक्रम हाथ में लिए। संस्थान ने केन्द्र तथा राज्य सरकारों को, तथा योजना और प्रशासन में लगे संगठनों को संकाय समर्थन शैक्षणिक तथा व्यावसायिक परामर्श प्रदान करना जारी रखा।

संस्थान ने मंत्रालय द्वारा 'शिक्षा की चुनौती—एक नीति परिप्रेक्ष्य' शीर्षक से तैयार किए गए एक पत्र में, जो शिक्षा के महत्वपूर्ण मामले पर राष्ट्रीय वाद-विवाद का आधार बना, योगदान के रूप में शिक्षा विकास—एक परिस्थिति रिपोर्ट तथा 'नीति निर्धारण समस्यायें' शीर्षक से एक विशद पत्र तथा शैक्षिक पद्धति की समस्याओं का क्षेत्रवार विश्लेषण तैयार किया। यहां पर नई शिक्षा नीति के निर्माण से संबंधित संगठनों तथा व्यावसायिक निकायों से प्राप्त वैयक्तिक पत्रों, प्रेस की कतरनों जिला राज्य स्तर की संगोष्ठियों तथा ज्ञापनों की रिपोर्टों के रूप में मंत्रालयों में प्राप्त 10,000 दस्तावेजों के विषय-वस्तु विश्लेषण का भी विशेष उल्लेख किया जा सकता है। संस्थान द्वारा अध्ययन रिपोर्ट (16 खंडों में) तैयार की गई तथा इस सामग्री का उपयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने में किया गया। संस्थान ने नई शिक्षा नीति में शैक्षिक योजना तथा प्रबंध की समस्याओं पर परिचर्चा करने के लिए चार क्षेत्रीय स्तर की एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों का भी आयोजन किया। संस्थान के संकाय ने बहुत से शोध-पत्र भी तैयार किए तथा मंत्रालय द्वारा संगठित विविध कार्य समूहों में सक्रिय भाग लिया। संस्थान ने अनेक राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों, व्यावसायिक तथा अन्य निकायों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित संगोष्ठियों/समितियों/बैठकों में भी भाग लिया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के अनुरोध पर शैक्षणिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में 9-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए गैर औपचारिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परियोजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन में तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की सम्मलित सलाह से माडल स्कूली की योजना के निर्माण में संस्थान द्वारा दी गई सहायता का भी यहां उल्लेख किया जा सकता है।

नवाचारों का विसरण

नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने और साथ ही स्वायत्तता प्राप्त करने के इच्छुक कालेजों के लाभ के लिए स्वायत्त कालेजों के विकास तथा अनुभवों का अध्ययन करने के विचार से चुने हुए 20 कालेजों के प्रधानाचार्यों द्वारा स्वायत्त कालेजों का दौरा किया गया। 'स्वायत्तता तथा उत्तरदायित्व' शीर्षक से एक प्रारूप रिपोर्ट भी तैयार की गई।

नीपा वार्तालाप संगोष्ठी

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 16 विषयों पर वार्तालाप संगोष्ठी आयोजित की गयी। इससे राष्ट्रीय शैक्षिक नीति से लेकर कम्प्यूटर तथा शिक्षा में प्रौद्योगिकी जैसे विविध विषय शामिल थे।

राष्ट्रीय पुरस्कार

शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवीन संप्रत्ययों तथा प्रयोगों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम के अन्तर्गत चौथी अखिल भारतीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सरकारी उच्चतम माध्यमिक स्कूल, फिरोजपुर (पंजाब) के प्रधानाचार्य श्री एम० एस० सचदेव द्वारा स्कूलों के छात्रों में 'अनुशासनहीनता के कारणों की खोज तथा उपचारी उपायों का प्रयोग शीर्षक से भेजी गई प्रविष्टि को सर्वश्रेष्ठ माना गया और पुरस्कृत किया गया।

अकादमिक समर्थनकारी सेवायें

पुस्तकालय अपना पाक्षिक अनुलेखित प्रकाशत 'शिक्षा में पत्रिकाएं : प्राप्त शीर्षक और उनकी विषय वस्तु' निकालता रहा है। पुस्तकालय ने यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'एजुकेशन इन एशिया एंड पेसिफिक : रिव्यूज, रिपोर्टस एवं नोट्स' में एशियाई दस्तावेजों पर टिप्पणियों शीर्षक से भारतीय प्रलेख संबंधी संदर्भांकनों द्वारा अपना योगदान किया है।

प्रलेखन केन्द्र ने समाचार पत्रों की समाचार मदों तथा विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मासिक शैक्षिक समाचार प्रकाशित किए हैं।

प्रकाशन एकक शैक्षिक योजना और प्रशासन में 'ईपा' एक त्रैमासिक बुलेटिन प्रकाशित करता रहा है तथा अनेक मूल्य वाले तथा निःशुल्क प्रकाशन, अनुसंधान प्रकाशन तथा शृंखलाबद्ध प्रसांगिक शोध पत्र भी निरन्तर प्रकाशित करता रहा हैं।

संस्थान के बहुमुखी तथा उत्तरोत्तर बढ़ते हुए कार्यक्रमों, अनुसंधान तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को पुस्तकालय, प्रलेखन केन्द्र, प्रकाशन एकक, हिंदी कक्ष, डाता बैंक, कार्तोग्राफिक कक्ष (आरेखण कक्ष) तथा इलेक्ट्रानिक डाता प्रोसेसिंग तथा रिप्रो ग्राम यूनिट से लगातार बहुमूल्य समर्थन मिलता रहा।

मानव संसाधन विकास

अकादमिक तथा अन्य स्टाफ की सेवाकालीन प्रशिक्षण को मानव संसाधन विकास का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। वर्ष के दौरान चार संकाय सदस्यों, प्रलेखन अधिकारी तथा पुस्तकालाध्यक्ष ने विदेशों में विशेषज्ञता वाले तथा उन्नत प्रशिक्षित पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

समूह बचत संबद्ध बीमा योजना

संस्थान में मार्च, 1986 से केन्द्र सरकार की कर्मचारी समूह बीमा योजना के पैटर्न पर भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बचत संबद्ध बीमा योजना प्रारंभ की गई। संस्थान के सभी पात्रता प्राप्त कर्मचारियों ने इस योजना में भाग लेना स्वीकार किया। यह योजना संस्थान की सभी नई भर्तियों पर अनिवार्यतः लागू होगी। इस योजना की शुरुआत से संकाय के सदस्य असामयिक मृत्यु के प्रति पर्याप्त रूप से आश्वस्त होंगे। यह उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी अति कल्याणकारी उपाय है।

नीपा के नियम तथा विनियम

नीपा के नियम तथा विनियम समीक्षाधीन हैं। प्रारूप सेवा विनियम में प्रतिष्ठित आचार्यों के पदों पर नियुक्तियों के नए प्रावधानों सहित राष्ट्रीय अध्येताओं, अभ्यागत अध्येता, योग्यता के आधार पर पदोन्नति योजना तथा संस्थान के विकास के लिए अनिवार्य अन्य प्रावधानों को भी सम्मिलित किया गया है।

कार्यक्रम रिपोर्टिंग तथा कार्यालय उत्पादकता

संस्थान की गतिविधियों का त्रैमासिक संक्षेप (अभिलेखिक) नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता रहा है। कार्यालय की कार्यात्मकता के मुख्य क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए कार्यालय रिपोर्टिंग तथा अनुरक्षण में नवाचारी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें प्राप्तियों के निपटान का परिवीक्षण करने के अतिरिक्त कार्मिक, वस्तुओं की आपूर्ति तथा सेवाएं, सम्पत्ति तथा निर्माण आदि सम्मिलित है।

नीपा का परिसर

निदेशक के आवास का निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है और पूरा होने वाला है। टाइप II में आठ और टाइप III में आठ क्वाटरों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। कार्यालय भवन की तीसरी मंजिल के निर्माण की भी मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 15-20 एकड़ भूमि के अतिरिक्त क्षेत्र की प्राप्ति के लिए अनुरोध भी किया गया है। संस्थान में अभी भी कार्यालय तथा आवास एकक के लिए बहुत स्थानाभाव है।

वित्त

वर्ष 1985-86 के दौरान सरकारी अनुदान में से कुल व्यय 89.63 लाख रुपये हुए (योजनेत्तर तथा योजना वाले मदों दोनों पर) इसके विपरीत वर्ष 1984-85 में कुल व्यय 80.31 लाख रुपये हुए (योजनेतर तथा योजना वाले मदों पर)। वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त कार्यक्रमों तथा अनुसंधान अध्ययनों पर 17.25 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय की गई।

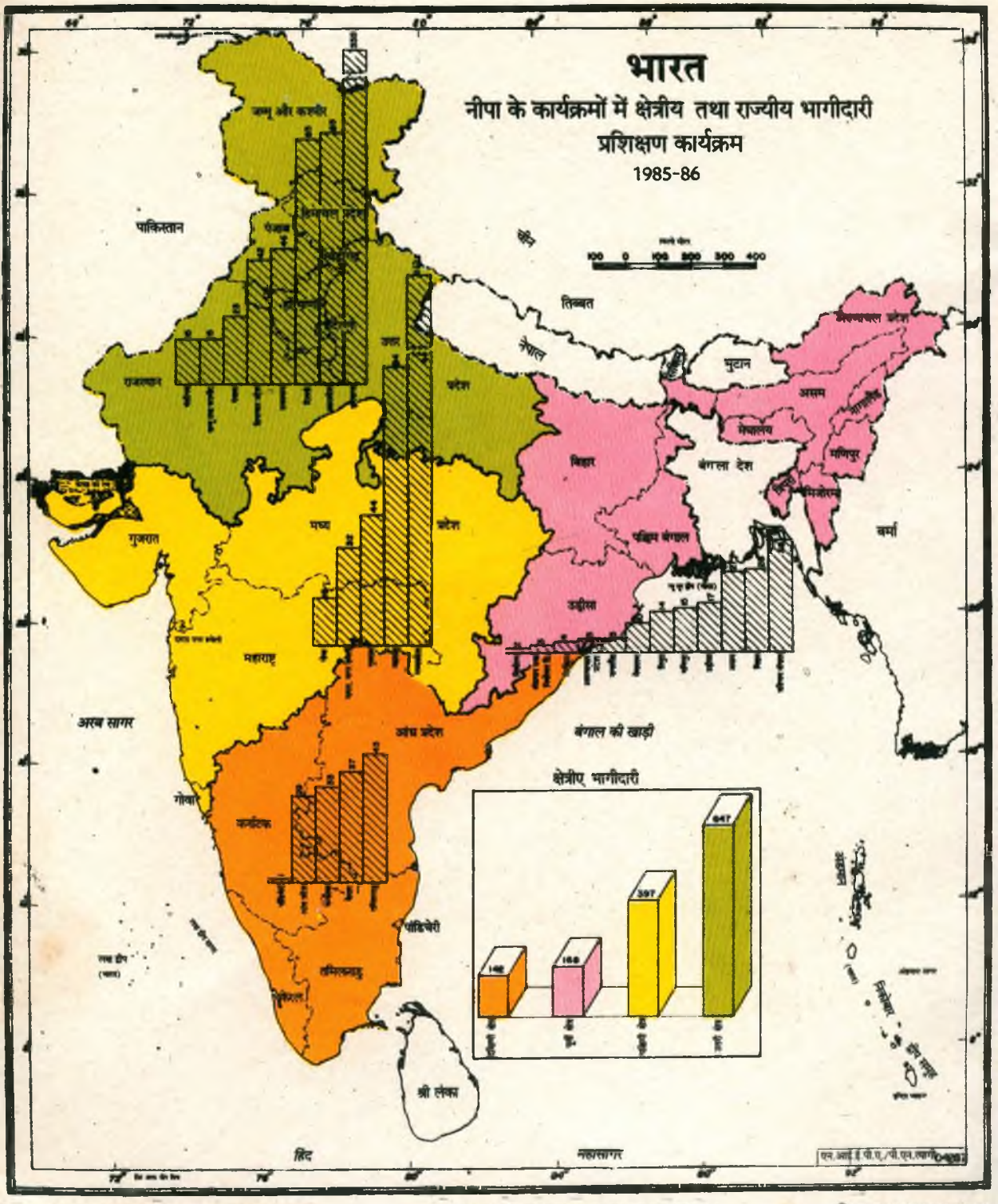

भारत
नीपा के कार्यक्रमों में क्षेत्रीय तथा राज्यीय भागीदारी
प्रशिक्षण कार्यक्रम
1985-86
पाकिस्तान
तिब्बत
नेपाल
भूटान
जम्मू और कश्मीर
राजस्थान
उत्तर
प्रदेश
बिहार
असम
मेघालय
मणिपुर
मिजोरम
बंगला देश
पश्चिम बंगाल
उड़ीसा
बर्मा
गुजरात
मध्य
प्रदेश
महाराष्ट्र
अरब सागर
बंगाल की खाड़ी
आंध्र प्रदेश
कर्नाटक
गोवा
पांडिचेरी
तमिलनाडु
केरल
श्री लंका
हिंद
महासागर
क्षेत्रीए भागीदारी
142
168
397
647

भाग एक

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम

संस्थान ने देश के तथा विदेश से आए हुए शिक्षा कर्मियों के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बहुत से प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों का आयोजन किया।

वार्षिक योजना

नई शिक्षा नीति के निर्माण प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, प्रौढ़ तथा गैर औपचारिक शिक्षा, आदिवासी शिक्षा, शिक्षा-व्यावसायीकरण, शिक्षा में समानता, शैक्षिक विकास में समुदाय की भागीदारी, शैक्षिक, प्रौद्योगिकी आदि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर इस वर्ष के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों की वार्षिक योजना तैयार की गई।

वर्ष 1985-86 की प्रशिक्षण गतिविधियों का कार्यक्रम तैयार करते समय संबद्ध विभागों तथा एजेंसियों से परामर्श करके प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पहचान की गई तथा शिक्षा के विभिन्न अनुभागों द्वारा अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया। वर्ष के प्रारंभ में कार्यक्रम की सूची, जिसमें कार्यक्रम की तिथियों की जानकारी दी गई थी, सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों विश्वविद्यालयों तथा अन्य संबद्ध संस्थाओं को भेज दी गई थी। प्रत्येक कार्यक्रम की पृथक-पृथक घोषणा बहुत पहले ही कर दी गई थी जिससे अधिकारियों को संस्थान के कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए समय पर भेजा जा सके।

व्यापक वर्गीकरण तथा भागीदारी

वर्ष के दौरान 54 राष्ट्रीय तथा उप-राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम चलाए गए। इसके अतिरिक्त पहले से चल रहे 3 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम पूरे किए गए।

कार्यक्रमों का व्यापक वर्गीकरण, उनकी अवधि तथा भागीदारी का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है—

सारणी 1.1 : कार्यक्रमों का व्यापक वर्गीकरण, अवधि तथा भागीदारी

क्र० सं०	एकक कोड नं	कार्यक्रम का नाम	तिथि तथा अवधि	भागीदारी की संख्या	कार्यक्रम व्यक्ति दिवस
1. शिक्षा की राष्ट्रीय नीति					
1.	04/85-86104	शिक्षा की राष्ट्रीय नीति पर उत्तर क्षेत्रीय संगोष्ठी : योजना और प्रबन्ध संबंधी मामले	सितम्बर 28-29, 1985 (2 दिन)	52	104
2.	01/85-86/04	नई शिक्षा नीति की माइक्रोस्तरीय योजना तथा प्रबंध पक्षों पर यूनेस्को द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय कार्यशाला	अक्तूबर 14-नवम्बर 2, 1985 (20 दिन)	25	500
3.	02/85-86/10	शिक्षा की राष्ट्रीय नीति पर पूर्व क्षेत्रीय संगोष्ठी : योजना तथा प्रबंध सम्बन्धी मामले	अक्तूबर 16-17 1985 (2 दिन)	15	30
4.	06/85-86/03	नई शिक्षा नीति की योजना तथा प्रबंध पक्षों पर दक्षिण क्षेत्रीय संगोष्ठी	अक्तूबर 26-27 1985 (2 विन)	31	62
5.	जी/आर पी एस/02	शिक्षा की राष्ट्रीय नीति पर संगोष्ठी योजना तथा प्रबंध संबंधी मामले	नवम्बर, 23-25 1985 (3 दिव)	55	165
6,	01/85-86/05	दीर्घकालीन शैक्षिक योजना के कुछ मामले (शिक्षा नीति पर पश्चिम क्षेत्रीय कार्यशाला, बंबई)	नवम्बर 4-5 1985 (2 दिन)	35	70
			31 दिन	213	931

2. स्कूल शिक्षा की योजना और प्रशासन

1	2	3	4	5	6
7.	07/85-86/02	उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना और मूल्यांकन पर कार्यशाला	मई 31-17 1985 (5 दिन)	5	25
8.	05/85-86/01	जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भर्ती पूर्व चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम	मई 6 नवम्बर 1, 1985 (180 दिन)	20	3600
9.	07/85-86/03	दादर तथा नागर हवेली के अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में प्रशिक्षण कार्यक्रम	मई 29, जून 8, 1985 (11 दिन)	26	286
10.	07/85-86/04	उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के लिए संस्थागत योजना में कार्यशाला	जुलाई 1-3 1985 (3 दिन)	12	36
11.	02/85-86/07	केन्द्रीय विद्यालय के वरिष्ठ प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रबंध में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	जुलाई 22 अगस्त 2, 1985 (12 दिन)	37	444
12.	07/85-86/07	वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में बारहवां अभिविन्यास कार्यक्रम	सितंबर 9-27, 1985 (19 दिन)	10	190

1	2	3	4	5	6
13.	05/85-86/04	जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रबंध में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भर्ती पूर्व पांचवां प्रशिक्षण कार्यक्रम	नवम्बर 18 1985 मार्च 31, 1986 (184 दिन)	35	6440
14.	05/85-86/05	जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए विद्यालय-पर्यवेक्षण में अभिविन्यास कार्यक्रम	जनवरी 6-10, 1986 (5 दिन)	16	80
15.	07/85-86/09	वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में तेरहवां अभिविन्यास कार्यक्रम	फरवरी 10-28 1986 (19 दिन)	17	323
			438 दिन	178	11,424
3. प्रौढ़ तथा गैर औपचारिक शिक्षा की योजना तथा प्रशासन					
16.	07/एस एन एस/06	शैक्षिक रूप से पिछड़े	अगस्त 12-14	9	27
तथा	तथा	हुए राज्यों में प्रारंभिक	1985 (3 दिन)	9	45
19.	07/एस एन एस/08	स्तर पर गैर-औपचारिक शिक्षा के मूल्यांकन अध्ययन के लिए उपकरण डिजाइन करने तथा संक्रिया-योजना को अंतिम रूप देने के लिए कार्यशाला	अक्तूबर 1-5 1985 (5 दिन)		
17.	05/85-86/02	औपचारिक तथा गैर-औपचारिक शिक्षा के बीच समन्वित योजना तथा अनुपूरकता पर यूनेस्को द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय कार्यशाला	सितंबर 16 27, 1985 (12 दिन)	21	252

1	2	3	4	5	6
18.	05/85-86/03	अन्य विभागों के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों तथा गरीबी हटाओ कार्यक्रम में परस्पर निर्भरता प्रबन्ध पर संगोष्ठी तथा कार्यशाला	सितंबर 30= अक्तूबर 4 1985 (5 दिन)	20	100
20.	05/85-86/06	प्रौढ़ शिक्षा कार्मिकों के लिए परियोजना क्रियान्वयन के प्रबन्ध पर राष्ट्रीय कार्यशाला	फरवरी 17-21, 1986 (5 दिन)	45	225
			30	104	649

4. आदिवासी कल्याण शैक्षिक विकास

21.	04/85-86/02	आश्रम विद्यालयों की योजना तथा प्रबन्ध पर अभिविन्यास कार्यक्रम	अगस्त 26-30 1985 (5 दिन)	23	115
22.	04/85-86/03	कंकर के आदिवासी कल्याण विकास विद्यालयों के लिए संस्थागत योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम	सितंबर 10-20 1985 (11 दिन)	68	748
23.	04/85-86/05	मध्य प्रदेश में आदिवासी कल्याण क्षेत्रों के विद्यालयों के अधिक अच्छे पर्यवेक्षण से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिसम्बर 17-24 1985 (8 दिन)	48	384
24.	04/85-86/06	बस्तर जिले, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की शिक्षा और विकास पर कार्यशाला	फरवरी, 24-26 1986 (3 दिन)	46	I38
			27 दिन	185	1385

1	2	3	4	5	6
5. तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध					
25.	02/85-86/06	बहुशिल्प विद्यालयों (पालिटैकिनकों) के लिए शैक्षिक प्रबन्ध में अभिविन्यास कार्यक्रम	जुलाई 1-12 1986 (12 दिन)	13	156
26.	02/85-86/09	शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए प्रबन्ध-माडल के विकास पर कार्यशाला	सितम्बर 9-13 1985 (5 दिन)	22	110
27.	02/85-86/15	+2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना और प्रबन्ध में अभिविन्यास कार्यक्रम	मार्च, 10-14 1986 (5 दिन)	11	55
28.	02/85-86/12	इंजीनियरिंग कालेजों के प्रबन्ध पर संगोष्ठी	फरवरी 24-28 1986 (5 दिन)	8	40
			27 दिन	54	361
6. उच्चतर शिक्षा की योजना तथा प्रशासन					
29.	06/85-86/01	उच्चतर शिक्षा की योजना तथा विकास के लिए आधार सामग्री प्रक्रमण (डेटा प्रोसेसिंग) पर प्रशिक्षण कार्यशाला	अगस्त 21-24 1985 (4 दिन)	26	104
30.	06/85-86/05	कालेजों के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में अभि-विन्यास कार्यक्रम	सितम्बर 9-28 1985 (20 दिन)	32	640
31.	06/85-86/05	महिला कालेजों के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम	दिसम्बर 9-27 1985 (19 दिन)	25	475

1	2	3	4	5	6
32.	06/85-86/06	विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार के लिए कार्यक्रम	दिसम्बर 28-29 1985 (2 दिन)	27	54
33.	02/85-86/11	शिक्षा के विभागों/ कालेजों के लिए शैक्षिक प्रशासन में प्रशिक्षण तथा अनु-संधान पर संगोष्ठी	जनवरी 13-17 1986 (5 दिन)	13	65
34.	06/85-86/07	स्वायता प्राप्त कालेजों का अध्ययन दौरा (मद्रास और मदुरई)	फरवरी 8-14 1986 (7 दिन)	21	147
35.	06/85-86/08	कालेजों के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में अभि-विन्यास कार्यक्रम	फरवरी 24 मार्च 14 1986 (19 दिन)	20	380
36.	06/85-86/09	कालेजों के विज्ञान विभागों के विभागा-ध्यक्षों के लिए विज्ञान शिक्षा की योजना तथा प्रबन्ध में अभिविन्यास कार्यक्रम	मार्च 17-23 1986 (7 दिन)	18	126
			83 दिन	182	1991

7. शैक्षिक प्रबन्ध

37. से	02/85-86/01	हरियाणा के विद्यालय/ कालेजों के प्रधानाचार्यों	अप्रैल, 15-19 1985	44	220
41.	02/85-86/05	के लिए	(5 दिन)		
		+2 स्तर के प्रबंध से संबंधित पहला अभिविन्यास	अप्रैल 22-26 1985 (5 दिन)	49	245
		कार्यक्रम (एक से पांच)	अप्रैल 29 मई 3, 1985 (5 दिन)	43	215

1	2	3	4	5	6
			मई 6-10 1985 (5 दिन)	55	275
			मई 13-17 1985 (5 दिन)	46	230
42.	02/85-86/14	शैक्षिक परिवर्तन के प्रबन्ध पर राष्ट्रीय कार्यशाला	मार्च-3-7 1986 (5 दिन)	8	40
			30 दिन	245	1225
8. शैक्षिक वित्त का प्रबन्ध					
43.	03/85-86/01	विश्वविद्यालय वित्तों के प्रबन्ध में अभिबिन्यास कार्यक्रम	अगस्त 5-9 1985 (5 दिन)	33	165
44.	3/85-86/02	शैक्षिक वित्तों के प्रबन्ध में अभिविन्यास कार्यक्रम	सितम्बर 16-27, 1985 (12 दिन)	19	228
			17 दिन	52	393
9. शैक्षिक प्रौद्योगिकी					
45.	01/85-86/03	शैक्षिक योजना तथा प्रबन्ध में कंप्यूटर के प्रयोग के आरम्भ पर कार्यशाला	मई 20-22, 1985 (3 दिन)	25	75
46.	02/85-86/08	शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रबंध पर कार्यशाला (5 दिन)	सितंबर 2-6 1985 (5 दिन)	21	105
			10 दिन	46	180

1	2	3	4	5	6
10. अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम					
47.	जी/एस बी एन/01	ग्रामीण शिक्षा समिति के प्रबन्ध के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	अप्रैल, 24 1985 (1 दिन)	40	40
48.	04/85-86/01	शिक्षा में समानता से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम	मई 27-31, 1985 (5 दिन)	18	90
49.	08/85-86/04	अनुसंधान के प्रणाली विज्ञानों पर कार्य-शाला	नवम्बर 20-24, 1985 (5 दिन)	45	225
50.	जी/85-86/05	हरियाणा के एक जिले के ग्रामों की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिसम्बर 19-20 1985 (2 दिन)	30	60
51.	03/85-86/03	शिक्षा के संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर कार्यशाला	फरवरी 24-27 1986 (4 दिन)	16	64
52.	जी/आर पी एस/04	भारत में विद्यालयों के लिए अध्यापक-छात्र अनुपात पर संगोष्ठी	फरवरी 26 1986 (1 दिन)	42	42
53.	02/85-86/13	शैक्षिक उत्पादकता तथा उत्पादिता शिक्षा पर कार्यक्रम	मार्च 3-4 1986 (2 दिन)	16	32
54.	01/85-86/06	शिक्षा तथा रोजगार अनुबंधन पर संगोष्ठी	मार्च 19-21 1986 (3 दिन)	44	132
			23 दिन	251	685

1	2	3	4	5	6
11. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम					
	07/85-86/01	यूनेस्को द्वारा प्रायोजित शैक्षिक प्रशासन के विशेष संदर्भ में प्रायोजित कार्यशाला प्रबन्ध में उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम (1984-85 से चल रहा था)	जनवरी 7, दिसम्बर 30 1985 (270 दिन)	1	270
	08/85-86/01	शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में पहला अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (1984-85 से चल रहा है)	जनवरी 14 जुलाई 13 1985 (104 दिन)	12	1248
	01/85/86/01	यूनेस्को द्वारा प्रायोजित दीर्घकालीन शैक्षिक योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम	मार्च 5, अगस्त 31, 1985 (153 दिन)	1	153
55.	01/85-86/02	मालद्वीप के अधिकारियों के लिए शिक्षा मानव शक्ति सांख्यिकी पर संलग्न कार्यक्रम	अप्रैल 23 जून 16, 1985 (55 दिन)	1	55
56.	08/85-86/02	यू एस ई एफ आई के सहयोग से संयुक्त राज्य अमरीका के सामाजिक अध्ययन के पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यक्रम परामर्शदों के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति पर कार्यशाला	जुलाई 8-19 तथा अगस्त 8-19 1985 (32 दिन)	16	512

नीपा के कार्यक्रमों में विदेशी भागीदारी 1985-86

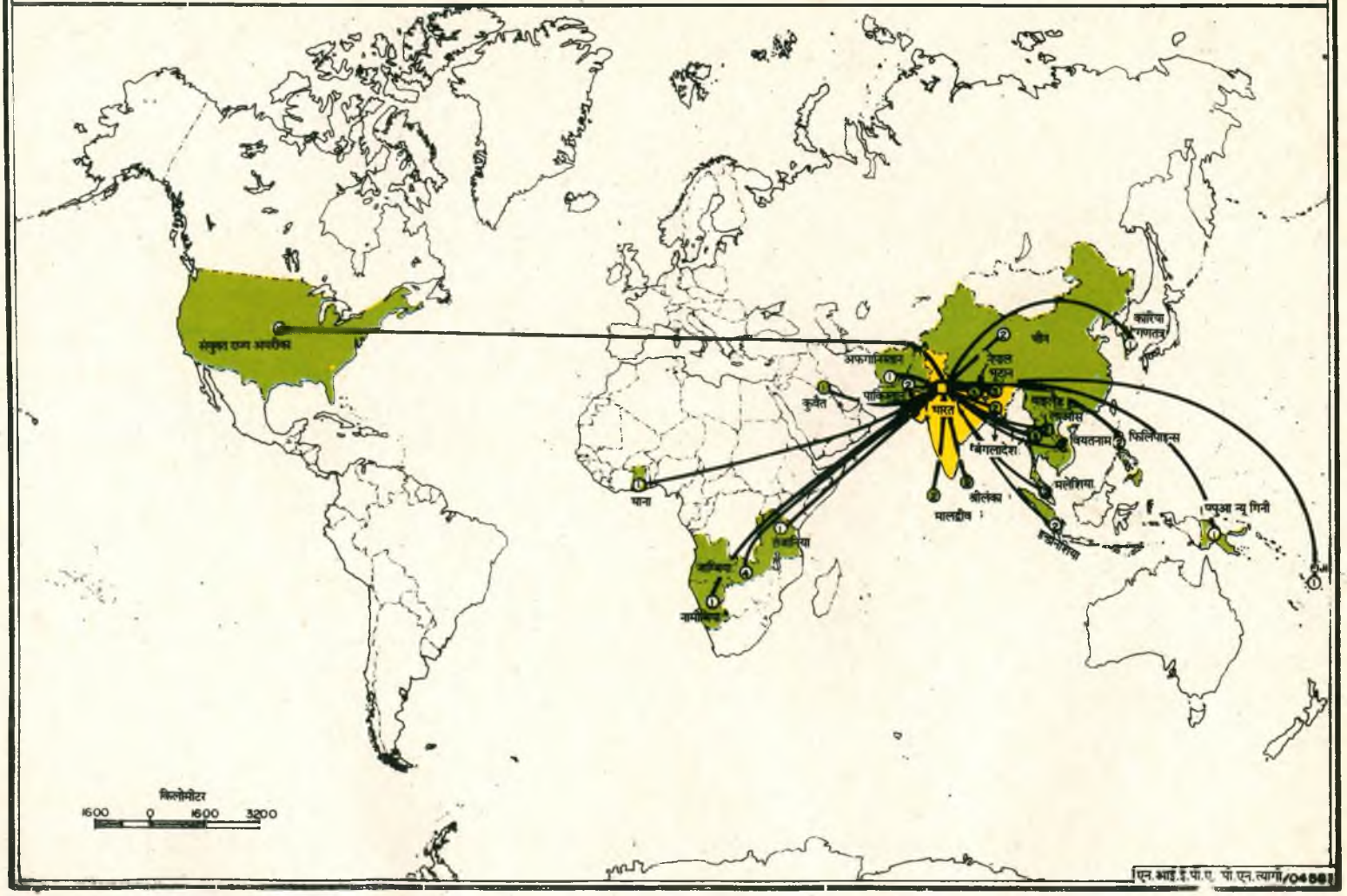

1	2	3	4	6	5
57.	08/85-86/03	शैक्षिक योजना और प्रशासन में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा	फरवरी 20 अगस्त 19 1986 (40 दिन)	10	400
			654	41	2638

व्यापक भागीदारी

कार्यक्रमों के उद्देश्य, एककवार सूची तथा अन्य ब्यौरे अनुबंध एक में दिए गए हैं ।

सारणी 1.2 कार्यक्रमों के वर्गीकरण के अनुसार संक्षेप, कार्यक्रम दिन तथा कार्यक्रम व्यक्ति दिवस

वर्गीकरण	भाग लेने वालों की संख्या	कार्यक्रम दिवस	कार्यक्रम व्यक्ति दिवस
1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (6 कार्यक्रम)	213	31	931
2. स्कूल शिक्षा की योजना तथा प्रशासन (8 कार्यक्रम)	178	438	11424
3. प्रौढ़ तथा गैर औपचारिक शिक्षा की योजना तथा प्रशासन (5 दिन)	104	30	649
4. आदिवासी के कल्याण हेतु शैक्षिक विकास (बे कार्यक्रम)	185	27	1385
5. तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध (5 कार्यक्रम)	54	27	361
6. उच्चतर शिक्षा की योजना तथा प्रशासन (8 कार्यक्रम)	182	83	1991
7. शैक्षिक प्रबंध (6 कार्यक्रम)	245	30	1225
8 शैक्षिक वित्त का प्रबन्ध (2 कार्यक्रम)	52	17	393
9. शैक्षिक प्रौद्योगिकी (8 कार्यक्रम)	46	10	180

10. अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम	251	23	685
11. अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (3 कार्यक्रम)[1]	41	654	2638
कुल 57 कार्यक्रम	1551	1370	21862

वर्ष 1985-86 के दौरान संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों में मूलत: सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों ने भाग लिया। इस वर्ष के दौरान राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से 1,354 व्यक्तियों ने भाग लिया जब कि पूर्ववर्ती वर्ष में भागादारों की कुल संख्या 709 थी। क्षेत्रानुसार भागीदारी इस प्रकार थी :

सारणी : 1.3 क्षेत्रवार भागीदारी

उत्तरी क्षेत्र	647
पश्चिमी क्षेत्र	397
पूर्वी क्षेत्र	168
दक्षिणी क्षेत्र	142
कुल	1,354

राज्यों में सें अधिकतम भागीदारी हरियाणा (338), तत्पश्चात् क्रमश: मध्यप्रदेश (210), महाराष्ट्र (94) तथा उत्तर प्रदेश (85) की थी। यह कहा जा सकता है कि संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की सबसे अधिक संख्या 491 थी जो राज्यों की कुल भागीदारी का 37 प्रतिशत है और भाग लेने वाले सभी व्यक्ति शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 9 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के अलावा दूसरी संस्थाओं से भी 132 लोगों ने इसमें भाग लिया जैसे भारत सरकार के अधिकारी तथा राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाओं जैसे एन सी ई आर टी, योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय आदि। 23 देशों के 65 व्यक्तियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया। देश के अनुसार उनका विवरण नीचे दिया गया है :

सारणी 1.4 : देश के अनुसार भागीदारी

देश का नाम	भाग लेने वालों की संख्या
अफगानिस्तान	1
बंगलादेश	2
भूटान	5
चीन	2
फीजी	1
घाना	1

1. इसके अतिरिक्त रिपोर्टाधीन अवधि में तीन अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को पूरा किया गया।

इंडोनेशिया	2
कुवेत	1
लाओस	2
मलेशिया	2
मालद्वीप	2
नामिबिया	1
नेपाल	3
पाकिस्तान	2
पपुआ एण्ड न्यू गिनी	1
फिलिपाइंस	2
कोरिया गणराज्य	1
श्रीलंका	8
तन्जानिया	1
थाईलैंड	3
संयुक्त राज्य अमेरिका	16
वियतनाम	2
जाम्बिया	4
कुल	65

वर्ष के दौरान भागीदारों का स्तर इस प्रकार है :

सारणी 1.5 :

स्कूल प्रधानाचार्य	305
जिला शिक्षा अधिकारी	92
विद्यालय के अन्य कार्मिक	271
प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	56
कालेज के प्रधानाचार्य	222
विश्वविद्यालय के अन्य कार्मिक	134
विदेशी भागीदार	65
अन्य	406
कुल	1,551

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नांकित दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए गए :

(क) भारत के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम; और

(ब) अन्य देशों के अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अन्तर्राष्ट्रीय डिप्लोमा।

जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम

वर्ष 1985-86 के दौरान संस्थान ने जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए दो भर्ती पूर्व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जबकि पूर्ववर्ती तीन वर्षों में 1982-83 तक प्रत्येक वर्ष एक-एक ही कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। पिछले तीन वर्षों में तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों से 82 अधिकारियों ने भाग लिया जबकि रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आयोजित दो डिप्लोमा कार्यक्रमों में 19 राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों से 55 अधिकारियों ने भाग लिया। वर्ष के दौरान आयोजित चौथे तथा पांचवें डिप्लोमा कार्यक्रमों में भाग लेने वालों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

सारणी 1.6 : जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में राज्यवार भागीदारी

राज्य	चौथा डिप्लोमा	पांचवां डिप्लोमा	कुल
1. आंध्र प्रदेश	—	1	1
2. गुजरात	—	2	2
3. हरियाणा	—	1	1
4. जम्मू और कश्मीर	—	1	1
5. कर्नाटक	—	3	3
6. केरल	3	1	4
7. मध्य प्रदेश	—	5	5
8. महाराष्ट्र	3	3	6
9. मणिपुर	1	—	1
10. मेघालय	5	—	5
11. उड़ीसा	—	3	3
12. पंजाब	—	1	1
13. राजस्थान	2	2	4
14. तमिलनाडू	—	1	1
15. त्रिपुरा	1	1	2
16. उत्तर प्रदेश	3	2	5
17. पश्चिमी बंगाल	1	2	3
18. दिल्ली	1	3	4
19. मिजोराम	—	3	3
कुल योग	20	35	55

डिप्लोमा पाठ्यक्रम के तीन चरण थे —

(अ) संस्थान में 15 गण्यता अंकों (क्रेडिटों) वाला तीन माह का गहन पाठ्यक्रम कार्य,

(ब) प्रशिक्षणार्थियों (जिला शिक्षा अधिकारियों) के जिले में तीन महीने का पर्यवेक्षिक परियोजना कार्य, तथा

(स) प्रशिक्षणार्थियों द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्टों पर चार दिन की मौखिक परीक्षा

शैक्षिक योजना, कार्य योजना, भाग लेने वालों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र को विशेष महत्व देते हुए सिंडीकेट कार्य आदि पर बल देने के लिए चौथे तथा पांचवें डिप्लोमा कार्यक्रमों की विषयवस्तु तथा खाके को पिछले डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भाग लेने वालों के अनुभवों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के प्रकाश में फिर से डिजाइन किया गया। संस्थागत योजना, विद्यालय मान चित्रण, शिक्षा की गुणवता, संस्थागत नेतृत्व, संकट का समाधान आदि विषय भी इस डिप्लोमा कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए।

चौथे डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले 20 व्यक्तियों ने पाठ्यक्रम को अत्यंत सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और संस्थान ने उन्हें डिप्लोमा उपाधि से सम्मानित किया। पांचवे डिप्लोमा कार्यक्रम के 35 भागीदारों ने भी डिप्लोमा पाठ्यक्रम को पूरा किया। उन्हें भी अपनी परियोजना रिपोर्टों को प्रस्तुत करने तथा उनके मूल्यांकन के पश्चात डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे।

शैक्षिक योजना और प्रशासन में अन्तर्राष्ट्रीय डिप्लोमा

तीसरे विश्व के देशों की मांगों को पूरा करने के लिए जनवरी 1985 से शैक्षिक योजना और प्रशासन में एक अन्तर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आई डी ई पी ए) शुरू किया गया। यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम जुलाई, 1985 में समाप्त हुआ।

शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आई डी ई पी ए) फरवरी 20, 1986 को प्रारंभ किया गया और अगस्त 1986 को प्रारंभ किया गया और अगस्त 1986 तक चलता रहा।

सारणी 1.7 : पहले तथा दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भाग लेने वालों की देशवार सूची नीचे दी गई है :

देश का नाम	पहला अन्तर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम	दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम	कुल
1. अफगानिस्तान	1	—	1
2. बंगलादेश	—	1	1
3. भूटान	3	—	3
4. फीजी	—	1	1
5. घाना	—	1	1
6. कुवैत	1	—	1

1	2	3	4
7. मारीशस	1	—	1
8. नामिबिया	—	1	1
9. श्रीलंका	6	—	6
10. तन्जानिया	—	2	2
11. जांबिया	—	4	4
कुल	12	10	22

डिप्लोमा पाठ्यक्रम के दो चरण थे—

(अ) संस्थान में तीन महीने का गहन पाठ्यचर्या कार्य, तथा।

(ब) जॉब पर तीन महीने का पर्यवेक्षित परियोजना कार्य।

पाठ्यक्रम का खाका काफी सोच बिचार करके तैयार किया गया था। पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया (i) मूल पाठ्यक्रम (ii) विशेषज्ञता का पाठ्यक्रम। मूल पाठ्यक्रम में शैक्षिक योजना और प्रशासन की आधारभूत संकल्पनाओं तथा तकनीकों को रखा गया था, विशेषज्ञता वाले भाग में भागीदारों द्वारा चुने गए किसी विशेष क्षेत्र में किए जाने वाले उन्नत कार्य की रखा गया था। इस पाठ्यक्रम में जो विभिन्न विषय लिए गए वे इस प्रकार थे : शैक्षिक योजना का मात्रात्मक पक्ष, परियोजना का नियोजन, परिवीक्षण तथा मूल्यांकन संगठनात्मक व्यवहार, कार्मिक प्रबन्ध, वित्तीय प्रबन्ध, कार्यालय प्रबन्ध इत्यादि। पाठ्क्रम के शैक्षिक विषय के पूरक के रूप में विभिन्न दौरों का भी आयोजन किया गया। इन दौरों में स्कूलों का दौरा, दिल्ली की बड़ी संस्थाओं का दौरा तथा बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल के राज्य सम्मिलित हैं। इन क्षेत्र भ्रमणों का आयोजन भागीदारों को भारतीय परिस्थितियों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करवाने के लिए किया गया था जिससे वे अपने देश की समस्याओं के समाधान के लिए प्रासंगिक निष्कर्ष प्राप्त कर सकें।

भागीदारों की पाठ्यक्रम फीस तथा अन्य व्यय यू एन डी पी, कामनवेल्थ फंड फार टेकनिकल क्वापरेशन (सी एफ टी सी) तथा अन्य विदेशी एजेंसियों ने वहन किए।

प्राथमिकता के क्षेत्र

इस पाठ्यक्रम में शिक्षा की चुनौती में उल्लिखित प्राथमिकता के क्षेत्र जैसे माइक्रो (सूक्ष्म) स्तरीय योजना, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, प्रौढ़ तथा गैर औपचारिक शिक्षा, शैक्षिक योजना में कम्प्यूटर का प्रयोग, व्यावसायीकरण का प्रबंध, शैक्षिक योजना तथा प्रबंध में समानता, आदिजाति क्षेत्रों में संस्थागत योजना, स्वायत्तता प्राप्त संस्थाओं का नियोजन तथा प्रबंध शैक्षिक प्रौद्योगिकी की अनुप्रयुक्तता तथा परिवर्तन के प्रबंध पर विशेष बल दिया गया था।

+2. स्तर पर व्यावसायीकरण के कार्यान्वयन की कुशल नीतियों के विकास पर कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित विषय सम्मिलित किए गए—व्यावसायी सर्वेक्षण, प्रशासन का संरचनात्मक पुनर्गठन, अकादमिक संगठन, नियमों तथा विनियमों में परिवर्तन, विभिन्न संरचनाओं का समाकलन-समस्तरीय विषमस्तरीय गतिशीलता, अनुबंधन तथा समन्वय।

शैक्षिक परिवर्तन के प्रबन्ध पर कार्यशाला में केस अध्ययनों तथा प्रभावी प्रबंध माडलों के विकास को केन्द्र बिन्दु बनाया गया।

आदि जाति क्षेत्रों में स्कूलों के बेहतर पर्यवेक्षण, आश्रम स्कूलों के नियोजन तथा प्रबंध आवि विषयों पर विचार विमर्श शिक्षा में समानता (निष्पक्षता) के अंतर्गत किया गया।

संसाधनों के प्रबंध पर कार्यशाला में संसाधनों के इष्टतम उपयोग की कार्य प्रणालियों पर बल दिया गया।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तथा अन्य विभागों के गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के बीच परस्पर निर्भरता का प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक नया क्षेत्र था।

उत्तर प्रदेश में संस्थागत नियोजन तथा मूल्यांकन में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

कार्य के नए क्षेत्र

उच्चतर शिक्षा के नियोजन तथा विकास के लिए आधार सामग्री प्रक्रमण (डेसा प्रोसेसिंग), विश्वविद्यालय रजिस्ट्रारों के प्रबंध की आधुनिक प्रणालियों में प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम, बिश्वविद्यालय प्रबंध पद्धति में कम्प्यूटरों के प्रयोग आदि नए क्षेत्र थे जिन पर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान द्वारा विचार-विमर्श किया गया।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन के प्रबंध पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में समुदाय के सहयोग, भागीदारी तथा अन्य विभागों से अनुबंधन की सहायता से क्षेत्र स्तर पर परियोजनाओं के प्रभावी कार्वान्वयन के लिए उचित कुशलकार्य नीतियों मार्गदर्शी रूपरेखाओं का निर्माण किया गया। पुनहाना में आयोजित क्रिया अनुसंधान कार्यक्रम में अपनायी गई कुशल कार्य नीतियों तथा अनुभवों का व्यापक पैमाने पर समुदाय की सहभागिता की कुशल कार्य नीति के निर्माण में प्रयोग किया।

स्वायत्त संस्थाओं में अध्ययन दौरों के दौरान स्वायत संस्थाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं तथा उनकी वृद्धि की मंद गति के कारणों पर भी विचार-विमर्श किया गया है। इस विषय का भी अध्ययन किया गया कि संस्थाओं को जिस प्रयोजन के लिए स्वायत्ता प्रदान की गई थी वह पूरा हुआ अथवा नहीं। इसके साथ-साथ इस प्रयोग की प्रभाविता का भी अध्ययन किया गया।

नीपा में पुनहाना के कार्य अनुसंधान क्षेत्रों की महिला कार्यकर्ताओं के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से नीपा में औपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा के बीच समन्वित नियोजन तथा अनुपूरकता पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

वर्ष 2000 में शिक्षा की अपेक्षाओं का पूर्वानुमान तथा जनांकिकीय विकास और अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों से इसकी संबद्धता तथा दीर्घकालीन योजना के मामले जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रबंध पर कार्यशाला में शिक्षा के उन क्षेत्रों की पहचान की गई जिनमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर भी भाग लेने वालों द्वारा परिचर्चा की गई।

शैक्षिक उत्पादकता तथा उत्पादक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विकसित की गई नई संकल्पनायें थीं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया। शैक्षिक परिवर्तन के प्रबंध पर राष्ट्रीय कार्यशाला में शैक्षिक परिवर्तन को नियमित तथा त्वरित करने की विधियों पर भी परिचर्चा की गई।

चालू कार्यक्रम

जिला शिक्षा अधिकारियों के डिप्लोमा कार्यक्रमों तथा शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रमों के अतिरिक्त इस वर्ष के दौरान कुछ ऐसे कार्यक्रम भी चलाये गए जो अब भी जारी है। उनके विषय में नीचे दिया गया है।

(क) केंद्रीय विद्यालय संगठन के वरिष्ठ प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ख) विश्वविद्यालय वित्तों के प्रबंध में दो अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एक कार्यक्रम एक सप्ताह की अवधि का और दूसरा 10 दिन का था।

(ग) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 'शिक्षा में समानता' विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आदिजाति शिक्षा से संबंधित शैक्षिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

(घ) प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन के प्रबंध पर राष्ट्रीय कार्यशाला : ये कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के सहयोग से आयोजित किए गए।

(ङ) कालेज के अध्यापकों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम। तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक महिला कालेजों के प्रधानाचार्यों के लिए तथा अन्य दो कालेजों के प्रधानाचार्यों के लिए।

(च) 'कालेजों के विज्ञान विभागों के अध्यक्षों के लिए विज्ञान शिक्षा के नियोजन तथा प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम' इस प्रयोजन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(छ) इस वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए संस्थागत नियोजन तथा मूल्यांकन में दो कार्यशालायें आयोजित की गईं।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस, भारत के संयुक्त राज्य अमरीकी न्यास, नई दिल्ली, यूनेस्को तथा प्रशांत क्षेत्र के तथा तीसरी दुनिया के संगठनों के अनुरोध पर संस्थान कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करने के अलावा संयुक्त राज्य अमरीका के समाज विज्ञान के पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यक्रम परामर्शदों के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति पर एक कार्यशाला चलाई गई। इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमरीका के 16 व्यक्तियों ने भाग लिया।

सामग्री की तैयारी और क्षेत्र-दौरे

प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिवार्य संबद्ध सामग्रियों के निर्माण के लिए पहले ही कदम उठा लिए गए थे। प्रोग्राम में भी अध्ययन रिपोर्टों, दस्तावेजों, केस अध्ययनों तथा कार्य योजनाओं के रूप में सामग्री का निर्माण किया गया। डिप्लोमा कार्यक्रमों में भाग लेने वालों द्वारा डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की गई अनुसंधान परियोजनाओं की रिपोर्ट भी उपयोगी सामग्री मानी गई।

भाग लेने वालों को क्षेत्र दौरों पर उचित स्थानों पर ले जाया गया। इन दौरों में विभिन्न संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्कूलों और कालेज, गैर-औपचारिक शिक्षा केंद्र तथा नवाचारी परियोजनायें भी सम्मिलित हैं। इन सबसे पठन सामग्रियों के तैयारी करने के लिए आधार-सामग्री संकलन में सहायता प्राप्त हुई। कुछ सामग्रियां तथा रिपोर्ट हिन्दी में भी तैयार की गईं।

अंतर-विषयी उपागम

लगभग प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक कार्य दल बनाया गया जिसमें विभिन्न एकक के संकाय सदस्य थे और कुछ मामलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यापक संकल्पना देने के लिए बाहर से भी विशिष्ट विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर-विषयी प्रकार के थे। यद्यपि कार्यक्रम के प्रबंध का दायित्व अकादमिक इकाइयों में से एक इकाई के जिम्मे था, अन्य अकादमिक इकाइयों ने भी संसाधन व्यक्ति प्राप्त करवाने तथा कार्यक्रमों के संचालन तथा अन्य अकादमिक कार्यों में काफी योगदान किया। प्रयोगात्मक कार्य, सिंडिकेट कार्य, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा कम्पयूटर की अनुप्रयुक्तता प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल थे। इसमें फिल्मों, विडियो तथा ओवर-हेड प्राजेक्टर का प्रयोग भी शामिल हैं। विभिन्न कार्यशालाओं, गोष्ठियों तथा कार्यक्रमों में अनुसंधान परिणामों का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया गया।

मूल्यांकन

प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्यतः स्वतः मूल्यांकन का तत्व निहित होता है। दीर्घ अवधि के कार्यक्रमों जैसे जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए छह महीने के डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में कार्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार भाग लेने वालों द्वारा प्रत्येक माह पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है। कार्यक्रम के अन्त में होने वाले समाकलित मूल्यांकन के अतिरिक्त कार्यक्रम के प्रत्येक माड्यूल का मूल्यांकन किया जाता है। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भाग लेने वालों द्वारा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किए जाने के अलावा भाग लेने वालों का भी मूल्यांकन नियत कार्यों, परीक्षणों, समूह तथा वैयक्तिक कार्य, सत्रपत्रों, भागीदारों की संगोष्ठियों तथा सिंडिकेट कार्य के रूप में किया जाता है। सामान्यतः मूल्यांकन पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है तथा भाग लेने वालों की प्रतिक्रियाओं के प्रकाश में पाठयक्रम-संरचना में पुनः समायोजन किया जाता है। शिक्षण कार्यक्रमों को अद्यतन बनाने तथा उनकी पुनः संरचना करने में बनी बनाई प्रश्नावलियों के उत्तरों तथा भाग लेने वालों द्वारा कार्यक्रम के मूल्यांकन का भी उपयोग किया गया।

कार्यक्रमों के प्रसांगिकता की गुणता को बनाये रखने और प्रशिक्षण कुशल नीतियों का अधिकाधिक विकास करने तथा नीपा द्वारा चलाये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भी एक अध्ययन किया गया। पूर्ववर्ती वर्षा के दौरान आसाम के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों की

एक बड़ी संख्या को प्रशिक्षित किया गया था। इसीलिए उसका प्रभाव जानने के लिए आसाम में एक अध्ययन का संचालन किया गया। अध्ययन रिपोर्ट में यह देखा गया कि संस्थागत निर्माण के व्यापक संदर्भ में प्रशिक्षण मात्र एक भाग है, अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कुल पद्धति उपागम अनिवार्य है। शैक्षिक कार्मिकों में परिवर्तन के प्रति अधिकाधिक प्रतिरोध दिखाई देता है। प्रतिरोधों अथवा बाधाओं के बावजूद भी प्रशिक्षण वास्तविक कार्यकारी परिस्थितियों में अति उपयोगी सिद्ध हुआ। कौशलों के निर्माण में अभ्यासों का भाग लेने वालों पर गहन प्रभाव पड़ा। यद्यपि व्यक्ति द्वारा कौशलों में सुधार किए जाने की सफलता संस्थागत परिवेश पर निर्भर करती है, फिर भी भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात स्थिति में सुधार लाने का पूरा प्रयत्न किया है। उन्होंने संस्थागत योजना का निर्माण किया तथा परिवीक्षण तकनीकों को भी अपनाया है। विविध प्रकार की समस्याओं के बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुआ।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No .... D - 9366
Date 5-12-96

भाग-दो

अनुसंधान और अध्ययन

संस्थान की अनुसंधान संबंधी गतिविधियों की मुख्य दिशा ज्ञानार्जन के उद्देश्य से शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में सूक्ष्म तथा वृहत् दोनों ही स्तरों पर आनुभाविक स्थितियों की खोज करना है। इनका लक्ष्य ज्ञान प्रदान करना, सार्थक आधार सामग्री उपलब्ध करना, नीति निर्धारण के मामलों के लिए प्रतिपुष्टि प्राप्त करना तथा क्षेत्र की समस्याओं का संभाव्य समाधान प्राप्त करना है। अनुसंधान-अध्ययनों के परिणामों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निरंतर उर्वरता प्राप्त होती रहती हैं। संस्थान की विशेषज्ञ समिति, राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक सरकारें, आई सी एस एस आर जैसे अकादमिक और अनुसंधान संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इन अध्ययनों के लिए विषय वस्तु की पहचान करते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुसंधान और अध्ययन पर सरकारी अनुदान के 2.97 लाख रुपए व्यय हुए। संस्थान ने अनुदान निधिक अनुसंधान कार्यों के लिए 8.60 लाख रुपए अन्य स्रोतों से एकत्र किए। अनुसंधान तथा अध्ययन पर सरकारी अनुदान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि को मिलाकर कुल व्यय 11.57 लाख रुपए तक पहुंच गया। वर्ष के दौरान 20 अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए और 18 अध्ययन चल रहे हैं। दो प्रासंगिक पत्र भी प्रकाशित किए गए।

इस वर्ष के दौरान पूरे किए गए अध्ययनों में मुख्य हैं : स्कूलों में अध्यापक छात्र का इष्टतम अनुपात, भारत में शैक्षिक नीति तथा नियोजन का अध्ययन—योजना आयोग की भूमिका : वर्तमान परिस्थिति तथा भविष्य परिप्रेक्ष्य; विकास के कुछ आयामों पर शैक्षिक स्वरों का प्रभाव-ग्रामीण गृह-परिवेश का अध्ययन; नई शिक्षा नीति के निर्माण में निवेश के रूप में विविध दस्तावेजों/संचारों/रिपोर्टों के विषयवस्तु विश्लेषण पर आधारित श्रृंखलाबद्ध 12 अध्ययन तथा भारत में सन् 2000 में शिक्षा : एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य' परियोजना के अन्तर्गत चार अध्ययन; भारत में प्राथमिक शिक्षा तथा भविष्य के विकास के लिए शैक्षिक योजना की समस्यायें तथा विकल्प। यह अध्ययन अभी चल रहा हैं।

शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नौ राज्यों में प्रारंभिक स्वर पर गैर औपचारिक शिक्षा के मूल्यांकन-अध्ययनों का, जो इस समय चल रहे हैं, विशेष उल्लेख किया जा सकता है। ये राज्य हैं : आंध्र प्रदेश असम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। ऐसी आशा की जाती है कि इस अध्ययन के निष्कर्ष योजना को संक्रियात्मक गति देने में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदा न करेंगे। इसका गैर औपचारिक शिक्षा की नीति निर्धारण तथा कार्यक्रमों पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा। ये अध्ययन समाप्ति पर हैं।

मेवात क्षेत्र के पुनहाना प्रखण्ड के बीस गांवों में चलाई जाने वाली एक क्रिया अनुसंधान परियोजना

का भी यहां विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। मेवात शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हरियाणा के कुछ चुने हुए कालेजों में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कार्य करने तथा विकास से संबंधित समस्याओं के विश्लेषण के लिए एक अन्य अनुसंधान परियोजना हाथ में ली गई है।

कालेजों के मुख्याध्यापकों के भूमिका-निष्पादन, इंजीनियरिंग कालेजों में कार्मिक संरचना तथा तालिका नियंत्रण प्रबंध पर चल रहे अध्ययन तथा शैक्षिक विकास पर मोनोग्राफ समाप्त होने वाले हैं। 'भारतीय मॉडल की दिशा में परिवर्तन का प्रबंध' विषय पर भी एक अध्ययन प्रारंभ किया गया। भारत में साक्षरता का अध्ययन एक देश-कालबद्ध विश्लेषण (1901 से 81) तथा उच्चतर शिक्षा में संसाधनों के प्रभावी उपयोग से संबंधित अध्ययनों पर स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

पूरे किए गए अध्ययन

1. स्कूलों में अध्यापक-छात्र के इष्टतम अनुपात का अध्ययन (जी/आर पी एस/15)

अनुसंधान दल में निम्नलिखित विशेषज्ञ सम्मिलित थे : डा० आर० पी० सिंहल, परियोजना निदेशक, श्री वी० के० पांडा तथा सुश्री रश्मी दीवान परियोजना सहायक।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य देश में राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित अध्यापक-छात्र अनुपात के मानकों तथा स्कूल-शिक्षा में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों में वस्तुतः प्राप्त मानकों के संबंध में आनुभविक स्थिति का पता लगाना हैं।

इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं : राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित अध्यापक-छात्र अनुपातों में व्यापक भिन्नतायें (1.20 से 1.55 तक) हैं। अध्ययन से यह प्रकट हुआ है कि निर्धारित मानकों तथा वस्तु स्थिति में व्यापक भिन्नता हैं। स्कूलों के आकार, कक्षा आकार तथा अध्यापक के कार्य भार में भी भिन्नतायें हैं। बहुत बड़ी संख्या में अध्यापक एक सप्ताह में निर्धारित निम्नतम घंटों तक भी अध्यापन कार्य नहीं करते। आधे से अधिक अध्यापक स्कूल वर्ष में 220 दिन से भी कम अध्यापन कार्य करते हैं। प्राथमिक स्कूलों के आधे से अधिक अध्यापक सार्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा के कार्य में कोई रुचि नहीं रखते। आदि जातियों के बच्चों के स्कूलों में 10 में से 9 स्कूल जाने वाले आयु के बच्चों की वार्षिक गणना नहीं करते। स्कूलों का बहुत बड़ा प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों, लड़कियों तथा पिछड़े हुए समुदायों को दिए जाने वाले विविध प्रोत्साहनों का भी पूरा उपयोग नहीं करते। अध्यापकों, विद्यार्थी सेवाओं तथा विस्तार कार्य का पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन सीमित स्तर तक ही होता है। 38 प्रतिशत स्कूलों में पांचवीं कक्षा में 25 से भी कम छात्र होते हैं। परन्तु ऐसे भी स्कूल है जिनमें प्रति कक्षा 50 छात्र से भी अधिक होते हैं। इस अध्ययन में विभिन्न स्तरों के लिए पूरे देश में नमूना स्कूलों में वास्तविक अध्यापक-छात्र अनुपात इस प्रकार है :

	ग्रामीण	नगरीय	कुल
प्राथमिक अवस्था	1:37	1:37	1:36
माध्यमिक अवस्था	1:29	1:28	1:28.5
उच्च विद्यालय अवस्था	1:16	1:34	1:24

कुछ मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं : राष्ट्रीय मानकों का होना अपेक्षित हैं जिससे विभिन्न राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश उनका पालन कर सकें। मानकों में छूट उन्हीं को दी जा सकती है जो लाभ वंचित तथा कम संख्या वाले और पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। अध्यापकों की संख्या की मंजूरी नामांकन के आधार पर न होकर वर्ष में तीन छात्रों की औसत उपस्थिति के आधार पर होनी चाहिए। स्कूलों के लिए वर्ष में निम्नतम 220 कार्य दिवस होने चाहिए। जहां तक सम्भव हो सके देश में विभिन्न कोटियों के अध्यापकों के लिए कार्य-भार के मानक समान होने चाहिए।

2. भारत में शैक्षिक नीति तथा योजना का अध्ययन—योजना आयोग की भूमिका—वर्तमान स्वरूप तथा भावी संभावनायें (जी/एस एन एस/17)

अनुसंधान दल में निम्न विशेषज्ञ सम्मिलित थे। डा० एस० एन० सराफ, परियोजना निदेशक, सुश्री अनिता तापलू, परियोजना सहायक।

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं : इस विषय की जांच करना कि भारत में स्वतंत्रतापूर्व तथा स्वातन्त्रोत्तर सम्पूर्ण राष्ट्रीय विकास ने राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों तथा नियोजन के विकास को किस प्रकार प्रभावित किया है, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक योजना के निर्माण में निहित प्रक्रियाओं तथा प्रविधियों तथा अन्य विकासात्मक क्षेत्रों और विभिन्न शिक्षा आयोगों तथा समितियों के योगदान का पता लगाना तथा नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में योजना आयोग, शिक्षा मंत्रालय तथा राज्य सरकारों की भूमिका की जांच करना। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

नियोजन को सुदृढ़ करने, प्रबंध तथा नीति निर्माण के लिए भारतीय शैक्षिक सेवा के व्यावसायिक कैडर का सृजन अनिवार्य हैं। सह-पाठ्यचर्या वाली एक राष्ट्रीय शैक्षिक पद्धति को संगठत किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक एकीकरण का प्रसार करने के लिए गति निर्धारक संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय कालेजों की भूमिका को पुन: परिभाषित करना आवश्यक है जिससे वे शैक्षिक नवाचारों की खोज करने में प्रभावी उपकरण सिद्ध हो सके तथा व्यवहार उपयोगी कार्यक्रमों पर प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला का कार्य कर सकें। कडरों के व्यावसायीकरण की दिशा में एक उपाय के रूप में राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी की तरह ही नीपा तथा एत सी आरटी द्वारा लघुकालीन भर्ती कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इन कार्यक्रमों में मुख्य स्तरीय कार्मिकों को शैक्षिक नियोजन की संकल्पनाओं तथा तकनीकों, वित्तीयन, प्रबंध, मूल्यांकन, शैक्षिक नवाचारी परियोजनाओं आदि से परिचय करवाया जा सकता है।

शिक्षा को अन्य विकासात्मक एजेंसियों से संबद्ध किया जाना चाहिए। वर्तमान स्थित अनुरक्षण संबंधी तथा नियंत्रणोन्मुख रचना को सुदृढ़ किया जाना चाहिए जिससे यह विकासोन्मुख संगठन के रूप में कार्य कर सके। एकीकृत सूक्ष्म स्तरीय योजना के लिए प्रशिक्षण प्रशासनिक यंत्र का अनिवार्य अंग होना चाहिए। जिले को शैक्षिक नियोजन, प्रबंध मूल्यांकन तथा वित्त का एक एकक माना जाना चाहिए। शैक्षिक विकास कार्यक्रम को सह-परियोजना पर आधारित मॉडल के रूप में क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

3. विकास के कुछ आयामों पर शैक्षिक स्तर का प्रभाव—ग्रामीण परिवारों का अध्ययन (की/एम आर जैड/16)

अनुसंधान दल में निम्नलिखित सम्मिलित थे : प्रो० मूनिस रज़ा, परियोजना निदेशक; डा० एच० रामचन्द्रन, परियोजना निदेशक तथा सुश्री शारदा मानवीकर, परियोजना सहयोगी :

अध्ययन में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया गया था : क्या शैक्षिक स्तर नई प्रौद्योगिकी के अपनाने को प्रभावित करता है और यदि करता है तो क्या शिक्षा का कोई क्रांतिक स्तर है जो अपनाने को प्रभावित करता है। क्या शैक्षिक स्तर आर्थिक क्रियाकलाप के विविधीकरण को प्रभावित करता है ? बाजार, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं के संदर्भ में शैक्षिक स्तरों तथा परिवारों के अनुबंधन में किस प्रकार का संबंध है ? क्या शैक्षिक स्तर अन्य विकासात्मक पक्षों के उपयोग तथा उनको समाहित करने की क्षमता रखता है ? क्या शैक्षिक स्तर आने वाली संततियों को प्रभावित करता है ?

इस अध्ययन के परिणाम कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले के यादृच्छिक रूप में चुने हुए 245 ग्रामों के 30,000 ग्रामीण परिवारों से एकत्रित किए गए आंकड़ों पर आधारित है। ग्रामीण परिवारों के विभिन्न वर्गों में शिक्षा का वितरण, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार, कृषि के आधुनिकीकरण में शिक्षा की भूमिका, जनांकिकीय प्रवृत्ति तथा जीवन स्तर का भी अध्ययत किया गया।

4. शिक्षा का बाह्य वित्तीयन (03/ई एफ एन/03)

अनुसंधान दल में निम्नलिखित सम्मिलित थे : डा० सी० बी० पद्मनाभन, परियोजना निदेशक तथा डा० जे० बी० जी० तिलक, परियोजना सहयोगी।

मुख्य परिणाम इस प्रकार हैं : शिक्षा के निम्नतर स्तरों की तुलना में उच्चतर शिक्षा को अधिकांशत: अधिक अनुदान दिया जाता रहा है, अनुदान अधिकांशत: तकनीकी सहायता, निर्माण तथा उपस्करों की मदों पर ही केन्द्रित है, निरपेक्ष रूप में प्रत्येक स्रोत के अंशदान में महत्त्वपूर्ण रूप में संवृद्धि हुई है परन्तु शिक्षा के निजी अलाभकारी स्रोतों के सापेक्ष अंशदान में बहुत कमी हुई,है। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्रोतों के अंशदान में वृद्धि हुई है, द्विपक्षीय अनुदान तकनीकी सहायता पर केन्द्रित है तथा बहुपक्षीय अनुदान जैसे विकास बैंकों से आने वाला अनुदान भौतिक सुविधाओं तथा उपस्करों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, निजी अलाभकारी एजेंसियों का ध्यान संस्थागत विकास, शैक्षिक नवाचारों तथा सुधारों पर केन्द्रित है। अनुदान की एक अन्य विशेषता यह है कि इसका गलत प्रयोग किया गया है जैसा कि अनुदान के भौगोलिक वितरण से पता चलता है। भारत में विविध स्रोतों से बाह्य संसाधन से अनुदान प्राप्त होता रहा है। तथापि इनका संकेंद्रण मुख्यत: सम्मानित संस्थाओं जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा चुने हुए कुछ विश्वविद्यालयों, जहां उच्च स्तरीय अध्ययन केन्द्रों का विकास हुआ है, पर ही है।

नई शिक्षा नीति के निर्माण में निवेश के रूप में विभिन्न दस्तावेजों/संचारों/रिपोर्टों के विषयवस्तु विश्लेषण पर आधारित अध्ययन (04/इ पी ओ/12.1 से 12.12 तक)

भारतीय शिक्षा की पुन: संरचना की दिशा में—नागरिक प्रत्यक्षण—खण्ड—1 से 4 (04/ई पी ओ/12.1)

भारतीय शिक्षा पद्धति की सामाजिक लेखा परीक्षा : जनवाणी संचार का एक अध्ययन (04/ई पी ओ/12 2)

भारतीय शिक्षा की पुन: संरचना की दिशा में—तकनीकी संस्थाओं का प्रत्यक्षण (04/ई पी ओ/12.3)

भारतीय शिक्षा की पुन: संरचना की दिशा में : विश्वविद्यालय में सम्बन्धित (04/ई पी ओ/12.4)

भारतीय शिक्षा की पुन: संरचना की दिशा में, : शैक्षिक संस्थाओं/निकायों के सुझाव (04/ई पी ओ/12.5

भारतीय शिक्षा की पुन: संरचना की दिशा में : शिक्षात्तर संगठनों के विचार (04/ई पी ओ/12.6)

शिक्षा के स्वैच्छिक तथा व्यावसायिक निकाय—खंड I तथा खंड II (04/ई पी ओ/12.7)

नई शिक्षा नीति पर प्रेस : प्रेस की करतनों का विश्लेषण (04/ई पी ओ/12.8)

भारतीय शिक्षा की पुन: संरचना की दिशा में : प्रेस का दृष्टिकोण (04/ई पी ओ/12.9)

नई शिक्षा नीति : उत्तर प्रदेश का एक परिपेक्ष्य (04/ई पी ओ/12।10)

भारतीय शिक्षा की पुन: संरचना की दिशा में : राज्य स्तर के विचार-विमर्श का विश्लेषण (04/ई पी ओ/12.11)

भारतीय शिक्षा की पुन: संरचना की दिशा में : राज्यों के प्रत्यक्षण (04/ई पी ओ/12.12)

इस परियोजना से निम्नलिखित व्यक्ति संबंधित थे : डा० कुसुम के० प्रेमी, डा० एस० सी० नूना, डा० ए० मैथ्यू, डा० समीया जैदी, डा० ऊषा नायर, डा० के० सुधा राव, डा० के० सुजाता, डा० ए० मंगलागिरी, सुश्री जै० जलाली, श्री एस० एस० दुदानी, श्री टी० के० डी० नायर, डा० सुषमा भागिया, श्री शब्बीर अहमद, श्री सी० मेहता, सुश्री सुनिता चुग, सुश्री जोसेफीन, सुश्री रशमी दीवान, सुश्री नलनी जुनैजा, श्री एन० डी० पी० मेनन, श्री प्रेमकृष्ण, श्री के० सी० नौटियाल, सुश्री प्रीति चुग, सुश्री पुष्पा मानस तथा श्री के० एम० त्रिपाठी।

शिक्षा की चुनौती से संबंधित नागरिकों, जनवाणी संचारों, प्रेस-करतनों, स्वैच्छिक तथा व्यावसायिक निकायों के शिक्षा विषय पर विचारों आदि से प्राप्त प्रतिक्रियायों का विश्लेषण किया गया तथा विषयवस्तु-विश्लेषण के 16 खंड तैयार किए गए। इन खंडों की नई शिक्षा नीति के निर्माण में प्रभाव के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। (इन्हें शिक्षा नीति पर होने वाली परिचर्चाओं में सहायक सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया गया)

भारतीय शिक्षा की पुन: संरचना की दिशा में नागरिकों के प्रत्यक्षण खण्ड 1-4

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा नीति के निर्माण की उद्घोषणा के प्रत्युत्तर में नागरिकों द्वारा फरवरी तथा दिसम्बर, 1985 के बीच लिखे 22 वैयक्तिक पत्र भेजे। ये पत्र भारत के विभिन्न भागों के प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा लिखे गए थे। विदेशों में बसे भारतीयों से अनेक पत्र प्राप्त हुए। इन पत्रों के आधार पर संस्थान ने 'भारतीय शिक्षा की पुन: संरचना की दिशा में : नागरिकों के प्रत्यक्षण' शीर्षक से चार खंड तैयार किए। पत्रों के 'विषयवस्तु-विश्लेषण' की विधि अपनाई गई।

पत्रों के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि शिक्षा-क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्ति विषय से अधिक संबंधित थे

और प्रति उत्तरों में उनका प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से अधिक था। इनमें स्कूलों और कालेजों के अध्यापक, विद्यार्थी तथा शैक्षिक प्रशासक सम्मिलित थे। प्रतिउत्तर देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे पहले, फिर महाराष्ट्र, तत्पश्चात दिल्ली तथा मध्य प्रदेश का स्थान था। विश्लेषण से यह भी प्रकट हुआ कि हिन्दी भाषी राज्यों से अधिक संख्या में प्रतिउत्तर प्राप्त हुए जबकि दक्षिणी राज्यों से प्रतिउत्तरों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम थी। लोग प्रारंभिक शिक्षा की समस्यायें तथा मामलों के विषय में अधिक चिंतित थे, तत्पश्चात माध्यमिक, उच्चचर माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा से। तथापि तकनीकी शिक्षा से भी संबंधित बहुत से प्रतिउत्तर प्राप्त हुए।

शिक्षा से संबंधित अनेक समस्यायें उठाई गईं। प्रतिउत्तरों के विषय विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि अधिकतर व्यक्ति शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाये जाने वाले विषयों तथा पाठ्यक्रमों के विषय में चिंतित थे। सारे देश में एक समान पाठ्यचर्या की मांग की गई और विविध प्रकार के स्कूलों में शिक्षा के स्तरों में विभिन्नताओं को कम करने पर जोर दिया गया। अधिक संख्या में व्यक्तियों ने ऐसी शिक्षा दिए जाने का सुझाव दिया जो राष्ट्रीय एकता तथा एकीकरण का प्रसार करे। इस विषय पर भी बल दिया गया कि शिक्षा को आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण तथा व्यक्तियों की प्रगति तथा खुशहाली का प्रभावी साधन बनाया जाए। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के लिए इसको केंद्रीय सूची में रखने का भी सुझाव दिया गया। पब्लिक स्कूलों की पद्धति के विरुद्ध अत्यंत रोष प्रकट किया गया।

विश्लेषण से यह पता चला कि लोग नियुक्त किए गए अध्यापकों की गुणवत्ता के विषय में चिंतित हैं। उनका विचार था कि अध्यापन व्यवसाय में उन्हीं व्यक्तियों को लिया जाए जो इसमें रुचि रखते हैं तथा उनकी नियुक्ति योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। उन्हें उच्च वेतन तथा अन्य लाभ-प्रोत्साहन के रूप में दिए जाने चाहिए। त्रिभाषा सूत्र के उचित कार्यान्वयन तथा पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा पद्धति को अपनाने के विषय में मतैक्य था। वर्तमान शिक्षा पद्धति में सुधार करने की मांग की गई थी और यह एक सामान्य भावना थी कि वार्षिक परीक्षा के स्थान पर नियमित आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति अपनायी जाए। महिलाओं की शिक्षा तथा समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा पर अधिक बल दिए जाने का प्रस्ताव किया गया और यह अनुभव किया गया कि शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना चाहिए। नौकरी से डिग्रियों के असंयोजन के मामले पर अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों ही प्रकार की मिश्रित प्रतिक्रियायें प्राप्त हुईं। उच्चतर शिक्षा में सीमित भर्तियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में राजनीति पर प्रतिबंध लगाने पर व्यक्तियों की दृढ़ सहमति थी। इस विषय पर भी दृढ़तापूर्वक बल दिया गया कि भ्रष्टाचार तथा कुरीतियों से सख्ती से निपटा जाए। यह भ्रष्टाचार देश की समस्त शिक्षा पद्धति में व्याप्त है।

भारतीय शिक्षा पद्धति का सामाजिक लेखा परीक्षा : जनवाणी सम्प्रेषण का एक अध्ययन

पत्रों के विषयवस्तु विश्लेषण के आधार पर 2255 "जनवाणी" सम्प्रेषण तथा दस्तावेज तैयार किए गए।

प्राप्त हुए पत्र पूरे देश से आये थे और इनमें दादर तथा नागर हवेली, लक्ष्यद्वीप और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व था। (सबसे अधिक प्रतिउत्तर उत्तर प्रदेश तत्पश्चात महाराष्ट्र, दिल्ली तथा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए थे)।

पत्रों के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि ये जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग द्वारा लिखे गए थे। अधिकतम प्रतिउत्तर "विद्यार्थियों" के वर्ग से, तत्पश्चात "अध्यापकों" तथा शैक्षिक प्रशासकों और "नौकरी पेशा" तथा

"व्यावसायिकों से प्राप्त हुए थे। कुल प्रतिउत्तरों का लगभग दो/पांच भाग उन व्यक्तियों से प्राप्त हुआ जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं।

एक समस्या जो बार-बार उभर कर आती थी वह थी भिन्न-भिन्न प्रकार के स्कूलों में जनसंख्या के विभिन्न समूहों तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच "विषमताओं को दूर करना"। इन विषमताओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने शिक्षा की संरचना, विषयवस्तु, पाठ्यचर्या, मूल्यांकन पद्धति तथा स्कूलों में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं में एकरूपता का सुझाव दिया था। रोजगार से संबंधित एक अन्य क्षेत्र था जिस पर ध्यान दिया गया था।

व्यक्ति तथा देश के लिए शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाने के लिए पाठ्यचर्या में परिवर्तन, व्यावसायीकरण, नौकरी उन्मुख शिक्षा तथा नौकरी से डिग्री के विसंयोजन के सुझाव दिए गए। उत्तरदाताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजावाद के साथ-साथ राजनैतिक हस्तक्षेप, जो समग्र शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करता है, पर गहरी चिंता प्रकट की।

भारतीय शिक्षा की पुनः संरचना की दिशा में : विश्वविद्यालय का सम्बन्ध तथा भारतीय शिक्षा की पुनः संरचना की दिशा में : तकनीकी संस्थाओं का प्रत्यक्षण

इन दोनों मोनोग्राफों में विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी शिक्षा के 12 संस्थानों/संगठनों द्वारा संचालित सम्मेलनों की कार्यवाहियों की रिपोर्टें तथा आलेख दिए गए हैं।

विश्वविद्यालय अपनी स्वायत्तता के विषय में अधिक चिंतित थे, तथापि उन्होंने तकनीक शिक्षा के संस्थाओं तथा संगठनों ने पाठ्यचर्या को आधुनिक बनाने, व्यावसायीकरण तथा रोजगार उन्मुखता पर अधिक बल देने, तकनीकी शिक्षा के प्रबंध, उद्योग और संस्थाओं के बीच अधिक संपर्क बनाने, मानव शक्ति नियोजन तथा तकनीकी शिक्षा के विकास के बीच संबंध को सुदृढ़ करने अपक्षय को दूर करने, उद्योगों द्वारा तकनीकी शिक्षा की आंशिक लागत का भार वहन करने आदि विषयों पर ध्यान केंद्रीत करने की आवश्यकता अनुभव की।

भारतीय शिक्षा की पुनः संरचना की दिशा में : शैक्षिक संस्थाओं/निकायों के सुझाव तथा भारतीय शिक्षा की पुनः संरचना की दिशा में : शिक्षात्तर संगठनों के विचार

उपरोक्त दो मोनाग्राफों में दिसम्बर-जनवरी 1985-86 की अवधि के दौरान नई शिक्षा नीति से संबंधित 18 शैक्षिक तथा 29 शिक्षात्तर संस्थाओं/निकायों के प्राप्त प्रतिउत्तरों की जांच की गई। प्रथम खंड में अधिकांशतः बड़े और छोटे शैक्षिक संस्थाओं, विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंडलों, अखिल भारतीय राज्य तथा जिला स्तरीय संगठनों और संघों तथा राष्ट्रीय क्षेत्रीय और राज्य स्तर के अध्यापकों और विद्यार्थी संगठनों की प्रतिक्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। यद्यपि इन मोनोग्राफों में महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु से प्राप्त रिपोर्टों की अधिक संख्या है, फिर भी इसकी विशेषता यह है कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की संस्थाओं/संगठनों ने अपने-अपने प्रतिउत्तर भेजे हैं जो इसमें सम्मिलित किए हैं।

शैक्षिक तथा शिक्षा इतर संस्थाओं तथा निकायों के विचारों तथा सुझावों के फोकस में नागरिक प्रत्यक्षणों के समान प्रवृत्ति परिलक्षित होती हैं। इनमें नियोजन तथा प्रबंध, विषयवस्तु और पाठ्यचर्या, अध्यापक,

भाषा प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्यों आदि मामलों पर अन्यों की तुलना में अधिक बल दिया गया। विविध विषयों के संबंध में मतैक्य इस प्रकार थे :

शिक्षा को निम्नांकित विषयों का मुख्य साधन माना जाना चाहिए (1) देशभक्ति, मानवीय मूल्य, सामाजिक चेतना तथा अपनी विरासत तथा प्रजातंत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान, (2) वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा समग्र व्यक्तित्व का विकास, (3) इसको न केवल आर्थिक विकास का साधन माना जाए बल्कि समाज के नैतिक गुणों का रक्षक भी माना जाए।

विषयवस्तु तथा पाठ्यचर्या में सुधार के रूप में शिक्षा के एक व्यापक समान प्रतिरूप को, जो अपनी संरचना तथा स्वरों में एक रूपता दर्शाये, अत्यधिक आवश्यकता है। 10+2+3 पैटर्न की सार्वजनिक रूप से अपनाने का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया गया और इसके साथ-साथ विषयवस्तु तथा पाठ्यचर्या में निम्नांकित एकरूपता की अपेक्षा की गई : (1) प्रत्येक विषय के सीखने में निम्नतम प्रवीणता को परिलक्षित करने वाली एक मूल पाठ्यचर्या, जो राष्ट्रीय लोकाचार, विरासत तथा आकांक्षाओं को दर्शाने वाली हो, तथा (ii) स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय पक्षों पर महत्त्वपूर्ण रूप से दिया जाने वाला बल।

त्रिभाषा सूत्र में शिक्षा के माध्यम तथा राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी की परिस्थिति भाषा विषयक तीन मुख्य मामलों में थे। मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा को प्रारंभिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम बनाये जाने का समर्थन किया गया।

परीक्षाओं के मूल्यांकन के प्रश्न पर निम्नांकित मुद्दों पर मतैक्य प्रकट किया गया (i) पत्र के अंत में बाह्य परीक्षाओं के स्थान पर नियमित रूप से आंतरिक मूल्यांकन, (ii) परीक्षा तथा मूल्यांकन के लिए विषय के अध्यापक का उत्तरदायित्व, (iii) स्मृति परीक्षण के स्थान पर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के द्वारा प्रवीणता तथा संज्ञानात्मक योग्यताओं का परीक्षण, (iv) परीक्षा उत्तरदायित्वों को राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय बोर्डों आदि को सौंपना।

योजना और प्रबंध के संबंध में अत्यधिक ध्यान आकर्षण के विषय निम्नांकित हैं (i) रक्षा के तुरंत पश्चात शिक्षा विषय को प्राथमिकता दिए जाने (ii) केंद्र और राज्य अधिकार क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से निर्धारण, (iii) सामाजिक आर्थिक, क्षेत्रीय, ग्रामीण शहरी तथा लिंग संबंधी असमानताओं पर ध्यान देने तथा उन्हें कम करने के लिए लाभ वचन के आधार का पुन निरूपण, (iv) सार्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा के विषय को प्राथमिकता देना तथा (v) विकेंद्रीकरण तथा उत्तरदायित्वों को सम्मिलित करते हुए नियोजन तथा कार्यान्वयन की कुशल नीतियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना।

सामान्य रूप से शिक्षा के लिए केंद्र-राज्य के पर्याप्त आबंटन तथा विशेष रूप से सार्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा को निश्चित रूप से प्राथमिकता दिया जाना नई शिक्षा नीति की सफलता के लिए अनिवार्य समझा गया।

शैक्षिक प्रक्रिया में अध्यापकों को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान पुनः नियत किए जाने के लिए निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत किए गए : अध्यापक-पाठ्यक्रम का पुनः अभिविन्यास तथा आधुनिकीकरण, अध्यापकों का योग्यता, गुणवत्ता प्रतिबद्धता के आधार पर चयन, अधिक अच्छे वेतन, सेवा परिस्थितियों में सुधार, पदोन्नति के अवसर, निष्पादन पर आधारित प्रोत्साहन तथा अप्रोत्साहन आदि।

'सामाजिक न्याय' के विषय में विभिन्न मंचों से उभर कर आने वाले सुझावों का संबंध निम्न विषयों से था : अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के प्रति दृढ़ समर्थन जिसमें आरक्षण, लड़कियों,

ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों तथा विकलांगों और गरीब लोगों के लिए प्रोत्साहन तथा उपचारात्मक शिक्षण सम्मिलित हैं।

समता (निष्पक्षता) पर विचार-विमर्श करते समय संस्थाओं द्वारा निजी रूप से चलाए जाने वाले पब्लिक स्कूलों तथा प्रति व्यक्ति फीस पर रोक लगाने का सुझाव दिया गया।

शिक्षा से संबंधित स्वैच्छिक तथा व्यावसायिक निकाय—खंड I और II

दो खंडों में देश के विभिन्न भागों से 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 244 स्वैच्छिक संगठनों तथा निकायों से प्राप्त होने वाली रिपोर्टों तथा ज्ञापनों की जांच की गई हैं। इनमें विद्यालयों, कालेजों, तकनीकी शिक्षा अध्यापकों के संगठन, शैक्षिक प्रशासक, विद्यार्थी संघ तथा अभिभावक, अल्पसंख्यकों शैक्षिक तथा स्वैच्छिक निकायों से इतर व्यावसायिकों के संगठन सम्मिलित हैं।

रिपोर्टों से प्राप्त होने वाले मतों को 17 विषयों के अन्तर्गत बांटा गया। शिक्षा के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के अंतर्गत सामाजिक प्रासंगिकता, राष्ट्रीय एकीकरण, चरित्र निर्माण आदि पर बल दिया गया। शैक्षिक एकरूपता की संरचना में 10+2+3 प्रतिरूप आदि को समर्थन प्रदान किया गया। विषयवस्तु तथा पाठ्यचर्या में अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यचर्या के पुनरुत्थान पर बल देने के साथ-साथ एक राष्ट्रीय मूल, उपयोगी तथा आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रम पर फोकस किया गया। भाषा के प्रश्न पर निम्नलिखित मुद्दों को समर्थन प्रदान किया गया, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा का माध्यम, राष्ट्रीय भाषा को अपनाना, त्रिभाषा सूत्र के एक भाग के रूप में उत्तरी भारत में दक्षिणी भाषाओं का प्रारंभ आदि।

अध्यापकों की भर्ती तथा चयन में योग्यता, अभिक्षमता तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं पर ध्यान दिया जाना, निष्पादन पर आधारित प्रोत्साहन तथा अप्रोत्साहन, सेवा स्थितियों तथा पदोन्नतियों में स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रक्रियाओं का दृढ़ता से पालन आदि विषयों पर बल दिया गया। यह अनुभव किया गया कि व्यावसायीकरण में उद्योगों के भाग लिए जाने के अंतर्गत उच्च स्तरीय अध्ययनों तथा व्यावसायिक गतिशीलता आदि के लिए व्यावसायिक अनुबंधनों की प्रारंभ करने में आने वाली लागत का कुछ अंश उद्योगों को वहन करना चाहिए। क्षमता तथा प्रवीणता का परीक्षण, निरंतर आंतरिक मूल्यांकन, सत्र पद्धति तथा कुरीतियों को दूर करने के लिए दृढ़ उपायों के आधार पर परीक्षाओं में समग्र रूप से सुधार करने का समर्थन किया गया। विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा स्टाफ का राजनीति में भाग लेने पर रोक लगाने, राजनैतिक दलों के हस्ताक्षेप तथा कानूनी प्रावधानों की सहयता से सभी राजनैतिक हस्तक्षेप को दूर किया जाना चाहिए।

नयी शिक्षा नीति पर प्रेस : प्रेस की कतरनों का विश्लेषण तथा भारतीय शिक्षा की पुनः संरचना की दिशा में : प्रेस के विचार दृष्टिकोण

515 प्रेस करतनों में सम्पादकीय, लेख, सम्पादक के नाम पत्र तथा समाचार रिपोर्ट सम्मिलित हैं। ये कतरनें हिन्दी अंग्रेजी, मराठी, बंगाली, उड़िया, तमिल तथा उर्दू भाषाओं से ली गई थीं। 20 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के समाचार-पत्रों की प्रेस करतनों को विश्लेषण के लिए चुना गया। तथापि हिन्दी और अंग्रेजी की करतनें ही अधिकांशतः ली गई थीं। अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के प्रेस प्रतिउत्तर अधिक थे।

योजना और प्रबंध की वेदी पर ही शिक्षा के प्रत्येक स्तर तथा पक्ष में विकृतियों को सुधारने के कार्य और साथ ही पूरी नहीं की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के कार्यों को निर्धारित किया गया। इनके कार्य क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को प्राथमिकता प्रदान करना, सार्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक द्रुत कार्य तथा संचार प्रौद्योगिक का उपयोग आदि सम्मिलित हैं। गलत विकल्प की वजह से उच्चतम लागत के कारण पर्याप्त संसाधन की मांग की गई परन्तु गैर मौद्रिक निवेशों, अतिरिक्त तथा समुदाय संसाधनों के जुटाव तथा सीखने वालों से विभेद लागतों के वसूल किए जाने पर भी समान रूप से बल दिया गया।

भारतीय शिक्षा की पुनः संरचना की दिशा में : राज्यों के प्रत्यक्षण (विचार) भारतीय शिक्षा की पुनः संरचना की दिशा में : राज्य स्तर के विचार-विमर्शों का विश्लेषण तथा नई शिक्षा नीति : उत्तर प्रदेश का परिप्रेक्ष्य

पहले दो मोनोग्राफों में 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विचार विमर्शों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया, एक अति विस्तृत रूप में और दूसरा प्रारंभिक रूप में।

इन विचार-विमर्शों का स्वरूप मुख्यतः क्षेत्रीय होते हुए इनका विश्लेषण प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्रौढ़ शिक्षा स्तरों के संबंध में किया गया है। इनमें विश्लेषण के सामान्य विषय से संबंधित सामान्य समस्याओं के अतिरिक्त नियोजन तथा प्रबंध से संबंधित विषयों पर भी विशेष रूप से फोकस किया गया है। नियोजन और प्रबंध के अंतर्गत विकेंद्रित समुदाय सहभागिता, स्कूल काम्पलेक्स् विकासात्मक क्षेत्रों से संबद्धता, प्रशासनिक कैडर का व्यावसायीकरण, शिक्षा में उत्तरदायित्व, भारतीय शिक्षा सेवा तथा राज्य/जिला संसाधन केंद्र आदि विषयों पर अभिव्यक्त किए गए मतों की जांच पर विशेष ध्यान दिया गया। कार्यवाहियों की पूरी जांच से तात्कालिक कार्यों पर दिए जाने वाले बल की आवश्यकता प्रकट हुई।

'उत्तर प्रदेश का परिप्रेक्ष्य' शीर्षक से मोनोग्राफ खंड, जिला तथा क्षेत्रील स्तर पर संगठित की गई 72 संगोष्ठियों की रिपोर्ट कार्यवाहियों पर आधारित है। लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के संबंध में तथा संरचना और विषय-वस्तु दोनों में उत्तर प्रदेश में प्राप्त विचार भारत के अन्य भागों से प्राप्त मतों के समान ही हैं। त्रिभाषा सूत्र के एक भाग के रूप में अहिंदी राज्य की भाषा को तीसरी भाषा के रूप में अपनाने के पक्ष में प्रकट किए गए मतैक्य उल्लेखनीय है। शैक्षिक अवसरों की समानता के अभियान के भाग के रूप में बढ़ती हुई सामाजिक क्षेत्रीय तथा लिंग संबंधी विषमताओं को रोकने के उपायों पर बल देने के अतिरिक्त विकसित/अविकसित क्षेत्रों में नए स्कूल खोलने के लिए निधियों तथा शक्तियों का विभागीकरण करने का दृढ़ अनुमोदन किया गया। यद्यपि उत्तर प्रदेश शिक्षा को जाब से संबद्ध करने की आवश्यकता पर सुनिश्चित था, परन्तु उसके विचार में रोजगार से डिग्री को अलग किए जाने का प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है। अध्यापकों की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए उनकी सेवा-पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण का समर्थन किया गया। शिक्षा का बढ़ता हुआ राजनीतिकरण उत्तर प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं में अव्यवस्थित स्थितियों का मूल कारण है। अध्यापकों के राजनैतिक क्रियाकलापों तथा उनकी आचरण संहिता पर नियन्त्रण रखने का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया गया। शिक्षा में कुरीतियों को अक्षम्य अपराध मानने की आवश्यकता को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई और साथ ही जन समूह शिक्षा को जन आंदोलन बनाने की इच्छा को भी सार्वजनिक रूप से स्वीकृति प्राप्त हुई है।

17-20. वर्ष 2000 में भारतीय शिक्षा परियोजना एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत पूरे किए गए चार अध्ययन : 01/ई पी एल/01

17. भारत में प्राथमिक शिक्षा—कुछ परिगणना साक्ष्य (01/ईपीएल/01.2)
18. शैक्षिक नियोजन तथा प्रबन्ध के लिए प्रतिरूपण माडलों के उपयोग पर प्राथमिक शिक्षा (01/ई पी एल/01.3)
19. भारत में प्राथमिक शिक्षा : एक प्रवृत्ति विश्लेषण (01/ई पी एल/01.4)
20. भविष्य विकास के लिए शिक्षा की योजना—समस्याएं तथा विकल्प (01/ई पी एल/01.5)

इस परियोजना कार्य के अनुसंधान स्टाफ में डॉ० ब्रह्म प्रकाश, परियोजना निदेशक, श्री एम० एम० खान, परियोजना सहयोगी, श्री मनोज शर्मा, श्री इफ्तिकार अहमद तथा सुश्री मंजू रूडोला, परियोजना सहायक सम्मिलित थे।

भारत में प्राथमिक शिक्षा : कुछ परिगणना साक्ष्य

यह दस्तावेज मूलत: आयु-विशेष जनसंख्या (ए एस पी) तथा भारतीय स्कूल पद्धति की प्राथमिक अवस्था के अनुरूप नामांकन स्तरों पर फोकस करता है। दोनों ही चरों का, उनकी रचना और वृद्धि दर का, लिंग अनुसार विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। 1951 से प्रारंभ करते हुए पिछले तीन दशकों में लड़के और लड़कियों की आयु-विशेष जनसंख्या (6-11 वर्ष) में वृद्धि, पिछले तीन दशकों में भारतीय स्कूलों की 1 से 5 कक्षाओं में लड़के और लड़कियों के नामांकन में वृद्धि, तथा वर्षों के दौरान कुल नामांकन अनुपात में परिवर्तन/सुधार तथा प्राथमिक स्तर के नामांकनों में मंदता मूल प्रस्ताव थे जिनकी जांच की गई।

दस्तावेज से यह पता चलता है कि पिछले दशक को छोड़कर जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों में लड़कियों की नामांकन संख्या में संवृद्धि हुई है, प्रत्येक 1000 लड़कों के प्रति लड़कियों की संख्या में सामान्य कमी आई है। दस्तावेज में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि नामांकन में वृद्धि 1950 से 1960 की अवधि में आयु-विशेष जनसंख्या (ए एस पी) में वृद्धि की तुलना में अधिक है, परन्तु 1970 के दशक में वृद्धि दर लगभग समान हो गई थी। यह भी देखा गया कि पिछले तीन दशकों में लड़कियों के नामांकन में लड़कों के नामांकन की तुलना में वृद्धि अधिक तीव्रता से हुई है। इस अध्ययन से उभर कर आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक का संबंध प्राथमिक स्तर के सकल नामांकन सें है। कुछ अध्ययनों पर आधारित सकल नामांकनों के आकलनों का प्रयोग प्राथमिक शिक्षा की व्याप्ति को मापने के लिए किया गया है। आयु से अधिक और कम नामांकन की समस्याओं तथा निहितार्थों पर परिचर्चा की गई।

शैक्षिक नियोजन तथा प्रबन्ध के लिए प्रतिरूपण मॉडलों के उपयोग पर प्राथमिक शिक्षा

बहुत समय से स्थूल तथा सूक्ष्म स्तर पर पद्धति की प्रवृति अथवा व्यवहार को जानने के लिए प्रतिरूपण मॉडलों का व्यापक रूप से अनुप्रयोग किया गया है। इसकी उपयोगिता के बावजूद भी विकासशील देशों में विशेष रूप से इसके अनुप्रयोग की प्रयिधियां अधिक नहीं है। प्रणाली के तकनीकी ब्यौरे का वर्णन न करके इस शोधपत्र में प्रतिरूपण मॉडल तथा शैक्षिक नियोजन और प्रबन्ध में इनकी अनुप्रयुक्तता का सामान्य रूप से वर्णन किया गया है।

शैक्षिक पद्धति के मॉडलों के विकास के लिए एक प्रारंभिक ढांचे पर परिचर्चा की गई तथा अनुकूल आधार सामग्री की आवश्यकताओं को भी अभिव्यक्त किया गया। मॉडल के अनुप्रयोग को एक उदाहरण की सहायता से चित्रित किया गया। पद्धति की प्रवृति से संबंधित प्रश्नों की एक बड़ी संख्या का उत्तर मॉडलों की जटिलता को, जो अधिकांशत: आधार-सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करती है, बढ़ा कर दिया जा सकता है। उच्च गति वाली आधार सामग्री प्रक्रमण मशीनों तथा पद्धतियों की मॉडलिंग की तकनीकों का प्रयोग बड़े मॉडलों को चलाने में किया जा सकता है।

भारत में प्राथमिक शिक्षा : एक वृद्धि विश्लेषण

यह दस्तावेज दो पक्षों पर फोकस करता है : प्रथम नामांकनों, अध्यापकों तथा शैक्षिक व्यय के संदर्भ में वर्ष 1951 से 1983 की अवधि के दौरान शैक्षिक विकास का सांख्यिकी विश्लेषण तथा द्वितीय, इसमें इन चरों के संबंध में वर्ष 2000 के लिए प्रक्षेपण तैयार करने का प्रयत्न किया गया है। वृति तथा प्रक्षेपणों की जांच करने के लिए प्रगतिमय विश्लेषण—सरल और बहु आयामी, प्रविधि का प्रयोग किया गया है। वृत्ति का अध्ययन विभिन्न समयावधियों जैसे 1951-1983, 1961-1983 तथा 1971-1983 के लिए किया गया। इन समयावधियों के वक्र से यह सूचित होता है कि प्राथमिक नामांकन की वृद्धि दर कम होती जा रही है।

विश्लेषण के आधार पर अध्ययन से प्रकट होता है कि निरपेक्ष रूप से प्राथमिक स्तर पर नामांकनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथापि यह अभी तक अनुरूप आयु-विशेष जनसंख्या के समीप नहीं पहुंचा है। इसका मुख्य कारण लड़कियों का निरंतर निम्न नामांकन है। यद्यपि समयावधियों में लड़कियों के नामांकन में सुधार हुआ है तथापि अभी भी इसमें निरंतर कमी आती रही है।

यदि अध्यापक-छात्र के अनुपात को उचित सीमा तक पहुंचाना है तो अतिरिक्त नामांकन के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की बहुत बड़ी संख्या की आवश्यकता है, अध्ययन से यह भी प्रकट हुआ कि यद्यपि समयावधियों में वास्तविक रूप से व्यय बढ़ा है, परन्तु इस बढ़ोत्तरी का काफी भाग मुद्रास्फीति के कारण लाभहीन हो गया और इसके परिणामस्वरूप सातवें दशक में वास्तविक व्यय में कमी आ गई।

अध्ययन के निष्कर्ष से यह ज्ञात हुआ कि सार्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न तीन मुद्दों पर संकेंद्रित प्रयत्न की आवश्यकता है—लड़कियों का नामांकन, अतिरिकत अध्यापकों की व्यवस्था तथा प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था।

भविष्य विकास के लिए शिक्षा की योजना-समस्यायें और विकल्प

यह दस्तावेज विकास के वर्तमान प्रतिरूप की, जो औद्योगिक क्रांति के तत्पश्चात् उभर कर सामने आया है, मुख्य विशेषताओं का विवेचन करता है। इसमें प्रौद्योगिकी तथा संबंधित संगठनात्मक परिवर्तनों को दो मुख्य विशेषताएं माना है जिन्होंने संसार भर में अभूतपूर्व परिवर्तन की धूम मचा दी यद्यपि इसकी चर्चा मुख्यत: आर्थिक विकास के संदर्भ में ही की गई है तथापि विश्व विकास की इस प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने में सामान्य रूप से सामाजिक संस्थाओं में और विशेष रूप से शिक्षा (विशेषत: पश्चिमी, अंग्रेजी माध्यम से तथा औपचारिक और कक्षा कक्ष पर आधारित) द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका का प्रत्यक्ष उल्लेख किया गया है। इस विषय के संदर्भ में यह दस्तावेज सातवीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2000 के परिप्रेक्ष्य में जांच करता है तथा भविष्य में भारतीय शिक्षा के संभाव्य वृद्धि प्रतिरूप का पूर्वानुमान करता है।

इस दस्तावेज में आगामी विभिन्न नामांकन दृश्यों पर परिचर्चा की गई है।

अध्ययन में यह देखा गया कि लोक उद्यमों में यदि निवेश अपर्याप्त तथा अथवा अनिश्चित होता है, संबंधित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाती, जबकि उनके टिके रहने के लिए व्यक्ति तथा समूह के लघुकालीन स्व-हितों के कौशलों का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। अध्ययन में वर्ष 2000 में कार्य दल तथा कार्य इतर जन-संख्या का शैक्षिक पार्श्वचित्र प्रस्तुत किया गया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा पद्धति पर नियन्त्रण के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के बीच लेन-देन को एक 'त्रिकल्प' मैट्रिक्स' में इकट्ठा किया गया। विश्लेषण को सरल बनाने के विचार से केवल दो ही विशेषताओं—सार्वजनिक लोक व्यय की यात्रा तथा विस्तार के आकार को लिया गया है। अध्ययन से प्रकट हुआ कि प्राथमिक शिक्षा की सार्वजनीनता तथा उच्चतर शिक्षा (व्यावसायिक) का विकास इन दोनों क्षेत्रों के गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों पक्षों को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए, खुली अधिगम पद्धतियों पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए और यदि उन्हें व्यापक पैमाने पर चलाया जाए तो वे अत्यधिक लागत प्रभावी हो सकती है। सामान्य माध्यमिक तथा सामान्य उच्चतर शिक्षा की वृद्धि पर नियन्त्रण रखा जाना चाहिए क्योंकि इन क्षेत्रों में विस्तार की तीव्र प्रवृति दिखाई देती है तथा विस्तार की प्रक्रिया में अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए नियत किए गए संसाधनों का प्रयोग इनके लिए किया जाने लगता है।

यह आशा की जाती है कि इस सरलीकृत व्याख्या से शैक्षिक विकास की दीर्घकालीन योजना का निर्माण करने के लिए शिक्षा के विभिन्न पक्षों के बीच अन्योन्यसंबंध का प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त होगी।

प्रगत्योन्मुखी अध्ययन

संस्थान द्वारा हाथ में लिए गए निम्नलिखित अध्ययन प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में है—

(क) जारी अध्ययन

1. भारत में अवसर की समानता तथा शैक्षिक अवसर के समानीकरण के विशेष संदर्भ में शैक्षिक वित्तीयन का अध्ययन—उत्तर प्रदेश तथा केरल में स्कूल शिक्षा का अध्ययन (भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रायोजित मार्च, 1985 में प्रारंभ किया गया। (02 / ई एफ एन/04)
2. वर्ष 2000 में भारतीय शिक्षा—एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य (यह अध्ययन मई, 1983 में प्रारंभ किया गया) (01/ई पी एल/02)
3. कालेजों द्वारा अपनी भूमिका के निष्पादन का अध्ययन (यह अध्ययन अगस्त 1983 में प्रारंभ किया गया) (02/ई ए डी/02)
4. केरल में शिक्षा के विकास का अध्ययन (यह अध्ययन फरवरी 1984 में प्रारंभ किया गया) (04/ई पी ओ/14)।
5. पुनहाना प्रखंड, जिला गुड़गांव (हरियाणा) के बीस गांवों के एक एकक में प्रारंभिक शिक्षा के

सार्वजनीकरण के उद्देश्य से शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी व्यवहारों पर आधारित कार्यानुसंधान (यह कार्य मार्च, 1984 में आरम्भ किया गया) (एस बी एन/17)

6. इंजीनियरिंग कालेजों में कार्मिक ढांचे (यह अध्ययन मई 1984 में प्रारम्भ किया गया)
7. इंजीनियरिंग कालेजों में तालिका नियन्त्रण प्रबन्ध (यह अध्ययन मई 1984 में प्रारम्भ किया गया) (ओ ई ए डी/04)

8-16. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए निम्नांकित राज्यों में प्रारंभिक स्तर पर गैर औपचारिक शिक्षा के मूल्यांकन अध्ययन से सम्बन्धित परियोजना की 9 मूल्यांकन रिपोर्टें (यह अध्ययन मार्च 1985 से प्रारम्भ किया गया) (07/एस एन एस/06)

—आंध्र प्रदेश (07/एस एन एस/06.1)
—असम (07/एस एन एस/06.2)
—बिहार (07/एस एन एस/06.3)
—जम्मू और कश्मीर (07/एस एन एस/60.4)
—मध्य प्रदेश (07/एस एन एस/06.5)
—उड़ीसा (07/एस एन एस/06.6)
—राजस्थान (07/एस एन एस/06.7)
—उत्तर प्रदेश (7/एस एन० एस०/06.8)
—पश्चिमी बंगाल (07/एस एन एस/06.9)

17. भारत में शिक्षा तथा विकास पर मोनोग्राफ (यह जून, 1985 को प्रारम्भ किया गया) (04/ई पी ओ/13)
18. परिवर्तन का प्रबन्ध : भारतीय मॉडल की दिशा में (यह नवम्बर, 1985 को प्रारम्भ किया गया) (02/ई ए डी/05)

(ख) स्वीकृत अध्ययन

1. उच्चतर शिक्षा में समानता, गुणता तथा लागत (यूनेस्को द्वारा प्रायोजित) (06 / एच आर ई/04)
2. भारत में साक्षरता : एक देश-काल विश्लेषण (1901-1981) (ए4/ई पी ओ/15)
3. कालेजों के विकास तथा उनकी प्रभावी कार्यकारिता—एक कार्यानुसंधान अध्ययन (06/एच आर ई/06)
4. उच्चतर शिक्षा में संसाधनों का प्रभावी आयोग—एक केस अध्ययन (06/ई एफ एन/05)

प्रासंगिक पत्र

1. भारत में आदिवासी-साक्षरता : क्षेत्रीय आयाम

यह शोध पत्र प्रो० मूनिस रजा तथा प्रो० ईजाजुद्दीन अहमद तथा डा० शोल चन्द्र नूना ने मिलकर लिखा था।

इस पत्र में भारत में 1961 से 1981 तक की अनुक्रमिक गणनाओं में रिकार्ड की गई अनुसूचित जातियों को साक्षरता की परिवर्तित स्थिति की समीक्षा करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें आदिवासी

साक्षरता के व्यापक क्षेत्रीय ढांचे की पहचान की गई है। इस पत्र में गणना तिथि से, जिसका कोई भी महत्व हो सकता है, परिवर्तन की मुख्य प्रकृतियों का पता चलता है। इसमें साक्षरता प्राप्तियों के सन्दर्भ आदिम जातियों तथा गैर आदिम जातियों के निष्पादन की तुलना की गई थी जिससे भारत में मुख्य रूप से आदिवासी जातियों वाले राज्यों में सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न साक्षरता अभियानों की सफलता अथवा असफलता की प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। इस पत्र में आदिजाति जनसंख्या के अपने ही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, विभिन्न भागों में साक्षरता-असमानता का प्रश्न उठाने का प्रयत्न किया गया है और इस विषय के लिए हम से स्पष्टीकरण की मांग की गई है जिसकी व्याख्या करना सरल नहीं है।

2. भारत में शिक्षा की लागत का विश्लेषण

यह शोध पत्र डा० जे० बी० जी तिलक द्वारा लिखा गया है।

इस पत्र के तीन मुख्य उद्देश्य हैं : पहला, शिक्षा के लागतों के विस्तृत विश्लेषण के लिए संकल्पनात्मक तथा विश्लेषणात्मक ढांचे को प्रस्तुत करना, दूसरा, शिक्षा की लागतों/वित्तीयन क्षेत्र में विशेषज्ञों तथा अनुसंधानकर्ताओं को प्राप्त होने वाले आंकड़ों की जांच करना, तथा तीसरा भारतीय संदर्भ में पहले से किए गए विविध आनुभाविक अध्ययनों का स्वीकृत आंकड़ों के मौलिक विश्लेषण की सहायता से भारत में वर्तमान समय में शिक्षा की लागतों का आनुभविक विश्लेषण प्रस्तुत करना। अध्ययन के तीन मुख्य भागों में उपरोक्त तीनों मामलों पर क्रमशः चर्चा की गई हैं। अंतिम भाग में पूर्ववर्ती भागों में किए गए विश्लेषणों के निहितार्थों से अनेक महत्वपूर्ण आशय निकाले गए है।

पहले भाग में लेखक ने लागत विश्लेषण की महत्ता पर प्रकाश डाला है, शिक्षा की लागतों की वर्गिकी का वर्णन किया है, शिक्षा की इकाई लागतों की विकल्प संकल्पनाओं तथा अन्य संकल्पनात्मक और विश्लेषणात्मक मामलों पर परिचर्चाएं की गई हैं। भाग दो में निजी तथा संस्थागत दोनों ही शिक्षा की लागतों की सरकारी तथा गैर सरकारी सांख्यकी के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तीसरे भाग में लेखक ने लागतों के कुछ आनुभविक अनुमानों पर आधारित भारत में शिक्षा की लागतों का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है। इस पत्र में अपने नए विश्लेषणों के अतिरिक्त लेखक ने भारत में शिक्षा की लागतों तथा संबंधित पक्षों पर स्वयं तथा अन्यों द्वारा किए गए पूर्ववर्ती अध्ययनों और उनसे निकाले गए अनुमानों को भी आधार माना है। इसी आधार पर लेखक ने समस्या के निम्नांकित विविध आयामों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम तथा नीति निहितार्थ निकाले हैं, शैक्षिक नियोजन में लागतों का महत्व, निजी तथा संस्थागत लागतों में उत्पादन प्रक्रिया का स्वरूप, शिक्षा की लागतों में क्षेत्रीय विविधतायें, शिक्षा की लागत तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध आदि। इस पत्र के अन्त में समस्याओं में संबंधित कुछ मुख्य सुझाव दिए गए हैं।

भाग तीन

परामर्शदायी, सलाहकारी तथा समर्थनकारी सेवाएं

शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में परामर्शदायी, सलाहकारी तथा समर्थनकारी सेवाएं प्रदान करना संस्थान के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। वर्ष के दौरान संस्थान ने समस्याभिमुखी अनुसंधान अध्ययन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्य-शालाओं का आयोजन करके तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन और अकादमिक समर्थन देकर केन्द्र और राज्य सरकारों तथा दूसरे देशों के संस्थानों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को कई सेवाएं प्रदान की हैं। इस संबंध में संस्थान की गतिविधियों को व्यापक रूप से निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(क) केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुरोध पर किए गए अनुसंधान अध्ययन और परियोजनाएं,

(ख) राज्य सरकारों और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के अनुरोध पर आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं/अध्ययन दौरे और,

(ग) संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, समितियों और कार्यदलों तथा अन्य परामर्शकारी सेवाओं में संकाय का योगदान।

राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान द्वारा प्रदान की गई परामर्शदायी, सलाहकारी और समर्थनकारी सेवाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

1. राष्ट्रीय

(क) अध्ययन तथा परियोजनाएं

नई शिक्षा नीति के प्रतिपादन के लिए पृष्ठभूमि-निर्माण सामग्री के तौर पर शिक्षा-प्रणाली पर लोगों की राय जानने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के आग्रह पर संस्थान ने मंत्रालय द्वारा प्राप्त पत्रों, शिक्षा मंत्री के जनवाणी कार्यक्रम में भाग लेने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्राप्त पत्रों, समाचार-पत्र की कतरनों, जिला/राज्य स्तर की विचार गोष्ठियों की रिपोर्ट और संगठनों/व्यावसायिक निकायों के ज्ञापन के विषय-विश्लेषण के अनुकूल काम हाथ में लिया। संस्थान ने बहुत ही अल्प समय में अपने विषय-विश्लेषण के आधार पर सारे देश से आने वाली लगभग 10,000 सिफारिशों में से विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत 11 शिक्षा रिपोर्ट तैयार की हैं। (अनुसंधान और अध्ययन पर भाग-2 में क्रमसंख्या 5 से 16 देखिए) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के आग्रह पर संस्थान ने शिक्षा में पिछड़े व राज्यों आन्ध्र

प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिमी बंगाल में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए 9 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परियोजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन का काम भी हाथ में लिया।

(ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने कुल 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए इनमें से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरोध पर (7 कार्यक्रम), मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुरोध पर (5 कार्यक्रम), राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (1 कार्यक्रम) केंद्रीय विद्यालय संगठन (1 कार्यक्रम) और भारतीय तकनीकी शिक्षा समाज के अनुरोध पर (1 कार्यक्रम) (संलग्नक 1 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्र० 5, 12, 13, 16, 19, 21, 27, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44 और 60 देखिए)

(ग) अखिल भारतीय सम्मेलन, संगोष्ठियों, कर्मशालाओं समितियों, कार्यदलों और अन्य परामर्शदायी सेवाओं में संकाय का योगदान

संस्थान ने कई उच्च स्तरीय अखिल भारतीय सम्मेलनों, समितियों और संगोष्ठियों में भाग लिया। इस संबध में संस्थान का मुख्य योगदान निम्नलिखित क्षेत्रों में था :

(I) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्माण (रा० शि० नी०)

पृष्ठभूमि सामग्री के अतिरिक्त संस्थान ने नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए तैयार किए गए विभिन्न प्रलेखों के विषय-विश्लेषण के आधार पर "शिक्षा विकास—एक स्थिति विवरण और नीति विषय" शीर्षक से एक वृहत् लेख तैयार किया। लेख में आकांक्षाएं और आवश्यकताएं, निष्पादन, शिक्षा का सामाजिक अंतरापृष्ठ, शिक्षा-रोजगार अंतरापृष्ठ, समस्याएं और विषय, योजना प्रबंध, और नई चुनौतियों की ओर जैसे विषयों पर आलेख शामिल हैं। इस प्रलेख और संस्थान द्वारा शिक्षा प्रणाली के सैक्टर अनुसार किए गए विश्लेषण का उपयोग, शिक्षा की चुनौती—एक नीति परिप्रेक्ष्य, पर मंत्रालय के लेख में निवेश के तौर पर किया गया जिसने कि इस महत्वपूर्ण विषय को राष्ट्रीय वाद-विवाद का आधार बनाया।

संस्थान ने शैक्षिक योजना और प्रबंध विषयों पर विचार-विमर्श के लिए शिक्षा पर चार प्रादेशिक और एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों का भी आयोजन किया।

संस्थान के संकाय ने शोध पत्र तैयार किए, मंत्रालय द्वारा स्थापित विभिन्न कार्यदलों में सक्रिय भाग लिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर संगोष्ठियों/समितियों/बैठकों में भाग लिया जिनकी सूची नीचे दी गई है :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के संदर्भ में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में कई बैठकें हुई;

दिल्ली प्रशासन द्वारा आयोजित नई शिक्षा नीति पर संगोष्ठी;

शिक्षा नीति पर कलकत्ता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्वी प्रदेश संगोष्ठी;

विभिन्न राज्यों जैसे कि पश्चिमी बंगाल, मेघालय, पांडीचेरी, उत्तर प्रदेश, केरल और उड़ीसा में नई शिक्षा नीति पर राज्य और केंद्र प्रशासित स्तर की संगोष्ठियां;

सेंट जेवियर स्कूल की अगुवाई में स्कूलों के समूहों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित संगोष्ठी :

गुजरात सरकार, गांधी नगर द्वारा गठित नई शिक्षा नीति की समन्वय समिति;

विद्या भारतीय, नई दिल्ली (एक राष्ट्रीय स्तरीय संगठन जो देश में 2000 स्कूल चला रहा है) में नई शिक्षा नीति पर संगोष्ठी;

दौलतराम महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति पर रजत जयंती समारोह संगोष्ठी;

'शिक्षा की चुनौती—एक नीति परिप्रेक्ष्य, शीर्षक पृष्ठभूमि प्रलेख पर विचार-विमर्श के लिए ग्राम प्रौद्योगिकी की उन्नति की समिति की बैठक;

हैदराबाद में अखिल भारतीय माध्यमिक अध्यापक परिसंघ द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित अखिल भारतीय संगोष्ठी;

'नागपुर में शिक्षा को चुनौती' शीर्षक प्रलेख पर विचार-विमर्श के लिए अध्यापकों और स्नातकों के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले एम आई सी एस पर संगोष्ठी;

सालवान पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चतुर्थ अखिल भारतीय सम्मेलन के कार्यकारी समूह की बैठक;

ए आई एफ यू सी टी ओ, विजयवाड़ा द्वारा नई शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन;

नई शिक्षा नीति पर शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन;

शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री की आर्थिक समिति के साथ बैठक;

भारतीय शैक्षिक परमर्शद लि० नई दिल्ली में साक्षरता और अनुवर्ती शिक्षा पर बैठक;

नई दिल्ली में एन सी ई आर टी और राजा राम मोहन राय पुस्तकालय द्वारा संयुक्त रूप से नई शिक्षा नीति, पुस्तकालयों और सूचना प्रणाली पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी;

विकास, नई शिक्षा नीति और शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर अखिल भारतीय सम्मेलन, और;

नई शिक्षा नीति में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एन सी ई आर ठी के कार्यक्रम ।

(II) मॉडल स्कूल

भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश के हर जिले में एक मॉडल स्कूल शुरू किया जाना है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने नीपा से मॉडल स्कूलों के प्रबंध के लिए डिजाइन तैयार करने को कहा है। डिजाइन संयुक्त परामर्शों द्वारा तैयार किया गया जिसमें कि नीपा और एन सी ई आर टी के संकाय सदस्यों सहित दोनों संगठनों के निदेशकों ने भाग लिया। कई अन्य विशेषज्ञों और विभिन्न प्रकार के स्कूलों के प्रधानाचार्यों से भी परामर्श किया गया। अन्त में मॉडल स्कूलों के प्रबंध की प्रस्तावित योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दी गई।

प्रस्तावित योजना के तथ्यों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रबन्ध प्रादेशिक निदेशालय, स्थानीय स्तर पर प्रबन्ध ब्लाक अनुदान प्रणाली, कर्मचारी-वर्ग स्थापना (प्रादेशिक निदेशक प्रिंसिपल, अध्यापक आदि), कुछ महत्व-पूर्ण प्रबन्धकीय कार्य, (पत्र-व्यवहार, लोकतन्त्रीकरण, कर्मचारी वर्ग का विकास और नवाचार जवाबदारी और क्षेत्र अन्तर मानक शामिल हैं।

III. वार्षिक योजना विचार-विमर्श

संस्थान ने वर्ष के दौरान योजना आयोग में शिक्षा क्षेत्र पर विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की शिक्षा के बारे में कार्य समूहों का प्रतिनिधित्व किया।

IV. प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजीनकरण पर कार्यदल

संस्थान शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए नौ राज्यों और केन्द्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय समिति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित प्रारंभिक शिक्षा पर कार्यदल का प्रतिनिधित्व करता है। संकाय के वरिष्ठ सदस्यों ने इन कार्यदलों की बैठकों में भाग लिया और राज्यों को कार्ययोजना तैयार करने में सहायता देने के रूप में पर्याप्त सहयोग दिया।

V. शिक्षा विकास पर सूचना का प्रसार

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में शिक्षा योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अद्यतन विकासों के बारे में सूचना प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए संस्थान ने प्रादेशिक समाचार-पत्रों, राज्य संवाददाताओं से प्राप्त रिपोर्टों, योजना, शिक्षा, वित्त आदि के राज्य विभागों जैसे विभिन्न स्रोतों से इस प्रकार को सूचना एकत्रित करने की प्रणाली को मजबूत बनाया। संस्थान ने इस सूचना की ई पी ए बुलेटिन के माध्यम से 'न्यूज फ्रौम द स्टैट्स' के रूप में प्रचारित किया।

VI. शिक्षा मन्त्रियों/सचिवों के सम्मेलनों में भागीदारी

संस्थान ने वर्ष के दौरान राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर आयोजित विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों और शिक्षा निदेशकों की विभिन्न बैठकों और सम्मेलनों में भाग लिया। इन बैठकों में संस्थान ने शिक्षा प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए और शिक्षा योजनाकारों और प्रशासकों के काडर के व्यावसायीकरण के लिए सुझाव दिए।

VII. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में बैठकें

संस्थान ने वर्ष के दौरान मंत्रालय के ब्यूरों अध्यक्षों की बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया। इसने निम्न-लिखित बैठकों में भी भाग लिया।

अनुमोदित निवासीय स्कूलों में भारतीय छात्रवृत्ति योजना का सरकारी सलाहकार बोर्ड;
कम्प्यूटर सीम्युलेशन माडल बैठक;
हर जिले में आदर्श स्कूल बनाने की योजना के कार्यान्वयन निरीक्षण के लिए विषय निर्वाचन समिति;
विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्रों और अध्यापकों का सहयोग;
शिसा के लिए संसाधनों के समूह;
मानव संसाधन विकास (शिक्षा विभाग) मंत्रालय में अनुसंधान अध्ययन;
बालिकाओं के शिक्षा के वर्धन पर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के सहयोग के साथ यूनेस्को

द्वारा प्रायोजित अध्ययन का कार्य अपने हाथ में लेने वाली विषय निर्वाचन समिति,
भारत में शिक्षा सांख्यिकी का कम्प्यूटरीकरण,
महिला शिक्षा पर उच्च स्तरी स्थायी समिति,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली में योजना तथा प्रौढ़ शिक्षा ब्यूरो के कार्य की समीक्षा के लिए विवरण बैठक,
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जाति शिक्षा;
ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं;
संसद सलाहकार समिति;
शिक्षा का व्यावसायीकरण; और
गैर औपचारिक प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने के लिए उपयुक्त योजना का निर्माण।

VIII. बैठकें, संगोष्ठियां और परिसंवाद

संस्थान ने निम्नलिखित बैठकों, संगोष्ठियों और परिसंवादों में भाग लिया :

नई दिल्ली में आयोजित स्वैच्छिक संगठनों के पदाधिकारियों और प्रौढ़ शिक्षा में मूल स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ कार्यक्रम;
भारतीय शिक्षा योजना और प्रशासन संघ;
जनसंख्या और विकास पर द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन;
यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित-शिक्षा उप-समिति;
नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में स्वास्थ्य के लिए अन्तर क्षेत्रीय समन्वय पर नामिका द्वारा विचार-विमर्श;
इन्दिरा गांधी संस्थान की स्थापना;
अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक परिसंघ द्वारा आयोजित एन. एफ. ई. पर अखिल भारतीय संगोष्ठी;
महिलाओं की समानता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संगोष्ठी;
नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के सहयोग में यू० एस० ओ० द्वारा आयोजित शिक्षा उत्पादकता पर संगोष्ठी;
बाल शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी;
महिला वैज्ञानिक कार्यकत्री साधारण सभा (भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, 73 वां अधिवेशन);
छठी भारतीय भूगोल कांग्रेस, खडगपुर;
भारतीय शिक्षा संस्थान, पूना में आयोजित शिक्षा विकल्पों पर सगोष्ठी;
राष्ट्रीय प्रगतिशील स्कूल सम्मेलन;
शिक्षा और विकास पर संगोष्ठी : भारत और समाज अनुभव;
आर्थिक संवृद्धि संस्थान की साधारण सभा;
भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद में आयोजित शिक्षा विकास तथा योजना कार्यशाला;
भारतीय शिक्षा संस्थान, पूना में आयोजित भविष्य 1921-80 के लिए शिक्षा सुधारों, कारणों,

परिणामों और पाठों पर संगोष्ठी,

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित 'आगामी दशक में कार्यकर्ताओं की शिक्षा' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी;

एशियाई समाज में शिक्षा और विकास पर संगोष्ठी;

9-14 आयु वर्ग के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित गैर-औपचारिक योजना की पुनर्रचना;

योजना के बहुस्तरीय प्रणाली पर योजना आयोग;

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2001 शताब्दी में उच्च शिक्षा के लिए ब्लू प्रिंट पर राष्ट्रीय संगोष्ठी;

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली में अभिविन्यास कार्यक्रम का विशिष्ट ब्यौरा तैयार करने के लिए कार्य समूह का गठन किया गया;

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उप-तकनीक समिति;

उच्च शिक्षा में समकालीन मुद्दों पर बैठक;

नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थायी समिति;

राजस्थान के आर्थिक विकास पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संगोष्ठी उदयपुर में हुई,

भारतीय विश्वविद्यालय संघ के हीरक जयंती समारोह पर उच्च शिक्षा में नई प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन;

प्रशासनिक सुधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय;

दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल का शासी निकाय;

खुला विश्वविद्यालय के दूरी की शिक्षा अनुभव पर राष्ट्रीय संगोष्ठी;

स्वायत्त कालेजों में प्रशासन की शिक्षा और योजना पर संगोष्ठी व कार्यगोष्ठी;

भारत में उच्च शिक्षा के चुने हुए दाब क्षेत्रों में संसाधन आबंटन प्रक्रम;

वाई एम सी ए सांस्कृतिक केन्द्र में पाठ्यक्रमों की पहचान पर खुले विश्वविद्यालयों की बैठकें;

केन्द्रीय विद्यालय संगठन अकादमिक समिति;

अमरावती नगर, कोयम्बटूर जिला (तमिलनाडु), में सैनिक स्कूलों के भारतीय पब्लिक स्कूलों के सम्मेलन का 46 वां अधिवेशन;

स्कूलों में गुणता शिक्षा : ए पी जे शैक्षिक सोसाइटी द्वारा आयोजित संकल्पनाएं, तकनीकें और मूल्यांकन;

खुले स्कूलों की सीनियर सैकेंडरी कक्षाओं के लिए शिक्षा योजना तैयार करने के लिए उप-समिति; और ग्रामीण प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए परिषद् ।

IX. एन सी ई आर टी के साथ सहयोग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तकनीकी और व्यवसायिक समर्थन के लिए रीतियां विकसित करने के लिए नीपा और एन सी ई आर टी के शिक्षा निदेशकों और उनके वरिष्ठ सहकर्मियों के बीच अनेक बैठकें हुईं जिससे वे शिक्षा में गुण-अभिवृद्धि के क्रम में प्राथमिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनों को ही शुरू कर सकें। मई, 1985 में एक संयुक्त स्थायी समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित शामिल थे :

एन सी ई आर टी	नीपा
—निदेशक	—निदेशक
—संयुक्त निदेशक	—कार्यपालक निदेशक
—समन्वय अध्यक्ष और निदेशक के दो नामित व्यक्ति	—अध्यक्ष (प्रशिक्षण) और निदेशक के दो नामित व्यक्ति

एन सी ई आर टी अध्यक्ष (समन्वय) और नीपा अध्यक्ष (प्रशिक्षण) ने अपने-अपने संगठनों की ओर से विशेष कार्यक्रमों के समन्वय के लिए दिन-प्रतिदिन सम्पर्क बनाए रखने के लिए सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य किया, इन कार्यक्रमों की पहचान संयुक्त स्थायी समिति द्वारा की गई। समिति की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से हर तिमाही बैठक की गई। इस समिति ने प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श क्षेत्रों की पहचान भी की जहां एन सी ई आर टी और नीपा दोनों सहयोग कर सकें।

समन्वय के निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई :

1. प्रशिक्षण : परियोजनाएं बनाने, प्रशिक्षण की कार्य प्रणालियां, योजनाएं, प्राथमिक कार्यक्रमों और योजनाओं के अनुवीक्षण और मूल्यांकन, प्रशिक्षण सामान के विकास, इत्यादि जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों पर एकाग्रता के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सामान्य कार्यनीति का विकास;
2. अनुसंधान : अनुसंधान के लिए दोनों संगठनों के प्रचालन क्षेत्र पहचाने जाएंगे और सामान्य अनुसंधान कार्यक्रम तैयार किए जा सकेंगे;
3. परामर्श : दोनों संगठनों के रुचि के क्षेत्रों में सक्रियता पर परामर्श के लिए एक संयुक्त दल बनाया गया।

नीपा और एन सी ई आर टी के बीच समन्वय निरन्तरता और परम्परा के आधार पर होगा और दोनों संगठनों द्वारा प्रकाशित सभी गैर-मूलपाठी सामग्री का प्रस्तावित सहयोगी प्रबन्ध के अन्तर्गत नियमित रूप से विनिमय होगा।

नीपा और एन सी ई आर टी के बीच समन्वय के लिए संयुक्त स्थायी समिति की एक बैठक 7 अक्तूबर, 1985 को हुई। अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अन्तर्गत एन सी ई आर टी के संयुक्त निदेशक को नीपा की कार्यक्रम सलाहकार समिति का सदस्य नामित किया गया और 28 जनवरी, 1986 को हुई इसकी अन्तिम बैठक में आमन्त्रित किया गया। गैर औपचारिक शिक्षा पर एक संयुक्त अनुसंधान अध्ययन बिल्कुल तैयार है।

नीपा ने वर्ष के दौरान एन सी ई आर टी द्वारा आयोजित निम्नलिखित विभिन्न कार्यक्रमों में भी सक्रिय भाग लिया :

पाठ्यक्रमों प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी;

प्राग विद्यालय और प्रारंभिक शिक्षा के सलाहकार बोर्ड के विभाग की बैठक;

+2 स्तर पर कम्प्यूटर अध्ययन शुरू करने के बारे में बैठक;

माडल स्कूल पाठ्यक्रम पर समिति की बैठकें;

पढ़ाई बीच में छोड़ देने वालों को और कक्षा दोहराने वालों की समस्याओं का सामना कर सकने के

लिए प्राथमिक शिक्षा कार्मिकों के पुनः प्रशिक्षण के लिए कार्यनीति तय करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला;
शिक्षा के व्यावसायीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी;
माध्यमिक शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी;
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम;
एन सी ई आर टी द्वारा आयोजित गैर औपचारिक शिक्षा पर वार्षिक सम्मेलन;
अध्यापकों के भारी अभिविन्यास के लिए मुख्य कार्मिकों के प्रशिक्षण की कार्यविधि पर कार्यशाला;
शिक्षा के व्यावसायीकरण पर बैठक;
महिला शिक्षा पर स्थायी समिति की बैठक, और व्यावसायीकरण पर कार्यसमूह की बैठक;

इसी तरह एन सी ई आर टी ने भी नीपा द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया।
नीपा और एन सी आर आई टी ने संयुक्त रूप में समन्वित योजना और औपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा के बीच अनुपूरण के रूप में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

II. उप-राष्ट्रीय स्तर

(क) अध्ययन और परियोजनाएं

संस्थान ने केरल में शैक्षिक विकास के इतिहास पर अध्ययन और अनुसंधान अध्ययन कारवाई का काम हाथ में लिया। ये अध्ययन हरियाणा के जिला गुड़गांव के पुन्हाना ब्लाक के 20 गांवों के समूहों में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण के उद्देश्य के साथ शिक्षा योजना और प्रशासन में परिवर्तन लाने की पद्धति पर आधारित थे। देखिए क० सं० 4 और 5 अनुबन्ध-II में अध्ययन प्रगति पर है।

आई सी एस एस आर द्वारा प्रायोजित शैक्षिक वित्त प्रबन्ध पर केरल और उत्तर प्रदेश में विद्यालय शिक्षा पर व्यक्ति अध्ययन भी प्रगति पर है (देखिए क्र० सं० 1 अनुबंध-II)

वर्ष के दौरान संस्थान ने स्कूल स्तर तक शैक्षिक संस्थानों के लिए संस्थागत योजना और मूल्यांकन के लिए साधन खोजने में उत्तर प्रदेश राज्य की मदद की। संस्थान ने हरियाणा राज्य में +2 स्तर के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए भी व्यक्ति अध्ययनों का विकास किया।

(ख) कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर 13 कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जो इस प्रकार हैं : हरियाणा-7, उत्तर प्रदेश-2, मध्य प्रदेश-3 और दादरा और नगर हवेली-1 (देखिए अनुबंध-1 क्र० सं० 7, 9, 10, 21, 22, 37, 38, 39, 40, 41, 47 और 50)

(ग) बैठकें, संगोष्ठियां और परिसंवाद

—1984-85 के लिए प्रो० डी० सी० शर्मा स्मारक पुरस्कार,
—केन्द्रीय विद्यालयों (i) सादिक नगर और, (ii) मस्जिद मोठ की शासी निकाय की बैठक,
—स्कूलों के अध्यक्षों और तमिल शैक्षिक संघ, करोलबाग नई दिल्ली के अध्यापकों की संगोष्ठी;

—ए ई सी प्रशिक्षण कालेज और केन्द्र पचमढ़ी में जरूरतों पर आधारित विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के पुनर्निर्माण पर संगोष्ठी;
—भारतीय विद्या भवन में शिक्षा में अनिवार्यता पर संगोष्ठी;
—उत्तरपूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग में भारत के जतजाति एटलस पर कार्यशाला,
—टी टी टी आई चंडीगढ़ में सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के अनुबंधन पर प्रादेशिक कार्यशाला,
—राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विकास गति विज्ञान पर संगोष्ठी,
—सरदार पटेल विद्यालय, दिल्ली की प्रबन्ध समिति की बैठक, और
—महिला शक्ति पर साहित्य अकादमी साक्षरता मंच, नई दिल्ली की बैठक,

III. अन्तर्राष्ट्रीय

(क) अध्ययन और परियोजनाएं

शिक्षा के बाह्य वित्त प्रबन्ध पर युनेस्को द्वारा प्रायोजित अध्ययन पूरा किया गया (देखिए भाग-2 में क्र० सं० 4) संस्थान ने यूनेस्को द्वारा प्रायोजित एक अन्य अध्ययन उच्च शिक्षा में समानता, विशेषण और लागत को हाथ में लिया। (देखिए अनुबंध-2 में क्र० सं० 1 के अन्तर्गत संस्वीकृत अध्ययन)

(ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम

1984-85 के दौरान शुरू किया गया शैक्षिक योजना और प्रशासन में पहला अन्तर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कोर्स वर्ष के दौरान पूरा किया गया। दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कोर्स भी वर्ष के दौरान शुरू किया गया। (देखिए अनुबन्ध 1 में क्र० सं० 54 और 56)

संस्थान ने छः अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए। इनमें यूनेस्को के अनुरोध पर (4), यू एस ई एफ आई (1) और माल द्वीप सरकार के अनुरोध पर (1) देखिए अनुबन्ध 2 की क्र० सं० 1, 2, 31, 45, और 55)

(ग) संगोष्ठी और परिसंवाद

पेरिस में शैक्षिक कर्मिकों के लिए समकालीन प्रशिक्षण नीतियां और योजनाओं पर अन्तर प्रादेशिक परिसंवाद;
शिमला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी;
नई दिल्ली में उच्च शिक्षा पर यूनेस्को प्रादेशिक कार्यशाला;
पपुआ, नई गिनी में माध्यमिक शिक्षा में नई प्रवृत्तियों और प्रक्रियाओं पर मंच;
पार्ट मेस (पपुआ, न्यू गिनी) में यूनेस्को द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा पर नई प्रवृत्तियों और प्रक्रियाओं पर उपाध्यक्ष मंच;
ए आई यू, नई दिल्ली द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय रजिस्ट्रारों और प्रशासकों का चतुर्थ

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन;

नेपाल के क्षेत्र अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, संस्थागत नेटवर्क और स्कूल मानचित्रण पर यूनेस्को द्वारा प्रायोजित परियोजना;

वारसा तकनीकी विश्वविद्यालय (वारसा, पोलैंड), में आयोजित राज्य शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के भाग लेने पर विशेषज्ञों की बैठक;

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा आयोजित यूनेस्को पर संगोष्ठी-अनुदर्शन और प्रत्याशा में; और

भारतवर्ष में शिक्षा और सामाजिक स्तरीकरण आर्थिक विकास के कारक के रूप में व्यापार, इन्स्टीट्यूटों पर ला को-आपरेजिआन यूनिवर्सिटरिया, रोम, इटली और बकोनी विश्वविद्यालय, मिलान, इटली द्वारा आयोजित लौम्बरडिया और भारत प्रदेश में आर्थिक विकास की तुलना पर संगोष्ठी।

भाग चार

अन्य अकादमिक क्रियाकलाप

शैक्षिक योजना और प्रशासन में प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्शी और सलाहकारी सेवाएं संस्थान के प्रमुख क्रियाकलाप हैं। संस्थान कों दूसरे महत्वपूर्ण शैक्षिक क्रियाकलाप इस प्रकार हैं—

(क) शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में नवाचार का प्रसार;

(ख) शैक्षिक नीति के मूलभूत मुद्दों और उद्देश्यों पर विचार-विमर्शों की शुरूआत;

(ग) शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी संकल्पनाओं और पद्धतियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देना;

(घ) संकाय सदस्यों द्वारा दूसरे संगठनों के क्रियाकलापों में और जिन विषयों में उन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त की हुई हैं उन क्षेत्रों में अकादमिक सहयोग; और

(ङ) शिष्टमंडलों और अभ्यागतों का स्वागत करना।

वर्ष के दौरान इस तरह के अकादमिक क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

(क) नवाचारों का प्रसार

संस्थाम ने विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से शैक्षिक और प्रशासन के क्षेत्र में सफल प्रयोगों और नवाचारों के बारे में प्राप्त सूचना को प्रलेखित किया है। इस प्रलेखन का उद्देश्य वरिष्ठ शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों को नियमित आधार पर अन्तर्ज्यी अध्ययन दौरों पर भेजने की व्यवस्था करके अनुभवों का परस्पर आदान-प्रदान करवाना है और उन्हें इन नवाचारी प्रयोगों को गहराई से अध्ययन करने के लिए तैयार करना है ताकि विचारों की अदला-बदली को बढ़ावा मिले और इन सफल प्रयोगों और नवाचारों के दूसरे राज्यों में विस्तार और पुनरावृत्ति की संभावना और भी बढ़े।

नई शिक्षा नीति में स्वायत्त कालेजों की संकल्पना स्वीकार की गई है। पिछले लगभग-पांच सालों से लगभग बारह कालेज स्वायत कालेज के रूप में कार्य कर रहे हैं और इतने समय में अनेक कालेजों ने अपने विश्वविद्यालयों को स्वायत्ता प्रदान करने के लिए आवेदन भेजे हैं। स्वायत कालेजों के विकास और अनुभवों का अध्ययन करने की दृष्टि से बीस चुने हुए कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा 8 से 14 फरवरी, 1986 तक स्वायत कालेजों का दौरा किया गया ताकि नई शिक्षा नीति को अमल में लाने में सहायता मिल सके और साथ ही स्वायत्तता के इच्छुक कालेजों की लाभ मिल सके। कालेजों से अनुरोध किया गया कि वे सुझाए गए दिशा

निर्देशों के आधार पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करें—ताकि उनके स्वायत्त रूप से कार्य करने के बारे में मूलभूत सूचना प्राप्त की जा सके। अभ्यागत दल द्वारा अध्ययन के दौरे के उद्देश्य और स्वरूप तथा प्रश्नों के प्रकारों के बारे में जो गुणात्मक सूचना प्राप्त की जानी थी उसके बारे में अभ्यागत प्रधानाचार्यों को दो दिन के लिए अभिविन्यस्त किया गया। 'स्वायत्तता और उत्तरदायित्व' शीर्षक ड्राफ्ट रिपोर्ट की अंतिम रूप दिया जा चुका है और प्रधानाचार्यों के बीच परिचालित किया जा चुका है। यह रिपोर्ट पांच भागों में है जो इस प्रकार है—भाग-1 'स्वायत्तता और उत्तरदायित्व' की संकल्पना और पद्धति, भाग-2-स्वायत्त कार्य की प्रक्रिया, समस्याएं और नाजुक मुद्दे; भाग-3 छात्रों, अध्यापकों, गैर अध्यापन स्टाफ और मोटे तौर पर समुदाय पर प्रभाव; भाग-4 स्वायत्तता और उत्तरदायित्व की संकल्पना को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक संरचनात्मक और क्रियाविधि परिवर्तन; और भाग-5 नीति सुझाव।

(ख) नीपा वार्तागोष्ठी

नीपा वार्तागोष्ठी शिक्षा और विकास में महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श और दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान के लिए एक व्यावसायिक मंच है जो संकाय को अपनी संकल्पनात्मकता तीव्र करने, सैद्धान्तिक आधार सुदृढ़ करने और शिक्षा नीति के आधारभूत मुद्दों और उद्देश्यों पर अधिकाधिक सुस्पष्टता से योगदान देने के योग्य बनाता है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सभी भाग लेने वालों को और उसमें रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों को वार्ता गोष्ठियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

वर्ष के दौरान 16: वार्तागोष्ठियां आयोजित की गईं। विभिन्न सत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर शिक्षा में कम्प्यूटर और टैक्नोलाजी जैसे अनेक विषयों पर चर्चा हुई। कई प्रकार के संगठनों के वक्ता सामने आए जिनमें भारत और विदेश में स्थित अनेक विश्वविद्यालय और विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाएं सम्मिलित हैं, जिन विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्रम सं०	तिथि	शीर्षक	वक्ता
1.	15 मई, 1985	राष्ट्रीय शिक्षा नीति: तुरन्त प्राथमिकता बल	डा० एस० एन० सराफ, अवैतनिक अध्येता, नीपा, नई दिल्ली
2.	22 मई, 1985	मूल्य प्रबंध: शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता	डा० वी० वी० देशपांडे, सहायक प्रोफेसर आई आई टी, नई दिल्ली
3.	29 मई, 1985	तकनीकी शिक्षा और ग्रामीण विकास	डा० आर० एन० कपूर, निदेशक, इंजीनियरी और ग्रामीण टैक्नोलाजी संस्थान, इलाहाबाद
4.	5, जून, 1985	सीखने की खुली प्रणाली	डा० जी० रामारेड्डी, उपकुलपति, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

1	2	3	4
5.	12 जून 1985	मालदीव में शिक्षा-वर्तमान स्थिति और भविष्य की आवश्यकताएं;	कुमारी बदूरा सलीम, शिक्षा विभाग, मालदीव
6.	19 जून, 1985	विकास प्रशासन	कुमारी जयश्री जलाली, नीपा, नई दिल्ली
7.	3 जुलाई, 1985	शिक्षा और भविष्य	डा० एस० सी० सेठ विज्ञान और टैक्नोलाजी विभाग, नई दिल्ली
8.	21 अगस्त, 1985	थाईलैंड में शिक्षा	श्री चंतर्त कोटकाम, शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्रालय, थाईलैंड
9.	28 अगस्त, 1985	स्कूलों में कम्प्यूटर क्लब	श्री आनन्द कार्तिक, कम्प्यूटर विशेषज्ञ, नई दिल्ली
10.	4 सितम्बर, 1985	भारतवर्ष में 2000 ईस्वी में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की स्थिति	डा० डेविड सेलिग्मैन, सी आई ई टी, एन सी ई आर टी, नई दिल्ली
11.	23 दिसम्बर, 1985	प्रासंगिक अभिकल्पना: सामाजिक तकनीकी शैक्षिक नेटवर्क के विकास की ओर	डा० डेविड पी हुब्स्ट कार्य अनुसंधान संस्थान, आस्लो, नार्वे
12.	6 दिसम्बर, 1985	इटालवी आर्थिक विकास और तीसरी दुनिया	डा० गुईडो त्रावग्लिनी, रोम विश्वविद्यालय, इटली
13.	22 जनवरी, 1985	शिक्षा पर फोकस सहित सिस्टम (होलिस्टिक) एप्रोच	प्राफेसर आई० एलिसन, काल्गेट विश्वविद्यालय, यू० एस० ए०

1	2	3	4
14.	3 फरवरी, 1986	शिक्षा का व्यावसायीकरण	प्रोफेसर एम० वुडहाल, लन्दन शैक्षणिक प्रशासन विश्वविद्यालय, शिक्षा और परामर्श विश्व बैंक संस्थान
15.	12 फरवरी, 1986	कम्प्यूटर और समाज	प्रोफेसर आर राज गोपालन औद्योगिक प्रबंध आई आई टी, मद्रास
16.	17 फरवरी, 1986	शिक्षा और मानव संसाधन विकास	प्रोफेसर पी० आर० ब्रह्मानन्द, आर्थिक स्कूल बम्बई विश्वविद्यालय

शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी संकल्पनाओं और पद्धतियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी संकल्पनाओं और पद्धतियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 1982-83 के दौरान निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों से शुरू किया गया था,

सूक्ष्म स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी पद्धतियों को बढ़ावा देना,

नवाचारी प्रयोगकार्य के अनुभवों से साधारणीकरण का अकाट्य रूप से वर्णन करने और उसका सार्थक रूप से सार निकालने तथा उस बारे में सर्जनात्मक चिंतन करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेरित करना; और इस तरह के साधन उपलब्ध करना जिनके द्वारा इस प्रकार के प्रयोगकार्य, अनुसंधान और सर्जनात्मक चिंतन का प्रचार हो सके।

वर्ष के दौरान प्रतियोगिता की गुंजाइश की ओर व्यापक बनाकर उसमें उप शिक्षा अधिकारियों, सीनियर सेकेंड्री स्कूलों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों के अध्यक्षों को सम्मिलित किया गया ताकि अधिक अच्छे और अधिक संख्या में लोग भाग ले सकें। प्रमुख समाचार-पत्रों और शैक्षिक पत्रि-काओं में विज्ञापन देकर भी कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया गया।

यह कार्यक्रम सूक्ष्म-स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचारी पद्धतियों को बढ़ावा देने में शैक्षिक कार्यकर्ताओं की सहायता करने और उनके द्वारा एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाने के उद्देश्य से विशेष रूप से तैयार किया गया है। भाग लेने वालों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जिला स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में नवाचारों तथा प्रयोगकार्यों से संबंधित किसी भी शीर्षक पर एक शोध पत्र प्रस्तुत करें। पुरस्कृत किए जाने वाले लेखों के लिए प्रत्येक के लिए 1000-00 रुपए के पुरस्कार की व्यवस्था है। ये पुरस्कार 10 से अधिक नहीं हैं।

वर्ष के दौरान चौथी अखिल भारतीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। दस प्रविष्टियां प्राप्त हुई। फिरोजपुर (पंजाब) के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल के प्रिंसीपल डा० एम० एल० सचदेव द्वारा प्रस्तुत 'एन इन्वेष्टिगेशन इन द कालेज आफ इन्डिसिप्लिन अमंग स्कूल स्टूडेंट्स एण्ड एप्लिकेशन आफ रिमेडियल मेजर्स' लेख को सर्वश्रेष्ठ आंका गया और पुरस्कार दिया गया।

(घ) विशेषता प्राप्त क्षेत्रों में संकाय का शैक्षिक योगदान

संस्थान का संकाय दूसरे शैक्षिक और व्यावसायिक निकायों को उनके प्रशिक्षण तथा अनुसंधान क्रियाकलापों में निवेश उपलब्ध कराता है, शैक्षिक और शासकीय समितियों/ शिष्ट मंडलों के सदस्य के रूप में कार्य करता है और विशिष्टीकरण के अन्य क्षेत्रों में शोधपत्र और पुस्तकें प्रकाशित करने जैसे कार्य करता है।

संस्थान ने विभिन्न राज्य सरकारों और दिल्ली प्रशासन, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली, तमिल शिक्षा संघ, नई दिल्ली, संयुक्त स्कूल संगठन, नई दिल्ली, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन, राष्ट्रीय रक्षा कालेज, नई दिल्ली, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली, आर्थिक संवृद्धि संस्थान, दिल्ली, राट्रीय जनसहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, अनुप्रयुक्त जन-शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और भारत में कई दूसरे संगठनों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में संकाय का सहयोग दिया।

संकाय द्वारा दिए गए इस प्रकार के योगदान का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 3 में दिया गया है।

(ङ) शिष्टमंडल और अभ्यागत

संस्थान देश और विदेश के विभिन्न भागों से आने वाले शिष्टमंडलों का स्वागत करता है, वर्ष के दौरान संस्थान में जिन दूसरे देशों से विशिष्ट शिक्षाविद् आए वे इस प्रकार हैं: अदन विश्वविद्यालय, यमन, एशिया और पेसेफिक (बैंकाक) में यूनेस्को क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, पेरिस, शैक्षिक योजना संस्थान, पाकिस्तान, राष्ट्र मंडल तकनीकी सहयोग प्रतिष्ठान, लन्दन; और बहरीन के शिक्षा मंत्री। चीन और नेपाल के शिष्टमंडल भी संस्थान में आए, देश के अनेक गणमान्य व्यक्ति संस्थान में अभ्यागत के रूप में आए जिसमें, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री, उप-कुलपति और अन्य विशिष्ट शिक्षाविद योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से अन्य अधिकारी सम्मिलित हैं।

कुछ विशिष्ट अभ्यागतों की सूची अनुबंध 4 में दी गई है।

भाग पांच

शैक्षणिक एकक

संस्थान का संकाय निम्नलिखित आठ एककों में गठित किया गया है—

1. शैक्षिक योजना
2. शैक्षिक प्रशासन
3. शैक्षिक वित्त
4. शैक्षणिक नीति
5. स्कूल और गैर-औपचारिक शिक्षा
6. उच्च शिक्षा
7. उप-राष्ट्रीय पद्धति
8. अन्तर्राष्ट्रीय

शैक्षणिक एककों की भूमिका

शैक्षणिक एककों से आशा की जाती है कि संस्थान की नीतियों और उपलब्ध निधि की ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए तथा एककों को सौंपे गए कार्यक्षेत्रों में परामर्शी और सलाहकारी सेवाएं देने के लिए वे पूरे दायित्व से कार्य करेंगे। एककों से निम्नलिखित कार्यों की आशा की जाती है :

(i) विभिन्न प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों की योजना बनाना और नियत करना,

(ii) परामर्शी और सलाहकारी सेवाओं के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना,

(iii) संस्थान के भीतर एककों को दिए गए कार्य के अनुसार उनके अपने-अपने कार्यक्षेत्रों के अनुसार सभी कार्यक्रमों का समन्वय करना,

(iv) एकक के विभिन्न प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और अनुसंधान डिजाइन पर विचार करना, और

(v) समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का पालन करना।

एककों के अध्यक्षों से आशा की जाती है कि अपने एकक के सदस्यों को नेतृत्व प्रदान करें, उनके क्रियाकलापों का समन्वय करें और उन्हें अपने कर्त्तव्यपालन करने में सहायता दें, एकक के विभिन्न प्रशिक्षण और अनुसंधान

कार्यक्रमों तथा अन्य क्रियाकलापों पर विचार करने, योजना बनाने और नियत करने के लिए समय समय पर बैठकें आयोजित करना। वे प्रशिक्षण के निदेशक/कार्यकारी निदेशक/डीन की सामान्य देखरेख में संकाय और एकक के दूसरे सदस्यों के कार्य का आवश्यक पर्यवेक्षण करते हैं।

शैक्षणिक एकक सतत दीर्घकालिक आधार पर कार्य करते हैं। निदेशक द्वारा समय समय पर विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए विशेष कार्यदलों और समितियों का गठन किया जाता हैं। संस्थान द्वारा हाथ में ली गई विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण करने, सलाह, सुझाव देने के लिए सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है जिसमें विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं।

इन एककों द्वारा अपनाए गए कार्यों का स्वरूप मोटे तौर पर नीचे दिया गया है :

शैक्षिक योजना एकक

शैक्षिक योजना के दो मोटे आयाम हैं। पहले विकास और परिवर्तन के संदर्भ में यह दूसरे सामाजिक-आर्थिक सेक्टरों के साथ शिक्षा की द्वि-दिशिक अनुबंधन के बारे में बताती है। दूसरे, यह शैक्षिक सेक्टर के ही कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन में सहायता देती है और इसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्य नीति तय करती है। इन दोनों पहलुओं की नीति निहितार्थों को समाकलित ढंग से स्पष्ट करने की दृष्टि से शैक्षिक एकक दोनों ही पक्षों का विस्तार से अध्ययन करना चाहता हैं। शिक्षा मंत्रालय और योजना आयोग तथा अनेक राज्य सरकारों के समर्थन में एकक एक व्यावसायिक समूह के रूप में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। ऐसा कर सकने के योग्य बनने के लिए एकक सिनेरियों निर्माण के क्षेत्र में तथा माडलिंग और पद्धति विश्लेषण के भी अधिक यथार्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। यह शैक्षिक पद्धति की सामाजिक पद्धति की एक उप-पद्धति के रूप में देखने के साथ-साथ इसे ऐसे परिवर्तनकारी माध्यम के रूप में देखता है जो कि प्रगति की दिशा निश्चित करती है।

अधिक विशिष्ट रूप से शैक्षिक योजना के क्षेत्र में यह अध्ययन और प्रशिक्षण, शिक्षा और जन-सांख्यिकी, शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षा और रोजगार को आपस में जोड़ने और विश्लेषण करने के साथ-साथ शिक्षा के भीतर ही अंतर-क्षेत्रीय बद्धता प्रदान करने, शैक्षिक योजना में जनशक्ति आवश्यकताओं को दर्शाने और शैक्षिक क्षेत्र में प्रादेशिक तथा संस्थागत योजना तैयार करते हैं। एकक के क्रियाकलाप मात्रात्मक प्रति-दर्शों और तकनीकों पर आधारित योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा, बहुस्तरीय योजना और दीर्घकालीन भविष्य संबंधी अध्ययनों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

वर्ष के दौरान एकक ने छः कार्यक्रम आयोजित किए। (देखिए अनुबंध-1 कार्यक्रम कोड सं० 01/85-86-01 से 01/85-86/06 तक दिए गए हैं) आजकल एकक वर्ष ई० 2000 में भारतीय शिक्षा-एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य, नामक अनुसंधान परियोजना में एकक जुटा हुआ है और इस शीर्षक के अन्तर्गत चार अध्ययन पूरे कर लिए हैं। (देखिए भाग-II-अनुसंधान अध्ययन क्रम सं० 17-20 पर : और अनुबंध II-अनुसंधान अध्ययन कोड सं० 01/इ० पी० एल/01 पर)

शैक्षिक प्रशासन एकक

वर्तमान उत्तरदायित्वों और समय-समय पर सामने आ खड़े होने वाले नए कार्यों की चुनौतियों का सामना

करने के लिए शैक्षिक प्रशासन का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। प्रशासनिक तंत्रों के संरचनात्मक सुधार के लिए प्रयास तो किए ही जाते हैं। वर्तमान तंत्र के कार्य में सुधार करके और मुख्य रूप से कार्मिक प्रबन्ध में तथा संस्थाओं के मनोबल में सुधार द्वारा निकट भविष्य में अधिक शीघ्र परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

शैक्षिक प्रशासकों के व्यावसायिक पक्ष की संवृद्धि द्वारा शैक्षिक प्रशासन की दक्षता सुधारना संस्थान की मुख्य चिंता है। शैक्षिक प्रशासन एकक अपने विभिन्न प्रशिक्षण, अनुसंधान-कार्यक्रमों और अन्य क्रिया-कलापों द्वारा संस्थागत और परम संस्थागत स्तरों पर शैक्षिक प्रशासकों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। एक ओर तो यह शैक्षिक प्रशासनिक मशीनरी को आधुनिक बनाने में सहायता देता है और दूसरी ओर यह शैक्षिक प्रशासकों में अपेक्षित प्रबन्ध संबंधी कुशलताओं को विकसित करने का प्रयास करता है ताकि वे सामान्य रूप से समाज की नई-नई मांगों और नई-नई चुनौतियों का और विशेष रूप से शैक्षिक विकास का सामना करने के योग्य बन सकें। शिक्षा के क्षेत्र में संबद्ध संस्थागत प्रबन्ध प्रतिनिधित्व, नेतृत्व, निर्णय लेना, प्रेरणा, संप्रेषण, संघर्षों का प्रबन्ध, समय प्रबंध, मानव संसाधन विकास, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध, नवाचारों और परिवर्तन का प्रबंध कार्मिक मूल्यांकन, संस्थागत मूल्यांकन जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाता है।

वर्ष के दौरान एकक ने पन्द्रह कार्यक्रम आयोजित किए। (कोड संख्या 02/85-86/01 से 02/85-86/05 तक के कार्य क्रम अनुबंध 1 में देखिए)।

तीन अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए जिनकी रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। वर्ष के दौरान शैक्षिक परिवर्तन के प्रबंध पर एक नए अनुसंधान अध्ययन की शुरुआत की गई है। (कोड संख्या 02/ए डी/02 से 02/इ ए डी/05 तक अनुसंधान अध्ययन अनुबंध 11 में देखिए)

शैक्षिक वित्त एकक

भारत जैसे देश में सभी चरणों में जनसंख्या की तेज वृद्धि और शिक्षा के असाधारण विस्तार के कारण शिक्षा के लिए वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर गंभीर बाधा पड़ी है। इसलिए शैक्षिक वित्त का प्रभावशाली प्रबंध अत्यन्त महत्वपूर्ण बन गया है।

इसके अनुसार ही शैक्षिक वित्त एकक राज्य के शिक्षा विभागों और विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें प्रशिक्षण देने के काम में जुट गया है। एकक अधिकारियों को शिक्षा में होने वाले अद्यतन विकास और रुझानों के बारे में जानकारी देता है और उन्हें वित्तीय प्रबंध के आधुनिक तरीकों और तकनीकों से अवगत कराता है। यह पी० पी० बी० एस० संसाधन उपयोग, लागत, व्यय को मानीटर करना, शैक्षिक विकास के लिए गैर आर्थिक निवेशों जैसे क्षेत्रों में उनके ज्ञान और कुशलता का विकास करता है।

वर्ष के दौरान शैक्षिक वित्त एकक ने तीन कार्यक्रम आयोजित किए (कोड संख्या 03/85-86/01 से 03/85-86/03 तक दिए कार्यक्रमों को अनुबंध I में देखिए) एकक ने एक अनुसंधान अध्ययन पूरा कर लिया है दूसरे अध्ययन का कार्य पूरा होने वाला है और एक अध्ययन को मंजूरी मिल चुकी है जिस पर अभी कार्य शुरू किया जाना है। (कोड संख्या 03/ई एफ एन/05 पर अनुसंधान अध्ययन अनुबंध II में देखिए)।

शैक्षिक नीति एकक

स्वातन्त्रोत्तर काल में राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में शिक्षा की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना सरकार की बहुत बड़ी चिन्ता रही है। सभी को शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षिक प्रणाली के स्वरूप को बदलने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। ग्रामीण और दूसरे पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाएं दी जा रही हैं और बालिकाओं, अनुसूचित जन जातियों तथा विकलांगों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। शिक्षा की भविष्य के परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है।

भारत और तीसरी दुनिया में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर एकक का ध्यान गया है जिन मुख्य मुद्दों के बारे में एकक विचारशील है वे इस प्रकार हैं :

शिक्षा और विकास—इनका पारस्परिक संबंध, मात्रात्मक, गुणात्मक, साम्यता और दक्षता के मुद्दे, शिक्षा और परिवर्त्तन तथा परम्परा और आधुनिकता के मुद्दे, शिक्षा में केन्द्रीयकरण बनाम विकेन्द्रीयकरण और समाधिकारिता के अन्तर्गत केंद्र राज्य संबंध। एकक के अनुसंधान और प्रशिक्षण क्रियाकलाप इनमें से एक या एक से अधिक क्षेत्रों से संबंधित हैं।

वर्ष के दौरान एकक ने छः प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए (कार्यक्रम अनुबंध I में कोड संख्या 04/85-86/01 से 04/85/36/06 तक देखिए)

एकक का प्रमुख योगदान नागरिकों में मिले उत्तरों, जनवाणी संप्रेषणों, प्रेस करतनों, शिक्षा पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक निकायों की सम्मतियों की विषयवस्तु का विश्लेषण करना रहा है। इस विश्लेषण को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तैयार करने में निवेश के रूप में उपयोग किया (अनुसंधान अध्ययन कोड संख्या 04/ई पी ओ/0/18.1 से 04/ई पी ओ/13.12 तक भाग दो में देखिए) एक अनुसंधान अध्ययन का कार्य समाप्ति पर हैं तथा दूसरे अध्ययन पर पर्याप्त कार्य हो चुका है और एक नए अध्ययन को मंजूरी मिल चुकी है जिस पर अभी काम शुरू किया जाना है (अनुसंधान अध्ययनों के लिए अनुबंध II में क्रमशः कोड संख्या 04/ई पी ओ/18देखें; 04/ई पी ओ/14 और 04/ई पी ओ 115 देखें)।

स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा एकक

एकक स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा के प्रबंध से संबंधित मुद्दों और विभिन्न समस्याओं से परिचित है और स्कूल तथा गैर-औपचारिक शिक्षा से संबंधित स्कूल प्रधानाचार्यों तथा अन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था द्वारा इन समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक कार्य नीति तलाश कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य इन अधिकारियों की व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाना है ताकि वे अपने दायित्वों का अधिक दक्षतापूर्वक और प्रभावशाली ढंग से निर्वाह कर सकें।

भारतवर्ष ने प्रारंभिक शिक्षा में सार्वजनीकरण के कार्यक्रम को बहुत उच्च प्राथमिकता दी है। शिक्षा के अवसरों का सभी के लिए विस्तार करने तथा समाज के वंचित वर्गों के बाल बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने के फलस्वरूप स्वतन्त्रता के बाद से स्कूल शिक्षा का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। औपचारिक स्कूल शिक्षा का गैर औपचारिक, अंशकालिक और एककालिक शिक्षा द्वारा अनपूरण किए जाने के कारण शिक्षा के

प्रशासन मे नए आयाम ग्रहण कर लिए हैं। प्रौढ़ निरक्षरता को दूर करने के कार्यक्रमों पर भी अत्यधिक जोर दिया जा रहा है।

भारतीय राज्यतन्त्र की प्रशासनिक इकाई के रूप में जिले का एक विशेष महत्व है जो कि इसकी पारिस्थितिक संमागता, बोलीगत एकरूपता और ऐतिहासिक निरंतरता की देन है। जिला प्रशासन अधिकारी जिले के निर्णायक स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रशासन का प्रभारी होने के नाते अनेक रूप से भारत में शैक्षिक प्रणाली का मध्य काबला है। एकक तदनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में एक छः महीने के डिप्लोमा कार्यक्रम का आयोजन करता है जिसमें संस्थान में तीन महीने का व्यापक पाठ्यक्रम संबंधी कार्य तथा उसकी नियुक्ति के जिले में तीन महीने का पर्यवेक्षित परियोजना कार्य करवाया जाता है। यह पाठ्यक्रम शिक्षा-सचिवों, शिक्षा निदेशकों/उपनिदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अल्पकालीन संगोष्ठियां/कार्यशालाओं द्वारा अनुपूरित किया जाता हैं। इस साल से आगे के लिए दो डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एकक ने छः कार्यक्रम आयोजित किए (कोड संख्या 05/85 — 86/01 से 05/85-86/06 तक पर दिए गए कार्यक्रम अनुबंध I में देखिए)

उच्च शिक्षा एकक

आजादी के बाद से भारतवर्ष में उच्च शिक्षा पाने के लिए लोगों की मांगें और आकाक्षाएं कई गुना बढ़ गई हैं। उच्च शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालयों, कालेजों और अन्य संस्थाओं की संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। ये सब जनशक्ति को प्रशिक्षित करने और शिक्षित करने का महत कार्य करते हैं। फिर भी कालेजों और विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ज्ञान देने और उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने के कार्य के अतिरिक्त विस्तार क्रियाकलापों के माध्यमों द्वारा समाज को अपेक्षित समर्थन देने और समाज में विकास संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने में अपना समय लगाएं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दूसरे निकायों के सहयोग से एकक ने अपना ध्यान उच्च शिक्षा में प्रमुख व्यक्तियों की क्षमताओं की विकसित करने पर केन्द्रित किया है जैसे कि कालेजों के प्रधानाचार्य, कालेज विकास परिषद के निदेशक, छात्र कल्याण के डीन, विभागों के अध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा विश्वविद्यालयों के अन्य पदाधिकारी। एकक बदलती हुई सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उच्च शिक्षा के संस्थानों की योजना और प्रबंध की आधुनिक तकनीकों पर अधिक जोर देता है। कार्यक्रम निर्णय लेने, पारस्परिक संबंध, कार्यालय प्रबंध, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक तकनीकों द्वारा और पाठ्यक्रमों को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाकर पढ़ाने और सिखाने की प्रक्रिया में सुधार द्वारा तथा पढ़ाने की नई क्रिया विधि शुरू करके और छात्र सेवाओं में सुधार द्वारा उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के साथ जोड़ने और उच्च शिक्षा को संस्थाओं की दक्षता बढ़ाने पर अधिक ध्यान देते हैं। संस्थाओं, शिक्षकों और छात्रों के मूल्यांकन की तकनीकों पर भी विचार-विमर्श किया जाता है।

वर्ष के दौरान एकक ने नौ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए (अनुबंध I में कोड संख्या 06/85-86/01 से 06/85-86/09 पर आर्यक्रम देखिए) दो अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है जिन पर अभी काम शुरू होना है (अनुसंधान अध्ययनों के लिए अनुबंध दो में दी गई कोड संख्या 06/एच० आर० ई० /04 और 06/एच०/आर० ई० 105 देखिए)

उपराष्ट्रीय प्रणाली एकक

शिक्षा के प्रभावशाली योजना और प्रशासन के लिए शिक्षा के स्थानीय आयामों का अध्ययन करना आवश्यक है विशेष रूप से भारत जैसे देश के संदर्भ में जहां कि भिन्न-भिन्न प्रदेशों में संवृद्धि और विकास का अन्तर बहुत महत्वपूर्ण है। एक राज्य के भीतर ही कुछ ऐसे जिले या ब्लाक हैं जो दूसरों की तुलना में कम विकसित हैं और उनकी समस्याएं अपने आप में एकदम अलग हैं। संस्कृतियों और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की अनेकता को देखते हुए तथा यह भी ध्यान रखते हुए कि विकास और योजना स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक विकेंद्रीयकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

तदनुसार जहां तक देश के विभिन्न भागों, में शैक्षिक विकास का प्रश्न है उप-राष्ट्रीय प्रणाली एकक अपने कान जमीन से लगाए रखता है और उन भागों के मूल्यांकन और परिवीक्षण (मानिटरिंग) में सहायता करता है। यह भारत के पांच प्रदेशों जैसे कि उत्तर, उत्तर-पूर्वी, उत्तर-पश्चिमी, दक्षिणी और पश्चिमी के बारे में लगातार विशेषीकृत कार्यक्षेत्र अनुभव और ज्ञान का विस्तार कर रहा है। इसने स्कूल मानचित्रण, संस्थागत योजना और मूल्यांकन, परियोजना की योजना बनाने और प्रबंध सूचना प्रणाली के विशेष संदर्भ सहित सूक्ष्म स्तर पर शैक्षिक योजना में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है।

प्रादेशिक और राज्य स्तर की समस्याओं और आवश्यकताओं के विशेष संदर्भ में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श का आयोजन करने के अतिरिक्त एकक शैक्षिक योजना और प्रबंध में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सफल प्रयोगों और नवाचारों को विचारों और प्रयोगों के माध्यम से दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने शिक्षा विभागों को आधुनिक ढंग से पुनर्गठित करने और शैक्षिक प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में सहायता करता रहा है।

वर्ष के दौरान एकक ने आठ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए (देखिए-अनुबंध-1 कार्यक्रम कोड संख्या 07/85-86/01 से 07/85-86/08 तक)। एकक इस समय 'शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए नौ राज्यों का मूल्यांकन अध्ययन' शीर्षक परियोजना में जुटा हुआ है (देखिए अनुबंध 1-अनुसंधान अध्ययन कोड सं० 07/एस एन एस/05.9 पर)

अंतर्राष्ट्रीय एकक

संस्थान का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक योजना और प्रशासन पर विशेष ध्यान देते हुए प्रादेशिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना रहा है। आत्मनिर्भरता के साधन के रूप में सामूहिक स्वावलंबन के विकास के लिए सूचना, सुविज्ञता के आदान-प्रदान और वर्तमान संसाधनों की भागीदारी को इस दिशा में उठाए गए आवश्यक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

शैक्षिक योजना और प्रशासन के कार्य क्षेत्र में एक राष्ट्रीय शीर्ष संगठन के रूप में कार्य आरंभ करने के बाद से ही संस्थान को यूनेस्को, यू एन डी पी, यूनिसेफ और सीडा तथा स्वयं राष्ट्रीय सरकारों से अनुरोध मिलते रहे हैं जिनके आधार पर संस्थान अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों को सहयोग देता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एकक शैक्षिक योजना और प्रशासन में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और विचारों तथा अनुभवों के आदान-प्रदान के क्षेत्र में, विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देशों में, बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करना है।

एकक पड़ौसी दक्षिण एशियाई देशों और एशिया तथा अफ्रीकी प्रदेश के अन्य देशों को प्रशिक्षण सुविधाएं और परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य इन देशों को शैक्षिक योजना और प्रशासन में सहायता देना है और इस प्रकार यह वरिष्ठ शिक्षा कार्मिकों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ जो कि अपने अपने देशों के अन्य शैक्षिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षक के रूप में काम आ सकते हैं और प्रशिक्षण के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकते हैं।

वर्ष के दौरान एकक ने तीन कार्यक्रम आयोजित किए। (देखिए अनुबंध-1 कार्यक्रम कोड सं० 08/85-86/01 से 08/85-86/01 से 08/85-86/03)।

भाग छः

अकादमिक आधारिक संरचना

संस्थान की अकादमीय आधारिक संरचना में पुस्तकालय, प्रलेखन केंद्र, प्रकाशन एकक, हिन्दी सेल, डेटा बैंक, मानचित्र सेल और इलैक्ट्रानिक डेटा प्रोसैसिंग एण्ड रिप्रोग्राफिक यूनिट (ई डी पी आर यूनिट) शामिल हैं। ये सब संस्थान के बढ़ रहे और बहु-पक्षीय कार्यक्रमों, अनुसंधान तथा अन्य अकादमिक क्रियाकलापों को एक दृढ़ आधार और समर्थन प्रदान करते हैं।

यहां का पुस्तकालय एशियाई क्षेत्र में शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में एक सबसे समृद्ध पुस्तकालयों में से एक होने का दावा कर सकता है। पूरे साल बाधारहित पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाओं की व्यवस्था होने तथा अच्छे पर्यावरण और सुधरी हुई भौतिक सुविधाओं के कारण यह पुस्तकालय कुछ सालों से गम्भीर अध्ययन और सीखने के केन्द्र के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र ने राज्य और जिला स्तर पर शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के बारे में अपने प्रलेखन को और भी बढ़ाया है।

प्रकाशन एकक ने त्रैमासिक ई पी ए बुलेटिन निकालना जारी रखा तथा अपने प्रकाशन कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाया। वर्ष के दौरान अनेक मूल्य सहित, निःशुल्क और अनुसंधान प्रकाशन निकाले गए।

डेटा बैंक, इलैक्ट्रानिक डेटा प्रोसेसिंग एंड रिप्रोग्राफिक एकक, मानचित्रण और हिन्दी सेल ने संस्थान के अकादमिक क्रियाकलापों की मूल्यवान समर्थन देना जारी रखा।

उपर्युक्त इकाइयों के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

I. पुस्तकालय

संस्थान के पास पुस्तकालय में शैक्षिक योजना और प्रशासन तथा अंतर शास्त्रीय विषयों की पुस्तकों का अच्छा संग्रह है। यह न केवल संकाय, अनुसंधान अध्येताओं और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वालों ही की बल्कि अन्तर-पुस्तकालय ऋण प्रणाली के माध्यम से दूसरे संगठनों की भी सेवा करता है। पुस्तकालय में पढ़ने के कमरे की सुविधाएं सब के लिए खुली हैं।

पुस्तकें : समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पुस्तकालय में 1342 प्रलेख जोड़े गए। पुस्तकालय में इस समय यू एन ओ, यूनेस्को, ओ ई सी डी, आई एल ओ, यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों की रिपोर्टों के मूल्यवान संग्रह के अलावा 38,747 पुस्तकों का संग्रह है।

पत्रिका (जरनल) : पुस्तकालय में 303 पत्र-पत्रिकाएं आती हैं, जो मुख्य रूप से शैक्षिक योजना,

प्रशासन, प्रबंध तथा अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों के बारे में होती हैं । इन पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले सभी महत्व-पूर्ण लेख अनुक्रमित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान इन पत्रिकाओं के 300 लेखों की अनुक्रमणिका बनाई गई।

पुस्तकों का परिचालन : समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को, संकाय को और दूसरी संस्थाओं को अंतर-पुस्तकालय ऋण पर 40,209 प्रलेख दिए गए।

अनुसंधान अध्वेताओं ने पुस्तकालय में 9,000 प्रलेखों का उपयोग किया।

समाचार-पत्र कतरनें : पुस्तकों और पत्रिकाओं के अतिरिक्त पुस्तकालय में शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित समाचार पत्रों की कतरनों का विशेष संग्रह किया जाता है। इस समय पुस्तकालय में 150 विषय मिसिलें हैं।

चालू जागरूकता सेवाएं : पखवाड़े के दौरान प्राप्त शिक्षा संबंधी पत्रिकाओं की विषयवस्तु के बारे में पाठकों को चालू जागरूकता सेवा उपलब्ध कराने के लिए पुस्तकालय ने अपना "पीरिओडिकल्स आन एड्यूकेशन : टाइटल्स रिसीव्ड एंड देयर कान्टेन्ट्स" नाम वाला अनुलिपित पाक्षिक प्रकाशन जारी रखा।

पाठकों को उनकी रुचि के महत्वपूर्ण लेखों और नई आई पत्र-पत्रिकाओं के बारे में अद्यतन जानकारी देने के लिए नई आने वाली पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि की मासिक सूचियां भी तैयार की गईं।

सूचना का चयनात्मक प्रसार : पुस्तकालय ने विभिन्न स्रोतों से नए विषय की सूचना को संस्थान के कार्यक्रमों एककों और अनुसंधान परियोजना दल को भेजा जहां उनके लिए वह अधिक उपयोगी सिद्ध होती हैं।

ग्रंथ सूची : इस अवधि के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पुस्तकालय ने ग्रंथ-सूचियां तैयार कीं।

क्षेत्रीय सूचना पुनः प्राप्ति : पुस्तकालय ने यूनेस्को रीजनल आफिस, बैंकाक द्वारा निकाले गए जनरल "एज्यूकेशन इन एशिया एंड द पैसेफिक: रिव्यूज्, रिपोर्ट्स एण्ड नोट्स" में "नोट्स आन एशियन डाक्यूमेंट्स" शीर्षक के अन्तर्गत भारतीय प्रलेखों पर टिप्पणयुक्त संदर्भ तैयार किए।

प्रदर्शनी : वर्ष के दौरान पुस्तकालय ने शिक्षा नीति संबंधी पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन किया।

II. राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र

संस्थान के कार्यक्रमों के लिए एक प्रभावकारी सूचना आधार विशेष रूप से ऐसी सूचना जो कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उपलब्ध कराने की दृष्टि से उक्त केंद्र "सब-नेशनल सिस्टम यूनिट" के निकट सहयोग से कार्य करता है ताकि सूचना और अनुभव के निकासी घर के रूप में अपने कार्य का पालन कर सकें।

प्रलेखन : केंद्र उप-राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतर राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों, जिला प्राधिकरणों और संस्थाओं द्वारा शिक्षा तथा शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित विषयों पर संदर्भ सामग्री

एकत्रित करता है। जिला स्तर पर सूचना एकत्रित करने, संग्रह करने और प्रसारित करने पर केंद्र का खास जोर रहता हैं।

इस समय केंद्र के पास लगभग 6,352 प्रलेख हैं जिनमें राज्य गजैटियर, राज्य जनगणना, पुस्तिकाएं, शिक्षा सर्वेक्षण, राज्य शिक्षा योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, बजट, राज्य विश्वविद्यालय पुस्तिकाएं, सांस्कृतिक ऐतिहासिक, सामाजिक-आर्थिक समस्याओं पर राज्य प्रलेख, मूलभूत स्रोत पुस्तकें तथा ग्रंथ-सूचियां, प्रेस कतरनें, टैक्नो-आर्थिक तथा नमूना सर्वेक्षण, जिला गजेटियर, जिला जनगणना पुस्तिकाएं, वार्षिक योजनाएं, शिक्षा योजनाएं, जिला उधार योजनाएं, लीड बैंक रिपोर्टें, जिला नमूना सर्वेक्षण, जिला शिक्षा सर्वेक्षण, जिला सांख्यिकीय पुस्तिकाएं, गांव तथा ब्लाक स्तर योजनाएं और अध्ययन, अनुसंधान तथा परियोजना रिपोर्टें, साधन वस्तुसूची अध्ययन, टैक्नो-आर्थिक सर्वेक्षण शामिल हैं।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से समाचार : केंद्र 14 प्रादेशिक समाचार-पत्रों के लिए चंदा देता है जिनमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में समाचार होते हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में शैक्षिक समाचार देने वाले इन अखबारों से प्रेस करतनों की मिसिल बनाकर केंद्र अपने पास संदर्भ के लिए रखता है। इन अखबारों में छपी खबरों के आधार पर और विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा समाचार संकलित किए जाते हैं और हर महीने प्रकाशित किए जाते हैं।

प्रलेखन और सूचना सेवा :

1. अनुसंधान कार्यकर्ताओं और संकाय सदस्यों के लिए प्रसार-सूचना (एड डी आई) का चयन;
2. प्रलेखन सूचियों; और
3. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए टिप्पणयुक्त ग्रंथ सूचियों के संकलन।

उपर्युक्त तीन माध्यमों से प्रलेखन केंद्र शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में नवाचारी अनुभवों तथा नई प्रगतियों से संबंधित सूचना प्रसार करता है।

III. प्रकाशन एकक

संस्थान का एक मुख्य उद्देश्य शोधपत्रों, पत्रिकाओं और प्रकाशनों का मुद्रण और प्रकाशन करना तथा विशेष रूप से संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन के बारे में पत्रिका प्रकाशित करना है।

वर्ष के दौरान प्रकाशन एकक ने शैक्षिक योजना और प्रशासन पर त्रैमासिक ई पी ए बुलेटिन प्रकाशित करना जारी रखा। एकक ने मूल्य वाले प्रकाशन, नि:शुल्क प्रकाशन, अनुसंधान प्रकाशन और प्रासंगिक शोध-पत्र शृंखलाओं का भी प्रकाशन किया।

(क) मूल्य वाले प्रकाशन

क्रम संख्या 1, 2 और 3 वाले प्रकाशन प्रेस में थे और क्रम संख्या 4, 5, और 7 प्रकाशन के लिए तैयार थे जैसा कि नीचे दिया गया है।

पुस्तकें

1. एड्यूकेशनल प्लानिंग—ए लांग टर्म पर्स्पेक्टिव प्रोफेसर मूनिस रजा द्वारा संपादित
2. स्कूल एंड इन्स्पेक्शन सिस्टम—ए मार्डन एप्रोच लेखक डा० आर० पी० सिंगल
   डा० एन० एम० भागिया
   श्री टी० के० डी० नायर
   और
   श्री वी० ए० कल्पांडे
3. फाइनेन्सिअल कोड फार ब यूनिवर्सिटी सिस्टस—लेखक श्री एम० एल० सोबती
4. 'कास्ट आफ सप्लाई आफ एड्यूकेशन एट माइक्रो लेवल : ए केस स्टेडि आफ टू एड्यूकेशन क्लस्टर्स इन द डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, हरियाणा' लेखक डा० जे० बी० जी० तिलक
5. 'मोबिलाइजेशन आफ एडिशनल रिसोर्सेज फार एड्यूकेशन—ए स्टडी आफ सर्टेन स्टेट्स इन इंडिया' लेखक डा० सी० बी० पद्मनामन
6. 'आर्गेनाइजेशन हिस्ट्री आफ ब मिनिस्ट्री आफ एड्यूकेशन' लेखक श्री ए० मैथ्यु
7. 'रिसोर्सेज फार एड्यूकेशन इन इंडिया' लेखक डा० जे० बी० जी० तिलक और डा० एन० वी० वर्गीज

(ख) निःशुल्क प्रकाशन

1-2 एन्युअल रिपोर्ट फार द ईयर 1984-85 (अंग्रेजी और हिन्दी अनुवाद)

3-4 ई० पी० ए० बुलेटिन अप्रेल और जुलाई, 1985, खण्ड-8, संख्या 1 और 2 तथा अक्तूबर, 1985 और जनवरी, 1986 खण्ड-8, संख्या 3 और 4

5 रिपोर्ट आफ कन्सल्टेटिव मीटिंग आन द ट्रेनिंग आफ कैरिकुलम डेवेलेपर्स, टीचर एड्युकेटर्स एंड एड्यूकेशन प्लानर्स इन एन्विरान्मेन्टल एड्यूकेशन (फरवरी 11-15, 1985)

(ग) अनुलिपिकृत माइमिओग्राफ्ड प्रकाशन

संस्थान ने 20 अनुसंधान अध्ययनों, 2 प्रासंगिक शोध-पत्रों और संस्थान द्वारा 1985-86 के दौरान आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्टों के अनुलिपि किए हुए प्रकाशन निकाले।

IV. हिंदी कक्ष

हिन्दी कक्ष नीपा सरकारी भाषा कार्यान्वयन समिति के निर्देशन में कार्य करता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कक्ष ने संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य अकादमिक क्रियाकलापों को बहुमूल्य योगदान दिया।

हिन्दी कक्ष के कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में सेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स/वर्कशाप्स/सेमिनार्स फार 1985-86, मेमोरेन्डम ऑफ एशोसिएशन एण्ड रुल्स ऑफ नीपा, दी स्कूल डिस्ट्रेस-ए केस, एण्ड, ए मॉडल

इन्स्पेंटर' बाई डॉ० आर० पी० सिंघल, सिस्टम्स एप्रोच टु इन्स्टीट्यूशनल प्लानिंग बाई एम० एम० कपूर; ग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स-एन एप्रोच टु इन्स्टीट्यूशनल सेल्फ-इवेल्यूएशन बाई श्री वी० ए० कल्पांडे; ग्राम शिक्षा समाचार; क्यूशचनेयर्स ऑफ इवेल्यूएशन फॉर नान-फार्मल एड्यूकेशन फार युनिवर्सेलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एड्यूकेशन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई सावित्री बाई फुले फास्टर पेरेन्ट स्कीम, और एन्यूअल रिपोर्ट फार 1984-85 के हिन्दी अनुवाद शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जिला मुड़गांव की क्रिया अनुसंधान परियोजना के उपयोग के लिए कुछ अंग्रेजी सामग्री को भी हिन्दी में अनुवाद किया गया।

हिन्दी कक्ष ने कार्यक्रमों की अनेक रिपोर्टें हिन्दी में तैयार कीं जैसे कि हरियाणा के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (2-4-85 से 6-4-85), ग्राम विकास समिति, मेवात के सामाजिक और आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका पर एक संगोष्ठी (24-4-85), उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के संस्थानिक योजना तथा मूल्यांकन पर कार्यशाला (31-5-85), वाराबंकी जिले (उत्तर प्रदेश) के ब्लाक में गैर औचापरिक और औपचारिक शिक्षा प्रणाली के सन्दर्भ में यू० ई० ई० के कार्यान्वियन कार्यक्रम का अध्ययन, पुन्हाना से चुने गए 20 अध्यापकों के लिए कार्यशाला, स्कूल के प्रधानाचार्यों के लिए संस्थान संगठन (म० प्र०) बी० टी० आई०, कांकर के अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित।)

हिन्दी कक्ष ने नई शिक्षा नीति पर व्यक्तिगत पत्रों, जिला, प्रभाग और राज्य समिति रिपोर्टों की विषयवस्तु के विश्लेषण में भी सहायता दी।

हिन्दी कक्ष ने शासकीय पत्राचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने में भी सहायता दी और हिन्दी भाषी राज्यों के साथ हिंदी में पत्राचार किए जाने की व्यवस्था की।

V. डेटा बैंक

डेटा बैंक के मुख्य कार्य नीचे दिए गए हैं:

(i) संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं को डेटा एकत्रित, संसाधित और विश्लेषित करने की प्रक्रिया में सहायता देना,

(ii) नीपा में अपनाई गई विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं में सम्बन्धित डेटा के कंप्यूटरीकरण की सुविधा देना,

(iii) जिला स्तर पर शैक्षिक योजना के लिए पर्याप्त जिला स्तर डेटा आधार तैयार करना और,

(iv) कंप्यूटरीकृत डेटा को एक क्रमबद्ध रूप में भण्डारित रखना ताकि भविष्य में काम में लाए जाने के लिए इसकी पुन: प्राप्ति हो सके।

कंप्यूटरीकरण की दृष्टि से राष्ट्रीय इन्फोर्मेटिक्स केन्द्र, नई दिल्ली में स्थित साइबर कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने वालों में नीपा भी है। नए एन० ई० सी० सुपर कंप्यूटर सिस्टम को देखते हुए डेटा को भी इस नए स्थल पर स्थानांतरित करना आवश्यक हो जाएगा। नीपा ने एक माइक्रो-कंप्यूटर भी हासिल कर लिया है। यह छोटे डेटा-आधार तैयार करने में सहायता देगा जो प्रशिक्षण कार्य के लिए व्यापक रूप से काम में लाने के साथ-साथ शैक्षिक योजना तथा प्रबन्ध में कुछ अनुरूपण अभ्यास के कार्य हाथ में लेने के लिए भी सहायक

सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त कुछ डेटा आधार को नीपा में लगे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि उपयोगकर्ता के लिए और अधिक सुगमता रहे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा इस सिलसिले में आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों के लिए भी नीपा द्वारा अपनाए गए विभिन्न प्रयोगों से सम्बन्धित डेटा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त डेटा-आधार तैयार किया गया।

VI. मानचित्रण कक्ष

कक्ष ने मानचित्रों, आरेखों, चार्टों और पारदर्शी चित्रों के माध्यम से चित्रालेखी डेटा निरूपण में सहायता देकर अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में तथा नई शिक्षा नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वर्ष के दौरान विभिन्न अनुसंधान अध्ययनों के लिए 150 मानचित्र और आरेख तैयार किए गए। भविष्य और वर्तमान के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विशेष चित्रालेखी पारदर्शी चित्र भी तैयार किए गए। 'ए स्टडी ऑफ आप्टिमम टीचर-प्यूपिल रेशियों पर अनुसंधान परियोजना, 'इण्डियन एड्यूकेशन इन द ईयर 2000-ए लांग टर्म पर्स्पेक्टिव,' 'पुन्हाना ब्लाक एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट,' हिन्दी और अंग्रेजी वार्षिक रिपोर्ट तथा ई० पी० ए० बुलेटिन आदि के लिए आलेख (ग्राफ) और मानचित्र भी बनाए गए।

इसके अतिरिक्त मानचित्रण कक्ष द्वारा निकाले गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रासंगिक शोध-पत्रों आदि में निवेश के रूप में 110 मानचित्र, चार्ट, पारदर्शी चित्र और अन्य पोस्टर भी तैयार किए गए।

VII. इलैक्ट्रानिक डेटा प्रोसेसिंग और रिप्रोग्राफिक एकक (ई डी पी आर)

एकक शैक्षिक योजना और प्रशासन के लिए पर्याप्त डेटा आधार उपलब्ध कराने और प्रशासन तथा प्रबन्ध के क्षेत्र में आधुनिक इलैक्ट्रानिक उपस्कर के उपयोग तथा अनुप्रयोग में सहायता देने में जुटा हुआ है। एकक विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वालों के लिए कंप्यूटर निदर्शन का आयोजन भी करता है ताकि उन्हें शिक्षा योजना और प्रशासन में कंप्यूटर के उपयोग और कार्य के बारे में जानकारी मिल सके। ई पी डी आर एकक ने अपनी डेटा प्रोसेसिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डेटा बैंक के निकट सहयोग से काम किया।

(क) शब्द संसाधन

एकक में लगाए गए उपस्कर का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

1. 64 के बी मेमोरी सहित एच सी एल सिस्टम 2, प्रत्येक 2 एम बी की 2 डिस्क ड्राइब्स, 80 के० बी० वाली 1 डिस्क ड्राइव और 35 सी पी एस गति वाला एक 132 कालम लेटर क्वालिटी प्रिंटर।
2. 64 के बी मेमोरी सहित एच सी एल वर्क हार्स, एच सी एल सिस्टम-2 के अनुरूप प्रत्येक 200/80 के बी की दो डूअल डेंसिटी डिस्क ड्राइब्स।
3. 256 के बी मेमोरी वाला दो टर्मिनलों सहित एच सी एल वर्क हार्स 2, एक कठोर डिस्क ड्राइव, 80/200/400/800 के बी की एक मिनी फ्लोपी ड्राइव और 150 सी पी एस की गति वाला एक 132 कालम डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर।

4. एक डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर सहित 2 बी बी सी क्लास कंप्यूटर।

शब्द संसाधन पर पृष्ठभूमि निर्माण सामग्री के विभिन्न खण्ड निकाले गए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रतिपादन के काम में लाए गए। इसके अलावा शब्द प्रोसेसर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पठन सामग्री/रिपोर्टें और विभिन्न शोध-पत्र निकाले गए।

वेतन बिल के कंप्यूटरीकरण के साथ-साथ कंप्यूटरीकृत डेटा प्रोसेसिंग में काम आने के लिए प्रशासन और लेखा के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अनेक पैकेज भी विकसित किए गए हैं तथा वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वत: स्वीकृति देना भी बरकरार रखा गया।

(ख) रिप्रोग्राफी

1. ओलम्पिया फोटोकॉपीयर
2. यू बिक्स किल्बर्न 1600 एम आर फोटोकॉपीयर
3. मोदी जिरोक्स फोटोकॉपीयर।

वर्ष के दौरान एक तीसरा फोटोकॉपीयर खरीदा गया जिसमें वर्धन की अतिरिक्त सुविधा है। फोटोकॉपीयर को विभिन्न रिपोर्टों, पठन-सामग्री, लेखों की कई गुना प्रतियां निकालने और अन्य फुटकर कार्यों के लिए व्यापक रूप से काम में लाया गया।

प्रशासन और वित्त

प्रभागीय ढाँचा

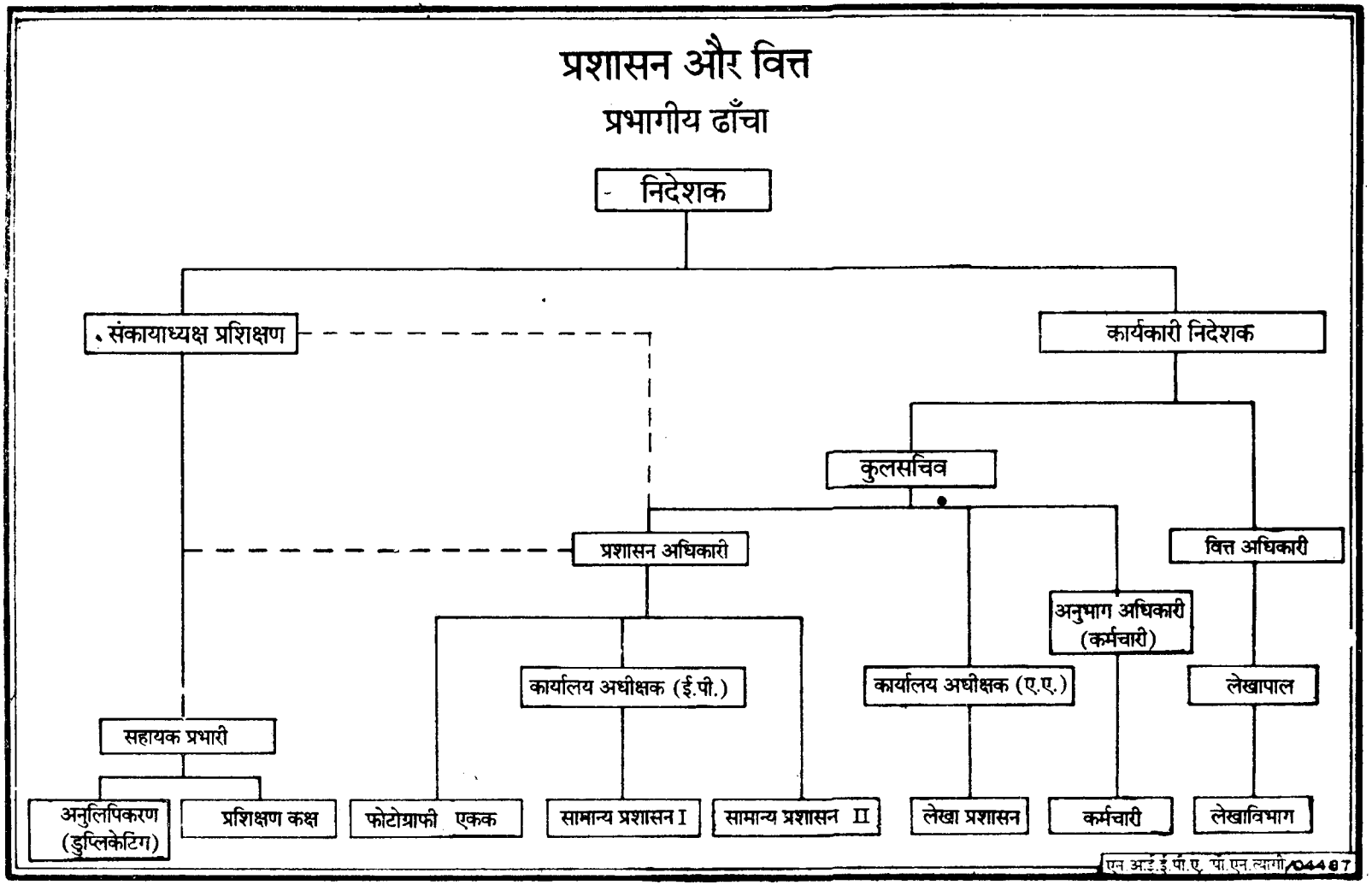

एन.आई.ई.पी.ए. पी.एन.त्यागी/04487

भाग सात

प्रशासन और वित्त

संस्थान को भारत सरकार की ओर से पूरी तरह वित्तीय सहायता मिलती है। भारत सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष इसका प्रधान होता है। भूतपूर्व संघीय शिक्षा मंत्री श्री के० सी पंत द्वारा पद-त्याग के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा राज्य-मंत्री श्रीमती सुशीला रोहतगी ने 14 नवम्बर, 1985 को अध्यक्ष पद सम्भाला।

संस्थान के नीति निर्धारकों में परिषद्, कार्यकारिणी समिति और वित्त समिति सम्मिलित हैं। संस्थान के शीर्ष निकाय के रूप में परिषद् ने शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर के मूर्धन्य कार्यपालकों और ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों को रखा हुआ है ताकि वे संस्थान को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मार्ग दिखा सकें और संस्थान के सभी मामलों में सामान्य पर्यवेक्षण कर सकें। संस्थान के प्रशासन और प्रबन्ध के मामलों की देखभाल कार्यकारी समिति करती है। लेखा और बजट की छानबीन करने और दूसरे वित्तीय मामलों में एक वित्तीय समिति इस कार्यकारी समिति की सहायता करती है। निदेशक महोदय परिषद के पदेन उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी तथा वित्तीय समितियों के अध्यक्ष होते हैं। रजिस्ट्रार महोदय परिषद् कार्यकारिणी अथवा वित्तीय समितियों के सचिव का कार्य करते हैं।

कार्यकारिणी समिति ने प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा अन्य अकादमिक गतिविधियों के बारे में सिफारिशें करने के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति और संस्थान द्वारा निकलने वाले प्रकाशनों के सभी मामलों के बारे में प्रकाशन सलाहकार समिति का गठन किया है। रजिस्ट्रार और प्रकाशन अधिकारी क्रमशः कार्यक्रम सलाहकार समिति तथा प्रकाशन सलाहकार समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है जो कि संस्थान का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता है। प्रशासन और वित्त के मामलों में कार्यकारी निदेशक उसकी सहायता करता है। रजिस्ट्रार और वित्तीय अधिकारी क्रमशः प्रशासन प्रभाव तथा लेखा अनुभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रकाशन अधिकारी प्रकाशन एकक का अध्यक्ष होता है।

नीति ढांचे के अंग

परिषद्

संस्थान का शीर्ष निकाय एक परिषद है जो अध्यक्ष के अधीन होती है। संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति करना और संस्थान के सभी मामलों की सामान्य देख-रेख करने का कार्य परिषद् करेगी।

नीपा का निदेशक इसका उपाध्यक्ष होता है। परिषद् के अन्य सदस्य इस प्रकार हैं : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, भारत सरकार के चार सचिव (शिक्षा, वित्त, योजना आयोग और कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग), राष्ट्रीय शिक्षा-अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के निदेशक, छः शिक्षा सचिव (पांच राज्यों से और एक केन्द्र शासित प्रदेश से), छः प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य, और नीपा संकाय का एक सदस्य। 31 मार्च, 1986 तक के परिषद् के सदस्यों की सूची परिशिष्ट एक में दी गई हैं।

परिषद् की सातवीं बैठक 10 मार्च, 1986 को हुई थी।

कार्यकारिणी समिति

संस्थान के मामलों का प्रशासन और प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति करती है। संस्थान के निदेशक इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा इसमें सचिवों, शिक्षा मंत्रालय, वित्त तथा योजना आयोग के नामिती; किसी राज्य का एक शिक्षा सचिव, एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् और नीपा के कार्यकारी निदेशक सम्मिलित है। 31 मार्च, 1986 तक कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट 2 में दी गई है।

कार्यकारिणी समिति की बाईसवीं और तेइसवीं बैठकें क्रमशः 26 जून, 1985 और 10 फरवरी 1986 को हुईं।

वित्तीय समिति

अध्यक्ष संस्थान के निदेशक की पदेन अध्यक्षता में एक वित्तीय समिति नियुक्त करता है जिसमें पांच सदस्य होते हैं। इसमें वित्तीय सलाहकार तथा परिषद के अन्य ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति जरूरी समझता है। यह समिति लेखा और बजट आकलन की छानबीन करती है और नए व्यय तथा अन्य वित्तीय मामलों के प्रस्तावों पर कार्यकारिणी समिति को अपनी सिफारिशें देती हैं। 31 मार्च, 1986 की वित्तीय समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट 3 में दी गई हैं।

वर्ष के दौरान वित्तीय समिति की भी दो बैठकें 26 जून, 1985 और 10 फरवरी, 1986 को हुई।

कार्यक्रम सलाहकार समिति

कार्यक्रम सलाहकार समिति प्रशिक्षण, अनुसंधान और दूसरे कार्यक्रमों के बारे में कार्यकारिणी समिति को सिफारिशें भेजती हैं और संस्थान के कार्य के अकादमिक पहलू की जांच करती हैं। इसमें पदेन अध्यक्ष के रूप में निदेशक, शिक्षा मंत्रालय, योजना आयोग के प्रतिनिधि तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित अन्य सदस्य होते हैं। नीपा के रजिस्ट्रार इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। 31 मार्च, 1986 को कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-4 में दी गई है।

कार्यक्रम सलाहकार समिति की बारहवीं और तेरहवीं बैठकें क्रमशः 21 जून, 1985 और 28 जनवरी 1986 को हुई।

प्रकाशन सलाहकार समिति

प्रकाशन सलाहकार समिति संस्थान द्वारा निकाले जाने वाले प्रकाशनों से संबंधित सभी मामलों और उनसे

जुड़ी हुई सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के समन्वय के बारे में कार्यकारिणी समिति को अपनी सिफारिशें भेजती हैं। प्रकाशन अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है। 31 मार्च, 1986 तक के प्रकाशन सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-5 में दी गई है।

प्रकाशन सलाहकार समिति की तीसरी और चौथी बैठक क्रमश: 24 जून, 1985 तथा 4 फरवरी, 1986 को हुई थीं।

स्टाफ संख्या और परिवर्तन

31 मार्च, 1986 को वर्ष के दौरान स्टाफ की काडर संख्या 164 थी। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त तारीख को 43 परियोजना स्टाफ सदस्य थे।

'शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए 9 राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए 9 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए प्रयोगात्मक परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन' नामक परियोजना में डाक्टर एस० क्यू० ए० नक़वी और कुमारी प्रमीला यादव की 16-5-1985 से परियोजना सह-अध्येता के रूप में नियुक्ति की गई।

'शिक्षा की दृष्टि से 9 पिछड़े हुए राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा सार्वजनीकरण के लिए 9-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए प्रयोगात्मक परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन' नामक परियोजना में श्री जी० खुराना की 1-7-1985 से परियोजना अध्येता के रूप में नियुक्ति की गई।

उत्तरी पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग के अनुवर्ती शिक्षा केन्द्र में रीडर-इंचार्ज श्री सी० पी० तिवारी को उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी हो जाने पर 8-7-1985 से उनके मूल विश्वविद्यालय में वापस भेज दिया गया।

वर्ष 2000 में शिक्षा नामक परियोजना में श्री एम० एम० खान को 12-8-1975 से कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में रखा गया।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के भूतपूर्व सम-कुलपति प्रोफेसर के० एम बहाउद्दीन ने 28-10-1985 से संस्थान में परामर्शद के रूप में कार्यभार सम्भाला।

महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग के उपनिदेशक श्री वी० ए० कल्पांडे को उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी हो जाने के बाद 22-11-1985 से उनके मूल कार्यालय में वापस भेज दिया गया।

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक श्री शब्बीर अहमद को प्रतिनियुक्ति काल-समाप्ति के बाद 30-12-1985 से उनके मूल कार्यालय में वापस भेज दिया गया।

मानव संसाधन विकास

अकादमिक तथा अन्य प्रकार के स्टाफ को सेवाकाल में प्रशिक्षण देना मानव संसाधन विकास का महत्वपूर्ण तत्त्व माना गया। इस नीति के पालन में संस्थान के संकाय (फैकल्टी) और दूसरे स्टाफ सदस्यों को उनकी व्यावसायिक संवृद्धि तथा विकास के लिए उन्हें सेवाकाल के दौरान ही देश में तथा विदेश में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

लेखाकार श्री चेरियन थामस, सहायक श्री शुभराम चौधरी, और उच्च श्रेणी लिपिक कुमारी उज्जवल भट्टाचार्य ने 1 अप्रैल, 1985 से 15 मई, 1985 तक माइक्रोशोफ्ट सिस्टम कन्सल्टेन्ट्स, लाजपतनगर, नई दिल्ली में कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स (बेसिक) में भाग लिया।

नीपा के प्रलेख अधिकारी श्री एन० बी० कन्डयाल ने 25 मार्च, 1985 से 29 अप्रैल, 1985 तक बैंकाक (थाईलैंड) स्थित एशिया और पैसेफिक में शिक्षा के लिए यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय के पुस्तकालय के प्रलेखीकरण तथा सूचना सेवाओं में ए पी ई आई डी शिशिक्षु (इंटरनशिप) कार्यक्रम में भाग लिया।

सह-अध्येता डा० (सुश्री) के० सुजाता, वरिष्ठ तकनीकी सहायक कुमारी जयश्री जलाली, वरिष्ठ तकनीकी सहायक कुमारी मीना श्रीवास्तव ने इतालवी सरकार छात्रवृत्ति के अंतर्गत इन्स्टीट्यूटो, पेरला कोआपरेजीआन यूनिवर्सिटरिया, रोम, इटली द्वारा आयोजित विकास प्रशासन पर एक छः महीने के उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम में नबम्बर, 1984 से मई, 1985 तथा नवम्बर, 1985 से मई, 1986 तक भाग लिया।

सह अध्येता डा० एन० वी० वर्गीस ने आई आई ई पी, पेरिस में शिक्षा योजना और प्रशासन में बीसवें प्रशिक्षण कार्यक्रम में 12 दिसम्बर, 1984 से 13 जुलाई, 1985 तक भाग लिया। पुस्तकालय अध्यक्ष कुमारी निर्मला मल्होत्रा ने तकनीकी सहकारिता शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाफबरो विश्वविद्यालय, यू० के० में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 7 अक्तूबर, 1985 से 9 मई, 1986 तक भाग लिया।

समूह बचत संबद्ध बीमा योजना

भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बचत संबद्ध बीमा योजना जो कि केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना 1980 के पैटर्न पर केंद्रीय और राज्य स्वायत्त संगठनों में अभी हाल ही में लागू की गई, मार्च, 986 से संस्थान में भी शुरू कर दी गई है तथा संस्थान के स्टाफ के सभी पात्र-सदस्यों ने योजना में शामिल होने की सहमति दी है। संस्थान की सेवा में आने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य होगी। योजना के अन्तर्गत ए० बी० सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों को क्रमश: रु० 80,000.00, रु० 40,000.00, रु० 20,000.00 और रु० 10,000.00 की बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। योजना के अन्तर्गत की गई सुरक्षा के दौरान यदि दुर्भाग्यवश किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो आश्रितों की जीवन बीमा का लाभ मिलेगा। सदस्य की कोटि के अनुसार मिलने वाले इस लाभ के साथ-साथ सदस्य के बचत निधि खाते में जमा की गई राशि भी ब्याज सहित आश्रित को मिलेगी। औपचारिक सेवा-निवृत्ति की तारीख तक जीबित रहने अथवा त्याग-पत्र द्वारा समयपूर्व वापसी अथवा सेवा समाप्ति के मामले में सदस्य के बचत निधि खाते में इकट्ठी हुई रकम ब्याज सहित उसको देय होगी। इस योजना के लागू होने से नीपा के स्टाफ सदस्यों को असामयिक मृत्यु के प्रति पर्याप्त सुरक्षा बीमा मिला है और उनके परिवार जनों के लिए यह एक अच्छा कल्याणकारी उपाय है।

नीपा के नियम-विनियम

नीपा के नियम-विनियम समीक्षाधीन है और वर्तमान नियम-विनियम को अद्यतन बना कर उनमें, संशोधन करके तथा उनको समेकित करके एवं एमिरिटस प्रोफेसर, राष्ट्रीय अध्येताओं को अभ्यागत अध्येताओं के पद के लिए नियुक्ति हेतु नए प्रावधान, योग्यता प्रोन्नोति योजना, अकादमिक अवकाश तथा सेवेटिकल अवकाश पर लागू होने वाली निबंधन और शर्तों आदि को सम्मिलित करके सेवा विनियमों का मसौदा तैयार किया गया है। मसौदा सेवा विनियमों को संस्थान के विभिन्न एककों (यूनिटों) में परिचालित किया गया है और एककों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतिमरूप दिए जाने के बाद इन विनियमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा इस कार्य के लिए गठित समिति के पास विचारार्थ भेजा जाएगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

निदेशक से कार्यकारी निदेशक, संकाय-अध्यक्ष (डीन) प्रशिक्षण और एककों के अध्यक्षों तक तथा रजिस्ट्रार से प्रशासन अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और कार्यालय अधीक्षकों तक प्रशासनिक और अकादमिक कार्यकर्ताओं के विभिन्न स्तरों पर कार्यात्मक और विकेन्द्रीकृत आधार पर वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों के व्यापक तौर पर पुनर्प्रत्यायोजन से कार्य त्वरित गति से हुआ है, गत्यावरोध और विलम्ब दूर हुआ है तथा परिणामस्वरूप निर्णय शीघ्रता से लिए गए हैं।

अर्थ-व्यवस्था

पठन/भूमिका सामग्री, रिपोर्टों, व्यक्तिगत शोधपत्रों के अनुलिपिकरण, आवरण पृष्ठों के मुद्रण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों और अन्य गतिविधियों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भाग लेने वालों को लेखन सामग्री के विभिन्न मद देने के लिए तय किए गए मानकों के प्रवर्तन से लेखन सामग्री के उपयोग में पर्याप्त बचत की गई है जो कि संस्थान में खर्च की प्रमुख मद है।

लेखा और प्रशासन का आधुनिकीकरण

प्रशासन और लेखा के सम्भावित क्षेत्रों को कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत लाने के व्यवस्थित प्रयास किए जा रहे हैं। वार्षिक वेतन-वृद्धि निकालने के तरीके का कम्प्यूटरीकरण हो जाने से वार्षिक वेतन-वृद्धि स्लिप देना खत्म कर दिया गया है और वेतन-वृद्धि दिए जाने में विलम्ब होने की संभावना समाप्त हो गई है। संवर्ग (काडर) और योजना स्टाफ की संख्या का कम्प्यूटरीकरण द्वारा तैयार किए गए मासिक विवरण से संवर्ग और परियोजना स्टाफ की नियमित संयमित समीक्षा करने में सहायता मिली है तथा इसके फलस्वरूप संवर्ग योजना और प्रबंध बेहतर हुए है। वित्तीय लेखा और तालिका (इन्वेन्ट्री) नियंत्रण पद्धति के कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रोग्राम विकसित किए गए।

कार्यक्रम रिपोर्ट बनाना

संस्थान में होने वाले महत्वपूर्ण विकासकार्यों और क्रियाकलापों की एक त्रैमासिक समीक्षा (अनुलिपियां बना कर) निकाली जाती हैं। इसमें त्रिमास के दौरान किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संस्थान द्वारा अपनाए गए अनुसंधान अध्ययनों की स्थिति और प्रगति तथा अन्य क्रियाकलापों के बारे में सूचना दी जाती है जैसे कि नीपा वार्तागोष्ठी, सलाहकारी, परामर्शदायी और समर्थनकारी सेवाएं, प्रकाशन, पुस्तकालय, प्रलेखीकरण, स्टाफ परिवर्तन, सेवा में रहते प्रशिक्षण, विभिन्न नीति निर्धारक निकायों और कार्यदलों की बैठकों के बारे में रिपोर्ट आदि।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए ढंग से तैयार की गई मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाती हैं।

कार्यालय उत्पादकता और रिपोर्ट तैयार करना

कार्य के शीघ्र निपटान और कार्यालय उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से संस्थान में कार्यालय रिपोर्ट तैयारकरने की एक प्रभावकारी पद्धति को संस्थानुकूल बनाने के लिए एक नवाचारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसका एक व्यापक आधार है ताकि कार्यालय के सभी कार्यक्षेत्र उसमें आ सकें जैसे कि प्राप्तियों के निपटान का परिवीक्षण करने के अतिरिक्त कार्मिक, पूर्ति तथा सेवाएं, सम्पदा और निर्माण। कार्यालय रिपोर्ट बनाने की पद्धति को पूरी तरह से लागू करना सम्भव नहीं रहा है किन्तु इसके सीमित रूप से प्रचालन द्वारा भी कार्यालय कार्य में प्रत्यक्ष रूप सें दिखाई देने वाला सुधार हुआ है और विलम्ब दूर हुआ है।

नीपा परिसर

निदेशक के निवास का निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है और पूरा होने वाला है। टाईप-II के 8 और टाईप-III के 8 मकानों (क्वार्टर्स) के निर्माण में भी प्रगति हो रही है।

इलैक्ट्रानिक डेटा प्रोसेसिंग और अन्य प्रशासन-एककों, लेक्चर हालों और संगोष्ठी कक्षों, बिजली की अबाधित पूर्ति देने की दृष्टि से विशेष रूप से संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य शैक्षणिक कार्यकलापों की दक्षता बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान रु० 1.83 लाख की अनुमानित लागत से एक जनेरेटर सेट संस्थापित करने की मंजूरी दी गई।

संस्थान को कार्यालय आवास की भयंकर कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को आंशिक रूप से सुलझाने की दृष्टि से वर्ष के दौरान 13.46 लाख रुपए की अनुमानित लागत से तीसरी मंजिल की मंजूरी दी गई। इसका निर्माण शीघ्र शुरू होने की संभावना है। संस्थान की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) से निवेदन किया गया है कि संस्थान के क्षेत्र में और इससे एकदम सटा हुआ लगभग 15-20 एकड़ का अतिरिक्त क्षेत्र उपलब्ध कराए।

छात्रावास

संस्थान द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम निवासीय होते हैं। भाग लेने वालों को एक सात मंजिला छात्रावास में ठहराया जाता हैं जिसमें संलग्न स्नानागार वाले पूरी तरह सज्जित 48 कमरे हैं। मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को ठहराने के ख्याल से पहली मंजिल के आठ वातानुकूलित कमरों को वर्ष के दौरान नया रूप दिया गया। पुराने साज-समान को बदल कर नया लगाया गया। हरेक कमरे में दो पलंग सजाए गए।

यदि एक व्यक्ति रहता है तो उच्च कोटि की सुबिधाओं वाले कमरों का किराया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु० 100.00 और यदि इन कमरों सें दो व्यक्ति रहते हैं तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से रु० 75.00 है। दूसरे कमरों का किराया प्रति भागीदार रु० 6.00 और गैर भागीदार के लिए रु० 15.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 2.37 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष छात्रावास से 2.06 लाख रुपए की आय हुई।

छात्रपाल (वार्डन) के लिए निवासगृह संकाय अतिथि और भंडार कक्ष बनाने, बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार भोजन हाल की क्षमता बढ़ाने और छात्रावास के रसोईघर में उच्च कोटि की सुविधाएं प्रदान करने का निश्चय किया गाया है।

वित्तीय

1984-85 के दौरान 74.39 लाख रुपए (31.44 लाख रुपए गैर योजना के अन्तर्गत और 42.95 लाख रुपए योजना के अन्तर्गत) के अनुदान की तुलना में 1985-86 वर्ष के दौरान संस्थान को 85.58 लाख रुपए (60.41 लाख रुपए गैर-योजना के अन्तर्गत और 25.17 लाख रुपए योजना के अन्तर्गत) का अनुदान मिला। 95.56 लाख रुपए की कुल आय की तुलना में जिसमें छात्रावास और विविध आय के 7.21 लाख रुपए तथा 2.56 लाख रुपए का आदि शेष सम्मिलित हैं वर्ष के दौरान सरकारी अनुदान में से कुल 89.63 लाख रुपए खर्च हुए। इसके अलावा संस्थान को कार्यक्रम चलाने और अनुसंधान अध्ययत जारी रखने के लिए शिक्षा मंत्रालय, आई सी एस एस आर, यूनेस्को आदि से 18.47 लाख की निधि प्राप्त हुई। प्रायोजित कार्यक्रमों और अध्ययनों के लिए 5.52 लाख रुपए के आदि शेष सहित 23.99 लाख रुपए की कुल आय की तुलना में 1984-85 के दौरान इन पर 17.25 लाख रुपए की राशि खर्च हुई।

अनुबंध

अनुबन्ध एक

प्रशिक्षण कार्यक्रम

01/ई. पी. एल./शैक्षिक योजना एकक

1. 01/85/86/01 दीर्घकालीन शैक्षिक योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम (5 मार्च से 31 अगस्त 1985)

भारत-थाईलैंड सांस्कृतिक विनिमय के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए श्री चंतारत कौतकम, शिक्षक, शैक्षिक योजना प्रभाग, शिक्षा मंत्रालय, थाईलैंड के लिए एक दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के उद्देश्य, भाग लेने वालों को, शैक्षिक योजना की पद्धति का विकास करने, शैक्षिक योजना की संकल्पनाओं से परिचित कराने; दीर्घकालीन शैक्षिक योजना की प्रणालियों और समस्याओं से सम्बन्धित ज्ञान प्रदान करने और साथ ही दीर्घकालीन शैक्षिक योजना की कम-से-कम एक प्रणाली में दक्ष करने के थे। इसके मुख्य विषय शैक्षिक योजना के लिए सांख्यिकी, विकासशील देशों में शिक्षा, शैक्षिक योजना : संकल्पना और उपागम, शैक्षिक योजना में मात्रात्मक तकनीक, शैक्षिक योजना में पद्धति विश्लेषण, शैक्षिक पद्धतियों का प्रबन्धन, शिक्षा पद्धति में वित्तीय योजना और शैक्षिक योजना में कम्प्यूटर। क्षेत्र वीक्षण ओर अध्ययन यात्राएं भी आयोजित की गई थीं।

कार्यक्रम की व्यवस्था डॉ० ब्रह्म प्रकाश कार्यक्रम निदेशक और श्री एल० एस० गणेश कार्यक्रम संयोजक ने की।

2.01/85-86/8-2 मालदीव के अधिकारियों के लिए मानवशक्ति सांख्यिकी की शिक्षा का कार्यक्रम (अप्रैल 23 से जून 16, 1985)

यह कार्यक्रम सांख्यिकी विभाग, योजना मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरोध पर मालदीव की एक अधिकारी कुमारी सलीम बदूरा के लिए आवोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य भाग लेने वाले को, शैक्षिक योजना के उपागमों से परिचित कराना; शैक्षिक योजना में सांख्यिकी के अनुप्रयोग से अवगत कराना; अधिवासी देश में शैक्षिक योजना के स्तर पर सत्र-लेख तैयार करने में सहायता करना और भारत की शैक्षिक और मानव शक्ति सांख्यिकी से अवगत कराना था। कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए विषयों में शैक्षिक

योजना की संकल्पनाएं, सांख्यिकी प्रणाली, शैक्षिक योजना के मात्रात्मक पहलू, शैक्षिक योजना में कम्प्यूटरों का प्रयोग, प्रायोजना कार्य और संगोष्ठी लेख थे।

कार्यक्रम की व्यवस्था डॉ० ब्रह्मप्रकाश, कार्यक्रम निदेशक और श्री एल० एस० गणेश, कार्यक्रम संयोजक ने की।

3.01/85-86/03 शैक्षिक योजना और प्रबन्धन में कम्प्यूटरों के अनुप्रयोग पर कार्यशाला (20 मई से 25 मई 1985)

इस कार्यशाला का आयोजन मई, 1985 में किया गया था। कार्यशाला के उद्देश्य निम्न थे : राज्य स्तर के शिक्षा अधिकारियों को उनके काम में कम्प्यूटरों के विभिन्न प्रयोगों से अवगत कराना, सांख्यिकी अधिकारियों एवं शिक्षा निदेशकों की शिक्षा के मात्रात्मक विश्लेषण के लिए विभिन्न कम्प्यूटर आधारित प्रणालियों से अवगत कराना और शैक्षिक योजना के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधानकर्त्ताओं, नीति विश्लेषकों और अधिकारियों को उनके क्षेत्र में कम्प्यूटर पर आधारित तकनीकों/विश्लेषणों की संभावनाओं से अवगत कराना। इस कार्यशाला में विचार-विमर्श के विषयों में, कम्प्यूटरों का परिचय, शैक्षिक योजना के मात्रात्मक पहलू, प्रोग्रामन की संकल्पनाएं, बुनियादी प्रोग्रामन के तत्त्व, शैक्षिक प्रशासन में कम्प्यूटर, पैकेज का उपयोग, शिक्षा पद्धति के लिए प्रबन्ध सूचना सिस्टम, कम्प्यूटर-आधारित मॉडल और प्रबंधन के लिए पाठों के कम्प्यूटीकरण में मानवीय कारक शामिल थे। कार्यक्रम में 11 राज्यों तथा 2 केन्द्रशासित प्रदेशों के 25 राज्यस्तर के अधिकारियों ने भाग लिया था।

कार्यशाला की व्यवस्था डॉ० ब्रह्म प्रकाश, कार्यशाला निदेशक और श्री एल० ए० गणेश, कार्यशाला संयोजक ने की थी।

4.01/85-86/04 यूनेस्को द्वारा प्रायोजित एशियाई देशों के लिए सूक्ष्म स्तरीय योजना और प्रबन्ध पर क्षेत्रीय कार्यशाला (अक्टूबर 14 से नवम्बर 2,1985)

इस कार्यशाला का आयोजन नीपा ने यूनेस्को के सहयोग से किया था। इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत महासागरीय सदस्य देशों के प्रमुख कार्मिकों को, राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रारंभिक स्तर पर अधिक प्रभावी शैक्षिक योजना और प्रशासन के लिए सहयोग देना था। ऐसी आशा थी कि इस कार्यशाला के पश्चात् प्रत्येक देश से संबंधित ऐसे क्रियाकलाप होंगे जिनसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार अधिक कारगर रूप से किया जा सके। इस क्षेत्रीय कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सूक्ष्म-स्तरीय योजना और प्रबंध में प्राकृतिक कार्य नीतियां तैयार करने और उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देना था। एशिया और प्रशांत महासागर के 25 कार्मिकों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

कार्यशाला की व्यवस्था करने वालों में डा० ब्रह्म प्रकाश कार्यक्रम निदेशक, डा० एन० वी० वर्गीज श्री एल० एस० गणेश कार्यक्रम समन्वयकर्ता और श्री निवासन एम, कार्यक्रम सहायक थे।

5.01/85-86/05 शिक्षा नीति पर पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यशाला योजना और प्रबन्ध समस्याएं (नवम्बर 4 से 5 नवम्बर 1985)

इस कार्यशाला का आयोजन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईंसिस, बम्बई के सहयोग से किया गया था। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज "शिक्षा की चुनौती : नीति परिप्रेक्ष्य में" पर इस संगोष्ठी में विचार-विमर्श हुआ। इसमें देश के पश्चिमी क्षेत्र से शैक्षिक आयोजकों, प्रशासकों, प्रबंध विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और पत्रकारों ने भाग लिया। भाग लेने वालों की संख्या 35 थी।

इसकी व्यवस्था डॉ० ब्रह्म प्रकाश, कार्यक्रम निदेशक, डॉ० एन० वी० वर्गीज और डॉ० वाई० पी० अग्रवाल, कार्यक्रम समन्वयको ने की थी।

6.01/85-86/06 शिक्षा और रोजगार संयोजनों पर संगोष्ठी (19 मार्च से 21 मार्च, 1986)

वर्तमान में शैक्षिक योजनाकार इस द्विविधा से ग्रस्त हैं कि उन्हें निकट भविष्य में निर्जीव रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति से जूझना पड़ेगा। इसलिए संगोष्ठी में इस पर विचार किया कि भविष्य सुधारने के लिए और शिक्षा को अधिक अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय किए जाएं। इस संगोष्ठी में भाग लेने वालों की संख्या 44 थी।

इस संगोष्ठी की व्यवस्था डॉ० ब्रह्म प्रकाश, डॉ० वाई० पी० अग्रवाल, डॉ० एल० एस० गणेश, डॉ० एन० वी० वर्गीज, डा० एम०एम० खान, श्री इफ्तिकार अहमद, श्री एच० श्रीनिवासन और कुमारी मंजु रूदौला ने की।

02/ई. ए. डी./शैक्षिक प्रशासन एकक

7 से 11.02/85-86/01-05 हरियाणा के स्कूल/कॉलिज के प्रधानाचार्यों के लिए +2 स्तर के प्रबंध पर अभिविन्यास कार्यक्रम (22-26 अप्रैल, 1985) 29 अप्रैल से 3 मई, 1985) (6-10 मई, 1985) और (13-17 मई; 1985)

हरियाणा के स्कूल/कॉलिज के प्रधानाचार्यों के लिए एक माला के पांच कार्यक्रम तिमाही के दौरान आयोजित किए गए थे जिनमें भाग लेने वालों की संख्या 237 थी। इन कार्यक्रमों के उद्देश्य निम्न थे : 10 + 2 + 3 पैटर्न की अध्ययन की योजना के दर्शन और मूलाधार की मूलभूत संकल्पनाओं को स्पष्ट करना; अपने से संबंधित संस्थाओं में +2 स्तर की योजना का कार्यान्वयन करना; और संस्थागत प्रबंध के कुछेक व्यवहारिक पहलुओं का विश्लेषण करना। उच्च माध्यमिक स्तर के कार्यान्वयन और शैक्षिक संगठनों के प्रबंध में संबंधित विभिन्न विषयों के अंतर्गत, अध्ययन की 10 + 2 + 3 की नई योजना के दर्शन और मूलाधार को; विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा और वाणिज्य के पाठ्यचर्या प्रबंध को; सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य और व्यावसायीकरण कार्यक्रमों; शैक्षिक संगठन में नेतृत्व को; आंतरिक परीक्षा और श्रेणीकरण को; मार्गदर्शन और परामर्श को; स्टाफ मूल्यांकन और विकास को; संसाधन योजना और उपयोग को;

और संस्थागत योजना और प्रबन्ध को शामिल किया गया था। कार्यक्रमों में जिन कॉलेज केप्रधानाचार्यों ने भाग लिया है उनकी संख्या क्रमश: 44, 49, 43, 55, 46 थी।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था डॉ० एम मुखोपाध्याय, संयोजक, डॉ० सुधा राव, सदस्य और कुमारी नलिनी जुनेजा ने की। कार्यक्रम में श्री एम० कन्दन और कुमारी एस० त्रिपाठी ने भी सहायता की।

12.01/85-86/06 पोलिटेकनिकों के लिए शैक्षिक योजना पर अभिविन्यास कार्यक्रम (1-12 जुलाई, 1985)

यह कार्यक्रम तकनीकी शिक्षा की भारतीय समिति द्वारा प्रायोजित और नीपा द्वारा आयोजित किया गया था। पोलिटेकनिक शिक्षा के बढ़ते हुए महत्त्व और पाठ्यचर्या विकास और शिक्षण सामग्री और अन्य शिक्षण उपकरणों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न थे : संसाधनों के प्रबन्ध के तरीकों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संदर्भ में तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता पर बल देना, संस्थाओं के विकास के लिए विकास योजनाएं तैयार करना। इस अखिल भारतीय कार्यक्रमों में पोलिटेकनिकी के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया था।

इस प्रकार की व्यवस्था डॉ० एम० मुखोपाध्याय, डॉ० के० सुधाराव और श्री सी० आर० के० मूर्ति ने की।

13.02/85-86/07 केन्द्रीय विद्यालयों के वरिष्ठ प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रबन्ध पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (22 जुलाई से 2 अगस्त 1985)

केन्द्रीय बिद्यालय संगठन नई दिल्ली के अनुरोध पर केन्द्रीय विद्यालयों के वरिष्ठ प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रबन्ध पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। पाठ्यक्रम के उद्देश्य निम्न थे : नई शिक्षा प्रवृत्तियां और गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ शैक्षिक योजना और प्रवन्ध की आधुनिक संकल्पनाओं से परिचित कराना, एक प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने के लिए स्कूल प्रधान के लिए आवश्यक कौशल की आवश्यकता पर बल और संस्थागत योजनाओं का निर्माण। इसमें केन्द्रीय विद्यालयों के 37 प्रधानाचार्यों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था डा० के० जी० विरमानी तथा कुमारी रश्मि दीवान ने की थी।

14.02/85-86/08 शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रवन्ध पर कार्यशाला (2-6 सितम्बर, 1985)

संस्थान में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रबन्ध पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रबन्ध में सम्बन्धित कुछेक प्रमुख मुद्दों पर और साथ ही प्रबन्ध में सुधार के लिए कुछेक व्यावहारिक नीतियों का विकास करने के लिए विचार-विमर्श हुआ। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे : प्रवन्ध निहिताओं को दर्शाते हुए प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं की रूपरेखा तैयार करना, सातवीं योजना में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में विचार-विमर्श करना और राज्य तथा संस्थागत स्तर पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी

के लिए प्रबन्ध मॉडलों का विकास करना इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से भाग लेने वालों की संख्या 21 थी।

इस कार्यशाला की व्यवस्था डा० एम० मुखोपाध्याय, डा० के० सुधाराव, कु० नलिनी जुनेजा और श्री सी० आर० के० मूर्ति ने की।

15.02/85-86/09 +2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के प्रबन्ध मॉडल के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला

सातवीं योजना में +2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण को प्राथमिकता प्रदान की गई है। शिक्षा की कार्य से जोड़े जाने के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए नीपा ने विभिन्न सिफारिशों के लिए, कार्यान्वयन नीतियां तैयार करने के लिए, +2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के प्रबन्ध के नाजुक मुद्दों की पहचान के लिए, विद्यमान प्रबन्ध उपागमों की जांच के लिए और व्यावसायीकरण के प्रबन्ध के व्यावहारिक मॉडलों का विकास करने के लिए बहुत-से कार्यक्रम आयोजित किए।

इस कार्यक्रम में कुछेक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 22 वरिष्ठ प्रशासकों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था डा० के० सुधाराव, डा० एम० मुखोपाध्याय, कु० नलिनी जुनेजा और श्री सी० आर० के० मूर्ति ने की।

16.02/85-86/10 "नई शिक्षा नीति : योजना और प्रबन्ध समस्याएं" पर पूर्वी क्षेत्रीय संगोष्ठी (16-17 अक्टूबर 1985 कलकत्ता)

इन संगोष्ठी का आयोजन भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के साथ मिलकर किया गया था। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज शिक्षा की चुनौती : नीति परिप्रेक्ष्य पर इस संगोष्ठी में विचार-विमर्श किया गया। संगोष्ठी का उद्देश्य शिक्षा नीति से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं और प्रबन्ध समस्याओं के सम्बन्ध में विचार-विमर्श और वाद-विवाद करना था। कार्यक्रम का उद्देश्य योजना और प्रबन्ध की वर्तमान स्थिति और इनसे जुड़ी हुई कुछेक मुख्य समस्याओं पर विचार करके योजना और प्रबन्ध की शिक्षा के सम्बन्ध में एक नीति सम्बन्धी दस्तावेज तैयार करना था। इस संगोष्ठी से पूर्वी क्षेत्र से भाग लेने वालों की संख्या 15 थी।

संगोष्ठी की व्यवस्था डा० मुखोपाध्याय कार्यक्रम निर्देशक, श्री सी० आर० के० मूर्ति कार्यक्रम सहायक द्वारा की गई थी।

17.02/85-86/11 शैक्षिक प्रशासन में प्रशिक्षण और अनुसंधान पर संगोष्ठी (13-17 जनवरी, 1986)

संस्थान ने शैक्षिक प्रशासन में प्रशिक्षण और अनुसंधान से सम्बन्धित संगोष्ठी का आयोजन पाठ्यक्रमों, पाठ्य-सामग्री और शैक्षिक प्रशासन में प्रशिक्षण के मूल्यांकन की प्रणालियों की पहचान करने और शैक्षिक प्रशासन

में अनुसंधान की प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करने के लिए किया था। भारत के 13 विश्वविद्यालयों के 13 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

संगोष्ठी की व्यवस्था डा० एन० एम० भागिया, संगोष्ठी निदेशक और श्री डी० एच० श्रीकांत, संगोष्ठी समन्वयकर्ता ने की।

18.02/85-86/12 इंजीनियरी कालेजों का प्रबंध (24-28 फरवरी, 1986)

यह इस माला का दूसरा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल प्रबन्ध क्षमताओं को सुदृढ़ करना है बल्कि सामान्य रूप से तकनीकी शिक्षा और विशेष रूप से इंजीनियरी शिक्षा की समस्याओं के प्रति इंजीनियरी कालेज के प्रधानाचार्यों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना है। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे : समस्याओं की पहचान करने के लिए इंजीनियरी कालेजों का पद्धति विश्लेषण करना और भाग लेने वालों की संगठनात्मक निदान में विभिन्न उपगमों/साधनों से परिचित कराना और संसाधनों के उपयोग के लिए समझ का विकास करना तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना। कार्यक्रम में देश के विभिन्न भागों के इंजीनियरी कालेजों के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था डा० एम० मुखोपाध्याय, कार्यक्रम निदेशक और श्री डी० एच० श्रीकांत कार्यक्रम सहायक से की।

19.02/85-86/13 शैक्षिक उत्पादकता और उत्पादकता शिक्षा पर कार्यक्रम (3-4 मार्च, 1986)

शैक्षिक उत्पादकता और उत्पादकता शिक्षा पर कार्यशाला का आयोजन संयुक्त रूप से संस्थान और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने किया था। कार्यशाला का उद्देश्य भाग लेने वालों को शैक्षिक संस्थाओं में उत्पादकता की आवश्यकता से परिचित कराने और प्रधानाचार्यों तथा वरिष्ठ अध्यापकों के जरिए स्कूल छात्रों में उत्पादकतोन्मुखी प्रवृत्तियों और मूल्यों के विकास की आवश्यकताओं पर बल देना था। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या 16 थी।

डा० एम० मुखोपाध्याय और डा० के० सुधाराव ने इस कार्यक्रम की व्यवस्था की।

20.02/85-86/14 शैक्षिक परिवर्तन के प्रबन्ध पर राष्ट्रीय कार्यशाला (3-7 मार्च, 1986)

इस कार्यशाला का आयोजन, स्कूलों में परिवर्तन के प्रबन्ध के सम्बन्ध में केस अध्ययनों का विकास करने, परिवर्तन की प्रक्रिया का परीक्षण करने और स्कूलों में परिवर्तन के प्रबन्ध का मॉडल प्रस्तावित करने के लिए किया गया था। इस कार्यशाला में भाग लेने वालों की संख्या 8 थी।

कार्यशाला की व्यवस्था डा० एम० मुखोपाध्याय, कार्यक्रम निदेशक, श्रीमती नलिनी जुनेजा, कार्यक्रम समन्वयकर्ता, श्री डी० एच० श्रीकांत और श्री सी० आर० के० मूर्ति, कार्यक्रम सहायक ने की थी।

21.03/85-86/15 +2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना और प्रबन्ध का अभिविन्यास कार्यक्रम (10-14 मार्च, 1986)

यह कार्यक्रम सातवीं योजना और आगामी नई शिक्षा नीति में व्यावसायीकरण को उच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम उच्च माध्यमिक स्कूलों और जूनियर कालेजों के उन प्रधानाचार्यों के लिए आयोजित किया था जहां व्यावसायीकरण चालू कर दिया गया है या किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार थे :+2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना और प्रबन्ध की मूलभूत संकल्पनाओं से भाग लेने वालों को परिचित करना, सूक्ष्म स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना की प्रणालियों और तकनीकों से भाग लेने वालों को अवगत करना, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों की योजना और प्रबन्ध की नवीन प्रक्रियात्मक पद्धति से भाग लेने वालों को परिचित कराना और योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यशील योजना का विकास करना। देश के विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इस कार्यक्रम में 11 प्रधानाचार्यों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की व्यवस्था डा० के० सुधाराव, कार्यक्रम निदेशक, डा० एम० मुखोपाध्याय, श्री सी० आर० के० मूर्ति और डा० डी० एच० श्रीकांत ने की थी।

03/ई एफ एन शैक्षिक वित्त एकक:

22.03/85-86/01 विश्व विद्यालय वित्त प्रबन्ध में अभिविन्यास कार्यक्रम (5-9 अगस्त, 1981)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरोध पर नीपा ने विश्वविद्यालय वित्त प्रबन्ध के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। इसके उद्देश्य निम्न थे: सामान्यत: आधुनिक प्रबन्ध की तकनीकी के बारे में और विशेष रूप से आधुनिक वित्त प्रबन्ध के बारे में इस प्रकार की जानकारी को बढ़ावा देना था ताकि विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन में इनका अनुपयोग किया जा सके और विश्वविद्यालयों के विकास में वित्त अधिकारियों को उनकी नई भूमिका और उत्तरदायित्वों से परिचित कराया जा सके। विभिन्न विश्व-विद्यालयों के 32 वित्त अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।

अभिविन्यास कार्यक्रम की व्यवस्था डा० सी० बी० पद्मनाभन, डा० जे० बी० जी० तिलक और कुमारी वाई० जॉसफीन ने की थी।

23.03/85-86/02 शैक्षिक वित्त के प्रबन्ध में अभिविन्यास कार्यक्रम (16-27 सितम्बर, 1985)

संस्थान द्वारा शिक्षा विभागों और निदेशालयों में कार्यरत अधिकारियों के लिए शैक्षिक वित्त के प्रबन्ध के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य निम्न थे : अधिकारियों में शिक्षा-वित्त की वर्तमान प्रणाली और शिक्षा में वित्त प्रबन्ध के बारे में बेहतर सूझबूझ का विकास करना और शिक्षा

में वित्तीय प्रबन्ध की आधुनिक तकनीकों के बारे में विशेष रूप से परिवर्तनशील शैक्षिक परिस्थितियों के संदर्भ में जानकारी को बढ़ावा देना था। 19 वित्त अधिकारियों ने इस अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लिया था।

कार्यक्रम की व्यवस्था डा० सी० बी० पद्मनाभन, डा० जे० बी० जी० तिलक और कुमारी वाई० जॉसफीन ने की थी।

24. 03/85-86/03 शिक्षा में संसाधनों का प्रभावी उपयोग पर कार्यशाला (24-27 फरवरी, 1986)

शिक्षा संसाधनों की समस्या अब लगभग संकट की स्थिति में है। बहुत से पूर्वानुमानों से पता चलता है कि विश्व के विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में शिक्षा प्रणालियां, संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में शिक्षा प्रणालियां, आने वाले वर्षों में सुधरने वाली नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, संसाधनों के प्रभावी उपयोग का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने शिक्षा में संसाधनों का प्रभावी उपयोग" पर कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला के उद्देश्य निम्न थे : संसाधन की बाधाओं के संदर्भ में विशेष रूप से सातवीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग के बारे में एक आम जानकारी उत्पन्न करना; भाग लेने वालों को ऐसे क्षेत्रों से परिचित कराना जहां पर कार्यकुशल रूप से सुविधाओं का उपयोग संभव है और ऐसे साधनों और तकनीकों की जानकारी देना जिससे विद्यमान संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो सके। कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या 16 थी।

इस कार्यशाला की व्यवस्था डा० सी० बी० पद्मनाभन, कार्यक्रम निदेशक, डा० बी० जी० तिलक, कार्यक्रम संयोजक और कुमारी वाई० जॉस फीन कार्यक्रम सहायक ने की।

04/ई. पी ओ शैक्षिक नीति एकक

25.04/85-86/ 01 शिक्षा में समता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (27-31 मई, 1985)

यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के राज्य शिक्षा विभागों के योजना खंडों के अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे : भाग लेने वालों को शिक्षा में समता की संकल्पनाओं के प्रति सुग्राही बनाना; वंचितों की शिक्षा के विकास के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों का वास्तविक आकलन करने के लिए भाग लेने वालों की सहायता करना; कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा के विकास की नीतियां तैयार करना; और भाग लेने वालों को असमानताओं के मापदण्ड के लिए सुव्यवस्थित साधनों के उपयोग से अवगत करना। कार्यक्रम में जो विषय में समता पर आधारित थे। इसमें भाग लेने वालों की संख्या 18 थी।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था डॉ० (श्रीमती) कुसुम प्रेमी, डॉ० के० सुजाता, डॉ० एस० सी० नूना, श्री ए० मैथ्यू, श्री एस० एम० आई० ए० जैदी ने की।

26. 04/85 86/02 **संस्थाओं के विभागाध्यक्षों और जिला स्तर के अधिकारियों के लिए आश्रम स्कूलों की योजना और प्रबंध पर अभिविन्यास कार्यक्रम** (26-30 अगस्त, 1985)

यह कार्यक्रम, नीपा द्वारा केन्द्रीय आदिवासी क्षेत्र के 5 राज्यों में आश्रम स्कूलों में किए गए अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर आयोजित किया गया था। यह अभिविन्यास कार्यक्रम आश्रम स्कूलों के अध्यक्षों को, इन स्कूलों में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया और वित्त प्रबन्ध के बारे में प्रशिक्षण देना था। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न थे : भाग लेने वालों को आदिवासी शिक्षा के सामाजिक-आर्थिक दबावों के बारे में सुग्राही बनाना; उन्हें आश्रम स्कूलों की समस्याओं से अवगत कराना और उन्हें योजना, प्रबंध, स्कूलों के पर्यवेक्षण और संस्थागत योजना की तकनीकों की नई प्रणालियों से परिचित कराना। इस कार्यक्रम में 23 आश्रम स्कूलों के अध्यक्षों ने भाग लिया था।

कार्यक्रम की व्यवस्था डॉ० (श्रीमती) कुसुम प्रेमी, डॉ० के० सुजाता, डॉ० एस० सी० नूना, श्री ए० के० मैथ्यू और श्री एस० एम० आई० ए० जैदी ने की।

27. 04/85-86/03 **मध्य प्रदेश आदिवासी कल्याण विभाग, के स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए संस्थागत योजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम** (10-20 सितंबर 1985—कंकर बस्तर)

संस्थान द्वारा कंकर में, मध्य प्रदेश, आदिवासी कल्याण विभाग के स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए संस्थागत योजना पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न थे : भाग लेने वालों को राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में आदिवासी शिक्षा के महत्त्व से परिचित कराना, आदिवासी शिक्षा के विकास की समस्याओं का तार्किक मूल्यांकन करना और साथ ही भाग लेने वालों को संस्थागत योजना की प्रक्रिया और प्रणाली को समझने में और संस्थागत स्वमूल्यांकन के साधनों का विकास करने में मदद करना। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 68 प्रधानाचार्यों ने और आदिवासी कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ प्राध्यापकों ने भाग लिया था।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था डा० (श्रीमती) कुसुम प्रेमी और डा० एस० सी० नूना ने की थी।

28. 04/85-86/04 **शिक्षा का राष्ट्रीय नीति पर उत्तर क्षेत्र संगोष्ठी** (28-29 सितंबर 1986)

इस संगोष्ठी का आयोजन विभिन्न योजना और प्रबंध से सम्बन्धित विषयों का विस्तार से विश्लेषण करने के लिए किया गया था। इसमें केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज 'शिक्षा की चुनौती-नीति परिप्रेक्ष्य में' पर विचार किया गया था। देश के उत्तरी क्षेत्र से इस संगोष्ठी में शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों प्रबन्ध विशेषताओं, शिक्षाविदों और पत्रकारों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की व्यवस्था डा० (श्रीमती) कुसुम प्रेमी, श्री एम० एम० कपूर और डा० एस० सी० नूना ने की।

29. 04/85-86/05 **मध्य प्रदेश, आदिवासी कल्याण स्कूलों में बेहतर पर्यवेक्षण का प्रशिक्षण कार्यक्रम (17-24 दिसंबर, 1985)**

मध्य प्रदेश में, आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए बेहतर पर्यवेक्षण के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य प्रधानाचार्यों को शिक्षा के आधुनिक सिद्धान्तों से परिचित कराना और पर्यवेक्षण की नवीन तकनीकों की सूचना प्रदान करना था। इसमें भाग लेने वालों की संख्या 48 थी।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था डॉ० (श्रीमती) कुसुम प्रेमी और डॉ० एस० सी० नूना ने की।

30.04/85-86/06 **आदिवासी शिक्षा पर कार्यशाला, जगदलपुर (बस्तर) मध्यप्रदेश 24-26 फरवरी 1986)**

यह कार्यशाला बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित की गई थी। कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासियों के बीच शैक्षिक विकास की बाधाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण करना; और विद्यमान बाधाओं के संदर्भ में आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षिक विकास के लिए नीतियों का विकास करना था। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या 46 थी। प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों और आदिवासी कल्याण विभाग से लिए गए थे।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था डॉ० एस० सी० नूना ने श्री ए० मैथ्यू की सहायता से की।

05/एस० सी० एन/स्कूल और गैर-औपचारिक शिक्षा एकक

31.05/85-86/01 **शैक्षिक योजना और प्रशासन में डिप्लोमा—जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए चौथा प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम (6 मई से 1 नवम्बर,1985)**

यह जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए चौथा डिप्लोमा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में केरल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान और दिल्ली के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे : शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबन्ध की मूलभूत संकल्पनाओं से भाग लेने वालों को परिचित कराना; भाग लेने वालों को ऐसी आवश्यक दक्षताओं और तकनीकों से परिचित कराना जो उनके शैक्षिक निर्णय की क्षमता के लिए आवश्यक है; राष्ट्र-निर्माण में शिक्षा के बढ़ते हुए व्यापक योगदान की प्रत्याशाओं के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं से भाग लेने वालों की जूझने की क्षमताओं को

सुदृढ़ करना; और भाग लेने वालों को शैक्षिक अनुसंधान और प्रयोगों की प्रारंभिक तकनीकों से परिचित कराना। यह कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया था जिसमें तीन माह का गहन पाठ्यक्रम कार्य 15 श्रेयांक (क्रेडिट) का; प्रशिक्षार्थी जिला शिक्षा अधिकारी के जिले में तीन माह का पर्यवेक्षित कार्य 9 श्रेयांक का; और प्रायोजना रिपोर्टों पर आधारित मौखिक परीक्षा चार दिन की रखी गई थी। पाठ्यक्रम के विषय निम्न थे : शिक्षा नीति और शिक्षा की समस्याएं; तृतीय विश्व में शैक्षिक विकास; शिक्षा में प्राथमिकता के क्षेत्र; शैक्षिक योजना; बृहत समस्याएं; शैक्षिक योजना में सूक्ष्म-स्तरीय योजना; शिक्षा में सांख्यिकी एवं अनुसंधान प्रणालियां; शैक्षिक योजना के मात्रात्मक पहलु; संगठनात्मक व्यवहार और विकास; निरीक्षण और पर्यवेक्षण; संसाधनों का प्रबन्ध, और कार्यालय प्रबन्ध।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था डॉ० सी० एल० सपरा, श्री शब्बीर अहमद और कुमारी जुबैदा हबीब ने की।

32. 05/85-86/02 **यूनेस्को द्वारा प्रायोजित समन्वित योजना एवं औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा के बीच अनुपूरकता पर राष्ट्रीय कार्यशाला** (16-27 **सितंबर**, 1985)

यूनेस्को के एशिया, पेसिफिक, बैंकाक क्षेत्रीय कार्यालय के अनुरोध पर संस्थान ने, समन्वित योजना एवं औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा के बीच अनुपूरकता पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य समन्वय और औपचारिक एवं गैर-औपचारिक शिक्षा की अनुपूरकता से सम्बन्धित विद्यमान पद्धतियों का सर्वेक्षण करना था जिनका संवर्धन संरचनाओं, विषय-वस्तु और प्रणालियों के जरिए प्रारंभिक एवं विज्ञान शिक्षा के सार्वजनीकरण, शिक्षक प्रशिक्षक तथा मूलभूत कौशल प्रशिक्षण के संदर्भ में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से समन्वय और औपचारिक तथा गैर-औपचारिक शिक्षा की अनूपूरकता को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यावहारिक सिफारिशें करने में मदद मिली। इस कार्यशाला में भाग लेने वालों की संख्या 21 थी।

इस कार्यशाला की व्यवस्था डॉ० सी० एल० सपरा, श्री टी० के० डी० नायर, श्री शब्बीर अहमद कु० रश्मि दीवान ने की।

33. 05/85-86/03 **प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों और अन्य विभागों के निर्धनता उपशमन कार्यक्रमों के बीच परस्पर निर्भरता के प्रबन्ध पर संगोष्ठी व कार्यशाला** (30 **सितंबर से 4 अक्तूबर**, 1985)

संस्थान ने प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के सहयोग से राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और अन्य विभागों के निर्धनता उपशमन कार्यक्रमों के बीच परस्पर निर्भरता के प्रबंध पर संगोष्ठी व कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सातवीं योजना में गैर-औपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न थे : प्रौढ़ तथा गैर-औपचारिक शिक्षा और अन्य विकास से संबंधित विभागों के आई आर डी पी एन आर इ पी और डी डब्ल्यू ओ आर ए आदि जैसे निर्धनता उपशमन कार्यक्रमों के बीच परस्पर निर्भरता को समझना एवं उसका विश्लेषण करना; अनुबन्धनों के प्रबन्ध मॉडलों और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के बीच परस्पर निर्भरता पर भी विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम में 20

जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों एवं परियोजना अधिकारियों ने भाग लिया।

इस संगोष्ठी व कार्यशाला की व्यवस्था डॉ० सी० एल० सपरा, डा० एस० भागिया, श्री डी० वी० शर्मा, श्री वी० अस्थाना और कु० कौसर विजारत ने की।

34. 05/85-86/04 **जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में पांचवां डिप्लोमा पाठ्यक्रम** (18 नवम्बर, 1985 से 13 मई 1986)

जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए यह पांचवां डिप्लोमा कार्यक्रम था। इसके मुख्य उद्देश्य निम्न थे : शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंध की मूलभूत संकल्पनाओं से भाग लेने वालों को परिचित कराना; जिला स्तर पर शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों का दायित्व पूरा करने के लिए आवश्यक मूलभूत कौशलों और तकनीकों का ज्ञान कराना; निर्णय लेने की क्षमता में विकास करना; राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की बढ़ती हुई भूमिका से उत्पन्न समस्याओं से अवगत कराके उन्हें हल करने के लिए सक्षम बनाना; भाग लेने वालों की शैक्षिक अनुसंधान और प्रयोग की प्रारंभिक तकनीकों से अवगत कराना। कार्यक्रम को तीन माह के 15 श्रेयांक (क्रेडिट) के गहन पाठ्यचर्या कार्य, तीन माह के 9 श्रेयांक (क्रेडिट) के पर्यवेक्षित और सिंडीकेट कार्य और परियोजना रिपोर्टों पर आधारित 4 दिन की मौखिक परीक्षा में बांटा गया था। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों/संघ केन्द्र शासित प्रदेशों के 35 जिला शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था डा० सी० एल० सपरा, श्री शब्बीर अहमद और कु० कौसल विजारत ने की।

35. 05/85-86/05 **जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक पर्यवेक्षण का अभिविन्यास कार्यक्रम** (6-10 जनवरी, 1986)

शिक्षा में पर्यवेक्षण के महत्त्व को देखते हुए शैक्षिक पर्यवेक्षण का अभिविन्यास कार्यक्रम जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे : शैक्षिक पर्यवेक्षण की कुछेक आधुनिक तकनीकों और पद्धतियों से भाग लेने वालों को परिचित कराना; भाग लेने वालों के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्कूलों की विद्यमान पर्यवेक्षण पद्धतियों का सर्वेक्षण; और स्कूलों को बेहतर पर्यवेक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समुचित क्रियात्मक कार्यक्रम तैयार करना। इस कार्यक्रम में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों 16 अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की व्यवस्था डॉ० सी० एल० सपरा, श्री टी० के० डी० वायर और कु० रश्मि दीवान ने की।

36.05/85-86/06 **उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए गैर-औपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा की योजना और प्रबन्ध पर संगोष्ठी** (17-21 फरवरी, 1986)

संस्थान ने प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के सहयोग से प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित उच्च अधिकारियों के लिए परियो-

जना कार्यान्वयन पर पांच दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य निम्न थे। परियोजना कार्यान्वयन के प्रबंध की मुख्य समस्याओं की पहचान करके उन पर वाद-विवाद करना; विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में परियोजना कार्यान्वयन को सफल बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनके अनुभवों और नवाचार उपागमों के आदान-प्रदान के लिए मंच प्रदान करना; प्रशिक्षण समुदाय सहयोग और अन्य विभागों के साथ अनुबंधनों के विशेष संदर्भ में क्षेत्र स्तर पर प्रभावी परियोजना कार्यान्वयन के लिए उचित नीतियों/निर्देशों का विकास करना; इस कार्यशाला में भाग लेने वालों की संख्या 45 थी।

इस कार्यशाला के प्रबंध-दल में डॉ० सी० एस० बसरा, श्री एस० के० टुटेजा, डा० सुषमा भागिया और श्री ओ० डी० त्यागी थे।

06/ एच आर ई/उच्च शिक्षा एकक

37 06/85-86/01 उच्च शिक्षा की योजना और विकास के लिए आधार सामग्री प्रक्रमण पर प्रशिक्षण कार्यशाला (21-24 अगस्त 1985)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरोध पर उनके सांख्यिकी कार्मिकों के लिए उच्च शिक्षा की योजना और विकास के आधार-सामग्री प्रक्रमण के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला का उद्देश्य भाग लेने वालों को उच्च शिक्षा के डेटा/सूचना योजना और विकास से; विश्वसनीयता और संगतता रोध की, आधार-सामग्री विश्लेषण की मूलभूत तथा उच्च सांख्यिकी प्रणालियों की और डेटा स्टोरेज, प्रक्रमण और पुनः प्राप्ति के लिए कम्प्यूटर के प्रयोग की तकनीकों से परिचित कराना था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 26 सांख्यिकी कार्मिकों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

कार्यशाला की व्यवस्था डॉ० जी० डी० शर्मा, डॉ० शक्ति आर० अहमद, श्री एम० एम० रहमान और कु० मंजु नरूला ने की।

38. 06/85-86/02 कालेज के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन पर अभिविन्यास कार्यक्रम (9-28 सितम्बर 1985)

यह श्रंखला का 7 वां कार्यक्रम था जिसे सामान्य कालेजों के प्रधानाचार्यों के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न थे : प्रधानाचार्यों को राष्ट्रीय विकास में उच्चशिक्षा की भूमिका; और मात्रा, गुणवत्ता और समानता, कालिज और समुदाय संबंध जैसे विषयों से परिचित कराना; उन्हें योजना प्रबन्ध और मूल्यांकन पद्धतियों की आधुनिक तकनीकों-से अवगत करना और साथ ही देश के विभिन्न भागों के प्रधानाचार्यों को परस्पर मिलने और अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करना। विभिन्न राज्यों से 19 विश्वविद्यालयों से 32 कालिज के प्रधानाचार्यों ने इस अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लिया था।

कार्यक्रम की व्यवस्था डॉ० जी० डी० शर्मा, डॉ० शक्ति आर० अहमद, श्री एम० एम० रहमान और कुमारी मंजु नरूला ने की।

39. 06/85-86/03 **नई शिआ नीति के योजना और प्रबंध पहलुओं पर दक्षिण क्षेत्र संगोष्ठी** (26-27 **अक्तूबर**, 1985)

इस संगोष्ठी का आयोजन विभिन्न योजना और प्रबंध विषयों का विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिए किया गया था। इसमें केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज 'शिक्षा की चुनौती : नीति परिप्रेक्ष्य में' पर विचार किया गया। देश के दक्षिण क्षेत्र से इसमें शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों, प्रबन्ध विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और पत्रकारों ने भाग लिया था जिनकी संख्या 20 थी।

इसकी व्यवस्था डॉ० जी० डी० शर्मा, डॉ० शक्ति आर० अहमद और श्री एम० एम० रहमान ने की।

40. 06/85-86/04 **जोधपुर विश्वविद्यालय में जोधपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्यों के लिए अनुसंधान की कार्यप्रणालियों पर कार्यशाला** (20-24 **नवम्बर**, 1985)

इस कार्यशाला का आयोजन नीपा के सहयोग से और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समर्थन से जोधपुर विश्वविद्यालय ने किया था। यह अपने प्रकार की पहली कार्यशाला थी जिसमें प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के 15 संकायों में से प्रत्येक संकाय के तीन-तीन सदस्यों ने भाग लेकर अनुसंधान कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। यह कार्यक्रम इसलिए भी अनूठा था क्योंकि विश्वविद्यालय के सभी संकायों के सदस्यों ने अपने-अपने विभागीय स्तर पर एम० फिल कार्यक्रम का मसौदा, अनुसंधान कार्य प्रणाली से संबंधित प्रश्नों पर परस्पर विचार-विमर्श करके तैयार किया था। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अंतः शास्त्रीय ढांचे के अंतर्गत अनुसंधान कार्यप्रणाली के प्रतिमानों, उपागमों, प्रणालियों तकनीकों और साधनों पर विचार-विमर्श करना और विभिन्न विषयों में एम० फिल कोर्स का पाठ्यक्रम तैयार करना था। इसमें भाग लेने वालों की संख्या 45 थी।

इस कार्यशाला की व्यवस्था डॉ० जी० डी० शर्मा, डॉ० (श्रीमती) शक्ति आर० अहमद और श्री एम० एम० रहमान ने की।

41. 06/85-86/05 **कालेज प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन का अभिविन्यास कार्यक्रम** (9-27 **दिसम्बर** 1885)

संस्थान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरोध पर तीन सप्ताह की अवधि का राष्ट्रीय स्तर का अभिविन्यास कार्यक्रम महिला कालेजों के प्रधानाचार्यों के लिए आयोजित किया जिसमें देश के विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्रधानाचार्यों को सम्मिलित किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य

उद्देश्य निम्न थे : भाग लेने वालों के साथ राष्ट्रीय विकास के उच्च शिक्षा की भूमिका और मात्रा, गुणवत्ता, और समानता; कालेज और समुदाय संबंध, उच्च शिक्षा के भावी परिप्रेक्ष्य के संबंध में विचार-विमर्श करना; भाग लेने वालों को योजना/प्रबन्ध/मानकों में सुधार की आधुनिक तकनीकों/प्रणालियों से; और कालेज-समाज अन्योन्यक्रिया और मूल्यांकन से परिचित कराना; और भाग लेने बालों को परस्पर मिलकर अपने अनुभवों के आदान-प्रदान के अवसर प्रदान करना ।

कार्यक्रम की योजना इस प्रकार बनाई गई थी जिससे उसमें पृष्ठभूमि और नीति से संबंधित क्षेत्र आ जाएं यथा कालेज योजना, कालेज प्रबंध, कालेज वित्त, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, कालेज-समुदाय संबंध और मूल्यांकन । इसमें 25 कालेज प्रधानाचार्यों ने भाग लिया था ।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था डॉ० जी० डी० शर्मा, डॉ० शक्ति आर० अहमद और श्री एम० एम० रहमान ने की ।

42. 06/85-86/06 **रजिस्ट्रारों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की योजना और प्रबन्ध के पहलुओं पर संगोष्ठी व कार्यशाला** (28-29 **दिसम्बर**, 1985)

संस्थान और भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समर्थन से विभिन्न राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की योजना और प्रबंध के पहलुओं पर एक संगोष्ठी व कार्यशाला का आयोजन किया था । कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य निम्न थे; विशेष रूप से नई शिक्षा नीति के संदर्भ में उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासकों की भूमिका; विश्वविद्यालय के विकास की योजना; संगठनात्मक संरचना और प्रत्यायोजित प्राधिकार के संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन के नए मॉडल बनाना । 28 बिश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों ने इस कार्यशाला में भाग लिया ।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था डॉ० जी० डी० शर्मा, डॉ० शक्ति आर० अहमद और श्री एम० एम० रहमान ने की ।

43. 06/85-86/0 7 **स्वायत्त कालेजों में अध्ययन दौरा (मद्रास कुट्टालम, कोयम्बटूर और मदुरै)** (18-14 **फरवरी** 1986)

नई शिक्षा नीति में स्वायत्त कॉलेजों के विषय में चर्चा हो रही है और यह भी तथ्य है । कि बहुत-से कॉलेजों ने संबंधित विश्वविद्यालयों को स्वायत्त स्थिति प्रदान करने के लिए लिखा है इसलिए यह जरूरी था कि स्वायत्त कालेजों के विकास और अनुभवों का अध्ययन किया जाए ताकि इन कॉलेजों से संबंधित नीति-निर्धारण में सहायता मिल सके और साथ ही स्वाययत्ता के इच्छुक कालेजों को फायदा पहुंच सके । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को ऐसे स्वायत्त कालेजों का अध्ययन दौरा करने का प्रस्ताव किया गया था, जिन्हें स्वायत्त स्थिति प्रदान की जा सकती थी । इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या 21 थी ।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था डॉ० जी० डी० शर्मा, डॉ० शक्ति आर० अहमद, श्री एम० एम० रहमान और कु० कौसर विजारत ने की। मद्रास में प्रो० के० एम० बहाउद्दीन ने भी अंतिम कार्यकलापों में भाग लिया।

44. 06/85-86/08 **कालेज प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम (24 फरवरी से 14 मार्च, 1869)**

भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरोध पर, संस्थान से विभिन्न राज्यों के उन कालेजों के प्रधानाचार्यों के लिए; जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की बहुतायत है, शैक्षिक योजना और प्रशासन पर तीन सप्ताह की अवधि का अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे : भाग लेने वालों के साथ राष्ट्रीय विकास में उच्च शिक्षा के भूमिका के साथ मात्रा, गुणवत्ता और समानता, कालेज और समुदाय संबंध, उच्च शिक्षा के भावी परिप्रेक्ष्य आदि जैसे विषयों पर विचार-विमर्श करना; भाग लेने वालों को योजना/प्रबंध मानकों में सुधार की आधुनिक तकनीकों/प्रणालियों से और कालेज-समाज अन्योन्यक्रिया और मूल्यांकन से परिचित कराना। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या 20 थी।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था दल में डॉ० शक्ति आर० अहमद, डा० सी० डी० शर्मा, श्री एम० एम० रहमान और कुमारी कौसर विजारत शामिल थे।

45. 06/85-86-09 **कालेजों के विज्ञान विभागों के अध्यक्षों के लिए विज्ञान शिक्षा की योजना और प्रबंध पर अभिविन्यास कार्यक्रम (17-23 मार्च 1986)**

संस्थान ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरोध पर एक सात दिवसीय विज्ञान शिक्षा की योजना और प्रबंध पर अभिविन्यास कार्यक्रम भारत के विभिन्न राज्यों के विज्ञान विभागों के अध्यक्षों के लिए आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे : कालेज शिक्षकों को विज्ञान क्षेत्र में हुए नए विकास और उनकी संभाव्यताओं का पता लगाना जिससे विज्ञान कार्यक्रमों की पुनर्रचना इस प्रकार की जा सके ताकि वे समुदाय की विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके, भाग लेने वालों को योजना और लागत प्रभावी प्रयोगशाला पद्धतियों से और प्रयोगशालाओं में सुरक्षा उपायों से परिचित कराना। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए भाग लेने वालों की संख्या 18 थी।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था डा० शक्ति आर० अहमद, डा० जी० डी० शर्मा, श्री एम० एम० रहमान और कु० कौसर विजारत ने की।

07/एस एन एस/उपराष्ट्रीय पद्धति एकक

46. 07/85-86/01 **यूनेस्को द्वारा आयोजित शैक्षिक प्रशासन के विशेष संदर्भ में कार्यालय प्रबंध में उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम** (जनवरी 7 से 31 दिसंबर, 85)

शिक्षा विभाग, विकास मंत्रालय, भूटान के एक अधिकारी श्री गौरी शंकर शर्मा के लिए 12 माह का उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 जनवरी, 1985 से शुरू किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे : भाग लेने वाले को कार्यालय प्रबंध की महत्वपूर्ण संकल्पनाओं और तकनीकों से तथा वर्तमान प्रवृत्तियों से परिचित कराना; और भाग लेने वालों को शैक्षिक प्रशासन के विशेष संदर्भ में कार्यालय प्रबंध के क्षेत्र में व्यावसायिक क्षमता अर्जित करने में सहायता प्रदान करना। कार्यक्रम के लिए 100 श्रेयांक (क्रेडिट) रखे गए थे जिनमें नीपा में पाठ्यचर्या कार्य के लिए 45 श्रेयांक, 20 श्रेयांक क्षेत्र कार्य के लिए और 33 श्रेयांक परियोजना कार्य के लिए। पाठ्यचर्या माड्यूल जिनमें भूटान और भारत में शैक्षिक विकास, कार्यालय संगठन, कार्यालय सेवाओं का प्रबंध, कार्यालय रूपरेखा और सामान्य सेवाएं, वित्तीय प्रबंध, कार्मिक प्रबंध, सूचना प्रबंध और पद्धति प्रबंध सम्मिलित है।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था श्री एम० एम० कपूर, श्री वी० ए० कालपांडे, डा० आर० एस० शर्मा, श्री अरुण सी० मेहता और भी चमन सिंह ने की।

47. 07/85-86/02 **उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए संस्थागत योजना और मूल्यांकन पर कार्यशाला** (20-22 मई, 1985)

उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने संस्थान से दो-तीन दिन की कार्यशाला आयोजित करने का अनुरोध किया था। पहली कार्यशाला रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आयोजित की गई थी। कार्यशाला के उद्देश्य निम्न थे : भाग लेने वालों को संस्थागत योजना और मूल्यांकन की संकल्पना, प्रक्रिया और तकनीकों से परिचित कराना और राज्य में स्कूल स्तर पर संस्थागत योजना और मूल्यांकन की पद्धतियों के कार्यान्वयन के लिए क्रियात्मक योजनाएं तैयार करना। कार्यशाला में मुख्य रूप से संस्थागत योजना और मूल्यांकन की संकल्पना, प्रक्रिया और तकनीकों पर तथा स्कूलों में संस्थागत योजना और मूल्यांकन की पद्धतियों को लागू करने के लिए क्रियात्मक योजनाएं तैयार करने पर, विचार-विमर्श हुआ। इस कार्यशाला में भाग लेने वालों की संख्या 5 थी।

इसकी व्यवस्था श्री एम० एम० कपूर, कार्यक्रम समन्वयकर्ता श्री वी० ए० कालपांडे और श्री अरुण मेहता ने की।

48. 07/85-86/03 **स्कूल काम्पलेक्स के विशेष संदर्भ में दादरा और नगर हवेली शिक्षा के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम** (29 मई से 8 जून, 1985)

यह कार्यक्रम दादरा और नगर हवेली प्रशासन के अनुरोध पर संस्थान ने आयोजित किया था। उसके मुख्य उद्देश्य निम्न थे : भाग लेने वालों को शैक्षिक योजना और प्रशासन की वर्तमान प्रवृत्तियों से अवगत कराना;

शैक्षिक योजना और प्रशासन की महत्वपूर्ण संकल्पनाओं और तकनीकों से और स्कूल काम्प्लेक्सों की भूमिका मे परिचित कराना, और उन्हें शैक्षिक प्रशासक के रूप में व्यावसायिक क्षमता अर्जित करने में सहायता करना। कार्यक्रम में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई : शिक्षा की वर्तमान प्रवृत्तियां, सूक्ष्म शिक्षण, दादरा और नगर हवेली का शैक्षिक विकास, पर्यवेक्षण की आधुनिक संकल्पना, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजतीकरण की शैक्षिक योजना, संस्थागत योजना और मूल्यांकन, लेखों और प्रलेखों का रखरखाव और शैक्षिक विकास में समुदाय और सहयोग। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या 26 थी।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था श्री एम० एम० कपूर, श्री वी० ए० कालपांडे, और डा० आर० एस० शर्मा ने की।

49. .07/85-87/04 **उत्तर प्रदेश के शैक्षिक प्रशासकों के लिए संस्थागत योजना और मूल्यांकन का प्रशिक्षण कार्यक्रम** (1-3 जुलाई, 1985)

शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर संस्थागत योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न थे :—भाग लेने वालों को संस्थागत योजना और मूल्यांकन की तकनीकों से परिचित कराना और साथ ही साथ राज्य में स्कूल स्तर पर संस्थागत योजना और मूल्यांकन के कार्यान्वियन के लिए क्रियात्मक योजना का निर्माण करना। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 26 वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों ने भाग लिया था।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था सर्वश्री एम० एम० कपूर, बी० ए० कालपांडे, अरुण सी० मेहता और चमन सिंह ने की।

50. 07/85-86/05 **उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के लिए संस्थागत योजना पर कार्यशाला** (1-3 जुलाई 1985)

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अनुरोध पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न थे : भाग लेने वालों को संस्थागत योजना और मूल्यांकन की तकनीकों से परिचित कराना और राज्य में स्कूल स्तर पर संस्थागत योजना और मूल्यांकन के कार्यान्वयन के लिए क्रियात्मक योजना का निर्माण करना। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 26 वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों ने भाग लिया था।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था सर्वश्री एम० एम० कपूर, वी० कालपांडे, अरुण मेहता और चमन सिंह ने की।

51. 07/85-86/06 **प्रारंभिक स्तर पर गैर-औपचारिक शिक्षा के मूल्यांकन अध्ययन के लिए साधन; अभिकल्प और संक्रियात्मक योजना के निर्धारण पर कार्यशाला** (12-14 अगस्त, 1985)

शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर नीपा ने एक अनुसंधान परियोजना पर कार्य शुरू किया है। इस परियोजना में 9 शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए 9-14 आयु वर्ग के बच्चों की

गैर-औपचारिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परियोजना से संबंधित योजना के अकादमिक, वित्तीय, संरचनात्मक, और प्रशासनिक पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा। यह कार्यशाला सर्वेक्षण करने के लिए साधनों का निर्धारण करने और क्षेत्र अध्ययन आदि करने की योजना के लिए आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों के 6 परियोजना निदेशकों ने भाग लिया।

इस कार्यालय की व्यवस्था सर्वश्री एम० एम० कपूर, जी० खुराना, क्यू० नकवी०, वी० रामराव और जय प्रकाश ने की।

52. 07/85-86/07 **वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन पर 12 वां अभिविन्यास कार्यक्रम** (9-27 **सितंबर**,1985)

यह शृंखला का 12 वां कार्यक्रम था जिसका आयोजन संस्थान ने वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए किया था। इस अभिविन्यास कार्यक्रम का उद्देश्य शैक्षिक प्रशासकों को शैक्षिक नीति और योजना के विषय में, शैक्षिक विकास की नई प्रवृत्तियों, शिक्षा पर नई प्रौद्योगिकी के प्रभाव, और शैक्षिक प्रशासन की सामान्य समस्या और उनका हल खोज निकालने के लिए उचित परिप्रेक्ष्यों को विकसित कराने के संबंध में परिचित करवाना था। इस अभिविन्यास कार्यक्रम में 10 वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था श्री एम० एम० कपूर, डा० आर० एस० शर्मा, श्री वी० काल पांडे और श्री अरुण मेहता ने की।

53. 07/85-86/08 9 **शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में प्रारंभिक स्तर पर गैर-औपचारिक शिक्षा के मूल्यांकन अध्ययन के लिए साधनों, अभिकल्प और संक्रियात्मक योजना के निर्धारण के लिए तकनीकी कार्यशाला** (1-5 **अक्टूबर**, 1985)

शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर नीपा ने इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पहलुओं का बृहत, मूल्यांकन अध्ययन प्रारंभ किया। कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य निम्न थे : ऐसे सर्वेक्षणों के लिए सर्वेक्षण कार्यक्रम और निर्देश तैयार करना जिन्हें पूर्व-निरीक्षण के आधार पर मुद्रित कराया जा सके; क्षेत्र के कर्मचारी वर्ग के प्रशिक्षण और क्षेत्र-सर्वेक्षण करने के लिए क्रियात्मक योजना तैयार करना; मूल्यांकन अध्ययन की अकादमिक और गैर अकादमिक पहलुओं के बीच कार्य के समन्वय पर विचार-विमर्श करना। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्य-20 थी।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था श्री एम० एम० कपूर और श्री जी० खुराना ने की।

54. 07/85-86/09 **वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में 13वां अभिविन्यास कार्यक्रम** (10-28, **फरवरी**, 1986)

संस्थान ने शैक्षिक योजना और प्रशासन पर तीन सप्ताह का 13वां अभिविन्यास कार्यक्रम वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे : भाग लेने वालों को शैक्षिक योजना

और प्रशासन की कुछेक महत्वपूर्ण संकल्पनाओं और तकनीकों से परिचित कराना; स्कूल शिक्षा की योजना और प्रशासन से संबंधित समस्याओं और वर्तमान कठिनाइयों से अवगत कराना और शैक्षिक प्रशासक और पर्यवेक्षक के रूप में उन्हें कार्य करने के लिए व्यावसायिक सक्षमता अर्जित करने में सहायता करना। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या 17 थी।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था श्री एम० एम० कपूर, डा० आर० एस० शर्मा और श्री बी० के० पण्डा ने की।

08/आई एन टी/अन्तर्राष्ट्रीय एकक

55. 08/85-86/01 शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (14 जनवरी से 13 जुलाई, 1985)

इस कार्यक्रम का दूसरा चरण विशिष्ट राष्ट्रीय सन्दर्भ में क्षेत्र अनुसंधान परियोजना से संबंधित था, जो पूरा किया गया था। इसमें भाग लेने वाले देशों में अफगानिस्तान, भूटान, मारिशस, श्रीलंका और कुवैत थे। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न थे : भाग लेने वालों को विश्वव्यापी संदर्भ में तृतीय विश्व में शैक्षिक विकास से परिचित कराना, विशिष्ट राष्ट्रीय संदर्भ में शैक्षिक योजना और प्रशासन के मूलभूत नियमों, संकल्पनाओं और तकनीकों को समझने में मदद करना और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों में प्राप्त अनुभवों के आदान-प्रदान के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय समझ को प्रोत्साहन देना। विभिन्न पाठ्यक्रमों में जो विषय रखे गए थे उनमें भाग लेने वालों को क्षेत्रीय, तुलनात्मक संदर्भ में तृतीय विश्व की शैक्षिक योजना की संकल्पनाएं और तकनीकें; शैक्षिक योजना के मात्रात्मक पहलू; शैक्षिक सांख्यिकी और परियोजना योजना; अनुक्षवण और मूल्यांकन; संगठनात्मक व्यवहार : कार्मिक प्रबन्ध; वित्तीय प्रबंध और कार्यालय प्रबंध सम्मिलित थे। इसमें भाग लेने वालों की संख्या 12 थी।

इस कार्यकम की व्यवस्था डा० उषा नायर, सुश्री अंजना मंगलागिरी, डा० एस० क्यू० ए० नकवी और सुश्री सुनीता चुघ ने की।

56. 08/85-86/02 संयुक्त राज्य अमेरिका के सामाजिक अध्ययन पर्यवेक्षकों और पाठ्यचर्या परामर्शदाताओं के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति पर कार्यशाला। (8 जुलाई से 9 अगस्त, 1985)

भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान के अनुरोध पर और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से यह कार्यशाला, संयुक्त राज्य अमेरिका के पाठ्यचर्या परामर्शदाताओं और पर्यवेक्षकों के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति विषय पर आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न थे; भाग लेने वालों को संस्कृति और साहित्य कलाओं के बारे में, भारतीय धरती और लोगों के बारे में, परिवर्तनशील सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में कृषि, उद्योग और प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति के संवर्धन में भारत की भूमिका से परिचित कराना था और

अमेरिका के स्कूलों के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति विषय की पाठ्यचर्या का विकास करना था। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के 15 पाठ्यचर्या पर्यवेक्षकों और परामर्शदाताओं ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था डा० उषा नायर, सुश्री जय श्री जालाली और सुश्री सुनीता चुघ ने की।

57. 08/85-86/03 **शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा**
20 फरवरी से 19 अगस्त, 1986)

वर्ष 1983 में नई दिल्ली में हुई एशियाई देशों में यूनस्कों के राष्ट्रीय आयोग की उप-क्षेत्रीय बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि नीपा को और अधिक नियमित रूप में दक्षिण एशिया और तृतीय विश्व के अन्य देशों को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिए। इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए संस्थान ने शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम प्रारम्भ किया।

इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं : विश्वव्यापी संदर्भ में तृतीय विश्व में शैक्षिक विकास का मूल्यांकन, विशिष्ट राष्ट्रीय संदर्भों में अनुप्रयोग करने के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन के मूलभूत सिद्धांतों, संकल्पनाओं और तकनीकों की समझ को बढ़ावा देना, भाग लेने वालों की विश्लेषण सांख्यिकी व्याख्या पूर्वानुमान परियोजना निर्माण, आंकड़े एकत्रित करके उन्हें सूक्ष्म और बृहद शैक्षिक योजना के प्रक्रमण के लिए विकसित करना और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों में प्राप्त अनुभवों के आदान-प्रदान के जरिए क्षेत्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करना। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्गा 10 थी।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था डा० उषा नायर, कुमारी अंजना, मंगलागिरी, कु० जयश्री जालाली, कु० सुनीता चुघ और डा० सरोज पांडे ने की।

जी/एस बी/01/सामान्य

58. **हरियाणा के एक गांव की ग्राम शिक्षा समिति के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम** (अप्रैल 24, 1985)

24 अप्रैल, 1985 को पुनहाना में हरियाणा के पुनहाना ब्लाक की ग्राम शिक्षा समिति के 40 सदस्यों के लिए एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य उन्हें शिक्षा की आवश्यकता के बारे में सजग करना और छात्रों के नामांकन और प्रतिधारण के, जो क्रियाकलाप उन्होंने प्रारम्भ कर रखे हैं, उन्हें चालू रखने के लिए प्रेरित करना था। इस कार्यक्रम में जिन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ उनमें शिक्षा और समुदाय विकास, कृषि में शिक्षा का महत्व; शिक्षा और सामाजिक विकास; स्वास्थ्य शिक्षा लड़कियों की शिक्षा, प्रौढ़ और गैर-औपचारिक शिक्षा का महत्व सम्मिलित थे। इसमें भाग लेने वालों की संख्या 40 थी।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था प्रो० सत्यभूषण, डा० अजीज, डा० प्रमिला मेनन, श्री उस्मान खान और श्री सतपाल सिंह ने की।

59. जी/आर पी एस/02 नई शिक्षा नीति : योजना और प्रबन्ध पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (23-25 नवम्बर, 1985)

23 नवम्बर से 25 नवम्बर 1985 तक होने वाली इस संगोष्ठी में नई शिक्षा नीति के संदर्भ में शिक्षा पद्धति के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ था। विशेष रूप से इस संगोष्ठी के केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज "शिक्षा की चुनौती : नीति परिप्रेक्ष्य में" पर और दिल्ली, कलकत्ता, बंगलौर और बंबई में पूर्व आयोजित चार क्षेत्रीय संगोष्ठियों की सिफारिशों पर विचार किया गया था। संगोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य योजना और प्रबंध की वर्तमान स्थिति और इनकी कुछेक मुख्य समस्याओं पर विचार करना और शिक्षा की योजना और प्रबन्ध के सम्बन्ध में नीति वक्तव्य तैयार करना था। इस संगोष्ठी में समस्त देश से विधायकों, शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों, प्रबन्ध विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और पत्रकारों को निम्न विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया गया था, यथा; क्षेत्रस्तर पर संगठनात्मक संरचनाएं और प्रक्रिया, संस्थागत योजना और प्रवन्ध, कार्मिक, मानव संसाधन प्रबन्ध और मानव संसाधन विकास की शिक्षा के लिए संसाधन। इस संगोष्ठी में भाग लेने वालों की संख्या 55 थी।

संगोष्ठी के निदेशक डा० आर० पी० सिंघल थे।

60. जी/एस बी एन/03 मेवात क्षेत्र (जिला गुड़गांव) के 15 गांवों की महिलाओं के लिए पुनहाना में कार्यशाला (19-20 दिसम्बर, 1985)

नीपा ने पुनहाना में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, मेवात क्षेत्र के 15 गांवों की महिलाओं के लिए किया था। इस कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य निम्न थे : प्रारम्भिक स्वास्थ्य-विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जानकारी प्रदान करना; हितकारी योजनाओं के बारे में सूचना देना; सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की उन्नत प्रौद्योगिकी से अवगत कराना और लड़कियों के बीच सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा के संवर्धन के लिए नीति-निर्धारण करना। 15 गांवों से इस कार्यशाला में भाग लेने वाले की संख्या 30 थी।

इस कार्यक्रम की व्यवस्था प्रो० सत्य भूषण, डा० ए० अजीज, डा० पी० मेनन श्री सतपाल सिंह और श्री उस्मान खान ने की।

61. जी/आर पी एस/04 भारत में स्कूलों के लिए शिक्षक छात्र-अनुपात पर संगोष्ठी (26 फरवरी, 1986)

संगोष्ठी में शिक्षक-छात्र अनुपात अध्ययन पर कुछ मुख्य निष्कर्षों और महत्वपूर्ण सिफारिशों पर विचार-विमर्श हुआ। भारत में, कक्षा-आकार और इष्टतम शिक्षक-छात्र अनुपात अनोखा है क्योंकि छोटे और बड़े दोनों ही आकार की कक्षाएं विद्यमान हैं। 1982-83 के नमूने के आधार पर स्कूलों का वास्तविक शिक्षक छात्र अनुपात विभिन्न स्तरों पर इस प्रकार था : प्राथमिक स्तर पर 1 : 36, मिडिल स्तर पर 1 : 28.5, था : हाई-स्कूल स्तर पर 1 : 29, संगोष्ठी में इस मत पर सहमति थी कि शिक्षक की सार्थकता कक्षा के आकार पर

निर्भर न रहकर नवाचारी प्रणालियों पर निर्भर करती है। विभिन्न राज्यों में जो व्यापक भिन्नताएं कक्षा-आकारों में और शिक्षक-छात्र अनुपातों में विद्यमान हैं उन्हें दूर करने के लिए यह आवश्यक हैं कि समस्त राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय मानदण्डों का प्रयोग एक रूप से किया जाए। इष्टतम शिक्षक-छात्र अनुपातों के लिए बहुत-सी युक्तियां भी सुझाई गई हैं। इसमें नामांकन, स्कूल मानचित्रण, स्कूल खोलने और श्रेणी रहित स्कूलों आदि के लिए मानदण्डों के निर्माण के अलावा औसत छात्र उपस्थिति सम्मिलित है। ये उपाय सार्वजनीन प्रारम्भिक शिक्षा शीघ्र प्राप्त करने में, छात्र-उपस्थिति सुधारने में सहायता करेंगे और शिक्षकों के बेहतर निष्पादन में सहायक होंगे। इस संगोष्ठी में भाग लेने वालों की संख्या 42 थी।

इस कार्यक्रम के व्यवस्था दल में डा० आर० पी० सिंघल, श्री बी० के० पाण्डे और कु० रश्मि दीवान थे।

अनुबन्ध दो

चालू अनुसंधान अध्ययन

1. भारत में अवसरों की समानता और शिक्षा अवसरों के समकरण के विशेष संदर्भ में शिक्षा वित्त का अध्ययन—केरल और उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा पर एक केस अध्ययन (आई सी एस एस आर द्वारा आयोजित) (03/ई० एफ एन/04)

अनुसंधान दल में डॉ० सी० बी० पद्मनाभन्, परियोजता निदेशक और श्री बी० शिबा रेड्डी परियोजना सहअध्येता थे।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं : समानता और समता के लक्ष्यों के संदर्भ में शैक्षिक वित्त के संसाधनों के परिवर्तनों की जांच करना; अनुदान सहायता पद्धति को मिलाकर शिक्षा के वित्त तंत्र और इसका शैक्षिक अवसरों के विभाजन पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना।

यह अध्ययन मुख्य रूप से आनुभविक-व-विश्लेषात्मक रूप का है और यह केरल और उत्तर प्रदेश राज्यों के स्कूल शिक्षा तक ही सीमित है। आधार सामग्री केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रालयों से ली गई है, जो प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही प्रकार की हैं। संबंधित राज्यों के योजना दस्तावेजों, बजट रिपोर्टों और सांख्यिकीय सार बुलेटिनों का प्रयोग सूचना प्राप्त करने के लिए किया गया है। अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन जैसे एन० सी० ई० आर० टी के प्रकाशनों से भी परियोजना संबंधी सूचना प्राप्त की गई है।

1956-57 और 1980-81 के बीच स्कूल स्तर की शैक्षिक विकास की आधार सामग्री एकत्रित की गई है ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या इन दो राज्यों में इस अवधि के दौरान शैक्षिक अवसरों की असमानता कम हुई है। एकत्रित आधार सामग्री में संस्थाओं, नामांकन, नामांकन अनुपात आदि की संख्या सम्मिलित की गई हैं। जिससे जनसंख्या के विभिन्न भागों में विभाजित शैक्षिक अवसरों की जांच की जा सके। अध्ययन लगभग पूर्ण हो गया है और अंतिम अध्याय लिखे जा रहे हैं।

2. वर्ष 2000 में भारतीय शिक्षा—एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य (01/ई० पी एल/01)

इस अध्ययन के अनुसंधान दल में डा० ब्रह्म प्रकाश, परियोजना निदेशक, श्री एम० एम० खान, परियोजना सहअध्येता, श्री मनोज शर्मा, परियोजना सहायक, श्री इफ्तिकार अहमद, परियोजना सहायक और कु० मंजु

रूदोला, परियोजना सहायक शामिल हैं।

विशेष रूप से इस प्रस्तावित अनुसंधान परियोजना के निम्न उद्देश्य होंगे : शिक्षा में खंड विकास पर आधारित प्रवृत्ति को पहचानना। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर यह कार्य अखिल भारतीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर किया जाएगा, यथा; प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी और गैर-तकनीकी; शिक्षा का व्यावहारात्मक मॉडल प्रस्तुत करना : नामांकन के आकार, शिक्षकों की संख्या, संस्थाओं की संख्या और शिक्षा पर किए गए व्यय की गई राशि को महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक और जनांकिकीय चरों के साथ संबद्ध करने का प्रयास; वार्षिक प्रक्षेपों के समुच्चय का निर्माण करना : यह नामांकन, शिक्षकों की संख्या, संस्थाओं की संख्या और वर्ष 2000 तक व्यय राशि के लिए किया जाएगा, इन प्रक्षेपों के सामाजिक, आर्थिक और बजट निहितार्थों को तैयार करना : इससे प्राथमिकताएं की योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

वर्ष 1985-86 के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज तैयार किए गए थे :

01/ई पी एल/01.2	भारत में प्राथमिक शिक्षा—कुछ जनगणना साक्ष्य
01/ई पी एल/01-3	शैक्षिक योजना और प्रबंध के लिए अनुरूप मॉडलों के प्रयोग में प्राथमिक शिक्षा
01/ई पी एल/01.4	भारत में प्राथसिक शिक्षा-प्रवृत्ति विश्लेषण
01/ई पी एल/01.5	भविष्य के लिए शिक्षा योजना-विकास, समस्याएं और विकल्प

(विस्तृत जानकारी के लिए देखें भाग II अध्ययन 17-20)

3. कालेज के अध्यक्षों की भूमिका-निष्पादन (02 ई ए डी/02)

इस अध्ययन के अनुसंधान दल में डा० एन० एम० भागिया, परियोजना निदेशक, कु० प्रमिला यादव और श्री डी० एच० श्रीकांत, परियोजना सहायक शामिल हैं।

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं : कालेजों के अध्यक्षों की भूमिका की पहचान करना; अध्यक्षों की विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के निष्पादन की बारंबारता की खोज करना; कालेज-अध्यक्षों की भूमिका-निष्पादन के साथ कुछेक कारणों के संबंधों का पता लगाना।

कालेज अध्यक्षों के कार्य जैसे कि शिक्षक और छात्र अनुभव करते हैं उन्हें अलग-अलग किया गया था ताकि कालेज-अध्यक्षों की जो भूमिका निभानी है उनकी पहचान की जा सके। विभिन्न भूमिकाओं का वर्गीकरण इस प्रकार था : योजनाकार और नवाचारक, कार्यालय प्रबंधक, संसाधन व्यवस्थापक; शिक्षण कार्यक्रम पर्यावेक्षक; सह-पाठ्यचारी क्रियाकलात्मक संवर्धक; स्टाफ मूल्यांकक और अभिप्रेरक; परामर्शद और समन्वयकर्त्ता : शिक्षाविद और शिक्षक, कालेज का प्रतिनिधि, और समुदाय के साथ संपर्क कराने वाला।

दस विभिन्न भूमिकाओं के अंतर्गत कार्यों के आधार पर 23 मदों की एक प्रश्नावली का निर्माण किया गया था। प्रश्नावली का परीक्षण किया गया था जिससे उसमें प्रश्नों और उत्तर के वर्गों को अंतिम रूप देने में सहायता मिली।

इस अध्ययन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 129 कॉलेजों में से 50 कॉलेज स्तर बद्ध यादृच्छिक प्रतिदर्श के लिए चुने गए थे। प्रतिदर्श में, सरकारी और निजी प्रबंध के अंतर्गत कालेज, सहायता प्राप्त और बिना सहायता वाले कालेज और सहशिक्षा और महिला कालेज शामिल थे। इन कालेजों के प्रधानाचार्यों के

अलावा, प्रतिदर्श में, कालेजों के 4-5 प्राध्यापक भी शामिल थे।

इस अध्ययन में उपर्युक्त भूमिका-निष्पादन प्रश्नावली (आर पी क्यू), व्यक्तित्व-सामग्री प्रश्नावली (पी डी क्यू) केटेल की 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली (पी एफ क्यू) और संगठनात्मक स्वास्थ्य प्रश्नावली (ओ एच क्यू) शामिल की गई है।

भूमिका-निष्पादन और संगठनात्मक स्वास्थ्य प्रश्नावलियां कालेज के प्राध्यापकों पर और व्यक्तित्व सामग्री और केटेल की 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावलियां कालेज-अध्यक्षों पर लागू की गई थीं। 28 कालेजों से आधार-सामग्री प्राप्त हुई थी जो हर तरीके से पूर्ण थी। सामग्री का विश्लेषण आवश्यक सारणियां बनाने के पश्चात् कम्प्यूटर की सहायता से किया गया था।

रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

4. केरल में शिक्षा विकास का इतिहास (04/ई० पी० ओ/14)

इस अनुसंधान दल में प्रो० के० एम० पान्नितकर अवैतनिक परामर्शद और श्री ए० मैथ्यू, परियोजना सह-अध्येता थे।

इस अध्ययन का उद्देश्य ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक विकास का बृहत रूप से विश्लेषण करना है। विशेष रूप से इसके उद्देश्य निम्न है : केरल में भूतपूर्व राजसी प्रदेश त्रावणकोर कोचीन और वर्ष 1820 और 1947 के बीच मद्रास प्रेसिडेंसी के मालावार प्रदेश में विकसित हुई शिक्षा का विलेषण करना, वर्ष 1956 में केरल राज्य की स्थापना के पश्चात शिक्षा विकास की दिशाओं का अध्ययन करना, वर्ष 1956 के पश्चात शिक्षा में हुए द्रुत विकास के ऐतिहासिक कारणों की पहचान करना, केरल के उन शैक्षिक अनुभव की विशेषताओं की रूपरेखा तैयार करना जिनका अनुसरण अन्य राज्य कर सकते हैं।

इस अध्ययन में अपनाई गई कार्यनीति में सर्वेक्षण और ऐतिहासिक स्रोतों का संग्रह है, जिसे अभिलेखागारों और नई दिल्ली, त्रावणकोर, कोचीन और तमिलनाडु के राज्य शिक्षा विभागों के साथ-साथ राज्य योजना बोर्ड त्रिवेंद्रम और योजना आयोग से लिया गया था।

सुप्रसिद्ध शिक्षा विदों और सरकारी अधिकारियों के साक्षात्कारों की भी व्यवस्था की गई है।

दिल्ली से सामग्री संग्रह का कार्य पूरा हो गया है। सामग्री की जांच करके वर्ष 1947 से पूर्व की अवधि का प्रारंभिक मसौदा तैयार कर लिया गया है। क्षेत्र-दौरों को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है।

5. हरियाणा जिला गुड़गांव के पुनहाना खंड में 20 गांवों के समूह में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचार पद्धतियों पर आधारित क्रियात्मक अनुसंधान (जी/एस० बी० एन०/17)

इस अनुसंधान दल ने प्रो० सत्य भूषण, परियोजना निदेशक, डा० अब्दुल अजीज परियोजना सह अध्येता, डा० पी० मेनन, परियोजना सहायक, श्री उस्मान खां और श्री सतपाल कनिष्ठ परियोजना सहायक शामिल थे।

इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं : प्रयोग के जरिए बृहत, एकीकृत कार्यक्रम का विकास करना,

6-14 आयु वर्ग के बच्चों में साक्षरता का संवर्धन करना, सहभागिता अन्वेषण के द्वारा समुदाय को संबद्ध करना, समस्याओं की पहचान करना, योजनाओं का निर्माण और उनके कार्यान्वयन, परिवीक्षण और मूल्यांकन करना, और अन्य विकास एजेंसियों के कार्यक्रमों के शैक्षिक घटकों की पहचान करके उनके साथ सहबद्धता और समन्वय स्थापित करना और उसे प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के साथ जोड़ना।

इस परियोजना पर कार्य, देश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के महत्व को देखते हुए शुरू किया गया था। समुदाय को सहबद्ध करके प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को पूरा करने की संभावना के अध्ययन के लिए गुड़गांव जिले के पुनहाना खंड के 20 संस्पर्शी गांवों की चुना गया था। चुने गए क्षेत्र की जनसंख्या 20,830 है जिसमें 8.3 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के हैं। परियोजना का मुख्य लक्ष्य प्रयोग के जरिए चुनिंदा गांवों के समूह में विकास का बृहत एकीकृत कार्यक्रम बनाने का है। शिक्षा के दृष्टिकोण से परियोजना माता-पिता में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रही है जिससे कि 6-11 आयु वर्ग के वे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं या जिन बच्चों ने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करे बिना स्कूल जाना छोड़ दिया है, वे स्कूल जाना शुरू कर दें। परियोजना ने शिक्षा के गैर-औपचारिक कारकों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रौढ़ और गैर-औपचारिक शिक्षा पर बल दिया गया था। गांव शिक्षा समिति ने, औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में नामांकित छात्रों की स्कूल में बने रहने और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी सुनिश्चित करके, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रत्येक गांव में गांव अधिगम केंद्रों की स्थापना की गई थी जहां समुदाय की पुस्तकें और अधिगम सामग्री भी उपलब्ध कराई गई थी। इस परियोजना में हमेशा ही साक्षरता के लिए प्रेरणा जागृत करने की कोशिश की गई है, इसे समुदाय पर लादने की नहीं। यह परियोजना, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक शिक्षा कार्यक्रम की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वास्तविकता समझने में हमारी सहायता करेगी और समाज के कमजोर वर्गों के लिए हितलाभकारी होगी। इससे ग्रामीण समाज में समुदाय पहल के साथ विकास का सहभागी विकेंद्रित मॉडल का प्रचालन होगा।

6. इंजीनियरी कॉलिजों में कार्मिक संरचना (02/ई० ए डी/03)

इस अध्ययन के अनुसंधान दल में डॉ० एम० मुखोपाध्याय, परियोजना निदेशक और श्री सी० आर० के० मूर्ति परियोजना सहायक शामिल थे।

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं : इंजीनियरी संस्थाओं के विभिन्न वर्गों की विद्यमान स्टाफ संरचना का पता लगाना और देश में इंजीनियरी संस्थाओं के लिए व्यावहारिक वैकल्पिक स्टाफ संरचना का सुझाव देना।

समस्त भारत के 150 इंजीनियरी कालेजों को प्रोफार्मा और प्रश्नावलियां तैयार करके भेजी गई थीं। इसके अतिरिक्त, दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों के 28 इंजीनियरी कॉलिजों में जाकर गुणात्मक और मात्रात्मक सूचना एकत्रित की गई हैं। वैकल्पिक संरचना का विकास करने के लिए डेल्फी पद्धति अपनाई गई थी।

रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

7. इंजीनियरी कॉलिजों में तालिका प्रबन्ध (02/ई० ए डी/04)

इस अध्ययन के अनुसंधान दल में डॉ० मुखोपाध्याय, परियोजना निदेशक और श्री सी० आर० के० मूर्ति, परियोजना सहायक शामिल थे।

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं : इंजीनियरी कॉलेजों में तालिकाओं के स्वरूप की पहचान करना; विभिन्न प्रकार के इंजीनियरी, कॉलेजों; यथा, क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, स्टेट कॉलिज और विश्व-विद्यालय इंजीनियरी संकायों में प्रति छात्र तालिका दर की तुलना करना, विभिन्न प्रकार के इंजीनियरी कॉलेजों में प्रबंध-लागत के साथ तालिका-दर की तुलना और अध्ययन करना : तालिका प्रबंध के विभिन्न मॉडलों का विकास करना।

दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों के 8 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों, 13 स्टेट इंजीनियरी कालेजों और 7 विश्वविद्यालय इंजीनियरी कालेजों का अध्ययन किया गया था। समस्त कालेजों में जाकर प्रश्नावलियों साक्षात्कारों और अवलोकन द्वारा आधार-सामग्री एकत्रित की गई थी।

रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

8-16 नौ शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में 9-14 आयुवर्ग के बच्चों के लिए सार्वजनीकरण के लिए गैर-औप-चारिक शिक्षा की प्रायोगिक परियोजनाएं (07/एस एन एस/06.1)

07/एस एन एस/06.1	आंध्र प्रदेश
07/एस एन एस/06.2	असम
07/एस एन एस/06.3	बिहार
07/एस एन एस/06.4	जम्मू व काश्मीर
07/एस एन एस/06.5	मध्य प्रदेश
07/एस एन एस/06.6	उड़ीसा
07/एस एन एस/06.7	राजस्थान
07/एस एन एस/06.8	उत्तर प्रदेश
07/एस एन एस/06.9	पश्चिमी बंगाल

इस परियोजना के अध्ययन दल में श्री एम० एम० कपूर, अध्येता और अध्यक्ष, श्री जी० खुराना, परियोजना अध्येता, डा० एस० क्यू० ए० नकवी और श्री अरुण सी० मेहता, परियोजन अध्येता, श्री वी० रामाराव श्री जे० पी० मलिक और श्री एस० सी० बंसल, परियोजना अनुसंधान सहायक शामिल थे।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं : सफलताओं के क्षेत्रों की पहचान करना; वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की पुनः संरचना के लिए संभव नए उपागमों का सुझाव देना।

यह अध्ययन शैक्षिक रूप से पिछड़े समस्त 9 राज्यों : यथा, आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व काश्मीर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में शुरू किया गया है।

इस अध्ययन में, उपर्युक्त सभी राज्यों में सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए जा रहे गैर-

औपचारिक शिक्षा की योजना से संबंधित कार्य का मूल्यांकन किया गया है। यह बहुत ही बृहत् मूल्यांकन अध्ययन है, जिसमें इस योजना के समस्त पहलुओं, विशेष रूप से, अकादमिक वित्तीय, संरचनात्मक और प्रशासनिक पहलुओं पर, विचार किया गया है। यह संस्थान इस योजना के प्रशासनिक, वित्तीय और संरचनात्मक पहलुओं का और एन सी इ आर टी इसके अकादमिक पहलू का मूल्यांकन कर रहा है। मई, 1985 में राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी कार्यशाला में अध्ययन अभिकल्प को अंतिम रूप देकर राज्य सरकारों को भेजा गया था। अगस्त, 1985 में एक तकनीकी कार्यशाला का आयोजन क्षेत्र सर्वेक्षण करने के लिए साधनों, सारणीकरण योजना और निर्देशों की अंतिम रूप देने के लिए किया गया था।

विभिन्न स्तरों पर, इस अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए 14 अनुसूचियों का सेट तैयार किया गया है। सूचना एकत्र करने के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों, अनुदेशकों, पर्यवेक्षकों, शिक्षार्थियों, बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों, स्कूल जाने वाले बच्चों, जानकार व्यक्तियों, प्राथमिक/मिडिल स्कूलों, गांव व शहरों, ब्लाकों, जिलों, राज्यों और राज्य के शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों और स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए अलग-अलग अनुसूचियां तैयार की गई हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण समस्त राज्यों में पूरा हो चुका है और उनको समेकित किया जा रहा है। समेकन रजिस्टर तैयार करके सभी राज्यों को भेजे जा चुके हैं। क्षेत्र सर्वेक्षणों की सूचना की नमूना जांच की जा रही है ताकि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों की जांच की जा सके।

17. शिक्षा और विकास पर मोनोग्राफ (04/ई० पी० ओ/13)

इस अध्ययन के अनुसंधानों दल में डा० एस० सी० नूना, परियोजना निदेशक और श्री ओ० डी० त्यागी मानचित्रकार शामिल थे।

मानोग्राफ शिक्षा और विकास के बीच के संबंध को उजागर करेगा। इस अध्ययन से यह सिद्ध किया जाएगा कि शिक्षा और विकास द्विदिश रूप से जुड़े हुए और सतत रूप से परस्पर संपोषित है। इसके तीन भाग होंगे। पहले भाग में, विश्व के चुने हुए देशों में शिक्षा और जीवन-सूचकों की गुणवत्ता के बीच के संबंध की विशेषताओं को दर्शाया जाएगा। दूसरे में भारत में वर्तमान राज्य-स्तर की परिस्थितियां दर्शायी जाएंगी और तीसरे भाग में भारत में जिला-स्तर की स्थितियों को प्रस्तुत किया जाएगा। यह समस्त अध्ययन 18 मानचित्रों और 18 मानोग्राफों की सहायता से पूरा किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त इसमें श्रेणीकरण भी किया जाएगा जिसमें विश्व के चुनिंदा देशों, भारत के राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों और भारत के जिलों का श्रेणीकरण शैक्षिक विकास सूचकों के आधार पर किया गया है। इस अध्ययन का कार्य पूरा हो चुका है और रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

18. शिक्षा में परिवर्तन का प्रबन्ध (02/ई ए डी/05)

इस अध्ययन के अनुसंधान दल में प्रो० एम० मुखोपाध्याय, परियोजना निदेशक, कु० नलिनी जुनेजा, परियोजना सह-अध्येता और श्री सी० आर० के० मूर्ति, परियोजना सहायक शामिल थे।

इस अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैं : राष्ट्रीय, राज्य और संस्थागत स्तरों पर प्रमुख नवाचार कार्यक्रमों की पहचान करना; योजना की संप्रेषण प्रक्रिया, कार्यान्वयन और संस्थागत नवाचार कार्यक्रमों की संकल्पनात्मक शैली की प्रक्रिया का अध्ययन करना; बहुकेस विश्लेषण के जरिये परिवर्तन के प्रभावी प्रबन्ध की प्रक्रिया की पहचान करके परिवर्तन के लिए प्रबन्ध-मॉडल तैयार करना।

इस अध्ययन का कार्य अपने पहले महत्त्वपूर्ण चरण में है यथा परिवर्तन-प्रबन्ध के साहित्य का प्रलेखन और अध्ययनों का पुनरीक्षण।

स्वीकृत अध्ययन

1. उच्च शिक्षा में समता, गुणवत्ता और लागत (06/एच आर ई/04)

यह अध्ययन, पेसिफिक और एशिया में शिक्षा के लिए यूनेस्को का क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक द्वारा आयोजित देशों के अध्ययनों का एक भाग है।

इन अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं। भाग लेने वाले देशों में उच्च शिक्षा में समता, गुणवत्ता और लागत से सम्बन्धित मुद्दों और समस्याओं की खोज करना, भाग लेने वाले देशों को एक मंच पर एकत्रित करना और इन पहलुओं पर उनके अनुभवों का विश्लेषण करना और नीतियां, योजनाएं और उपाय प्रस्तुत करना ताकि लागत-प्रभावी विधियों द्वारा समता का संवर्धन और गुणवत्ता में सुधार हो सके।

2. भारत में साक्षरता : देश-काल सापेक्ष विश्लेषण (04/ई पी ओ/15)

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं वर्तमान शताब्दी के दौरान पूरे राष्ट्र में साक्षरता प्रसार के मुख्य लक्षणों की पहचान करना; साक्षरता में क्षेत्रीय विविधताओं को स्पष्ट करने के लिए व्याख्यात्मक मॉडल का विकास करना ताकि क्षेत्रीय विविधताओं के संदर्भ में नई नीतियों का निर्माण किया जा सके।

जहां तक प्रतिनिध्यात्मक और काल सापेक्ष विश्लेषण का सम्बन्ध है विश्लेषण के लिए सरल तकनीकों के साथ-साथ बहुचर मानचित्रीय तकनीकों का प्रयोग मूलभूत साधना के रूप में किया जाएगा। फिर भी विश्लेषण की प्रमुख समस्या, प्रशासनिक इकाइयों में परिवर्तन के फलस्वरूप कालसापेक्ष आधार-सामग्री के तुलना की होगी। इस समस्या को हल करने के लिए प्रक्षेप तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। साक्षरता में क्षेत्रीय विविधताओं को स्पष्ट करने के लिए व्याख्यात्मक मॉडल बनाने के लिए मानक सांख्यिकीय पैकेज का प्रयोग किया जाएगा। अनुसंधान स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है।

3. कालेजों का विकास और सफल संचालन : एक क्रियात्मक अनुसंधान अध्ययन (06/एच० आर० ई०/06)

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं : चुनिंदा कॉलेज के विकास और सफल संचालन की समस्याओं का विश्लेषण, यदि आवश्यक हो तो कालेज के विकास और सफल संचालन के लिए सुझाव प्रस्तुत करना; कालेज

को दिए गए सुझावों और सी ओ एस आई पी, सी ओ एच एस एस आई पी तथा यू एल पी जैसी विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए और सामाजिक आवश्यकताओं को शिक्षा से जोड़ने के और व्यावसायिक घटकों को लागू करने के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना करना; कालेज के निष्पादन और संचालन में परिवर्तन के प्रभावों की जांच करना; उनकी समस्याओं और उनके समाधानों पर विचार करना और ऐसा करने में जो अनुभव अर्जित हो, उसे कालेज प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में काम में लाना।

क्रियात्मक अनुसंधान में बेस, प्रक्रिया और संघात विश्लेषण सम्मिलित होते हैं। "बेस और संघात" विश्लेषण के लिए आनुभविक विश्लेषण प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। क्रियात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दौरान अर्जित अनुभव के जरिए प्रक्रिया विश्लेषण की प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। अनुसंधान स्टाफ की नियुक्ति की जा रही हैं।

4. **शिक्षा में संसाधनों का प्रभावी उपयोग एक केस अध्ययन** (03/ई० एफ० एन०/05)

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा पर किए गए कुल व्यय की दक्षता के साथ-साथ विभिन्न कार्यों के लिए शिक्षा में व्यय के आबंटन/उपयोग के पैटर्नों की दक्षता की जांच करना है।

यह अध्ययन भारत के शहरी और ग्रामीण प्रतिदर्श स्कूलों से एकत्र की गई आधार-सामग्री पर आधारित होगा। आधार-सामग्री सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों तथा प्रश्नावलियों पर आधारित होगी। अनुसंधान स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है।

अनुबन्ध तीन

संकाय का अकादमिक योग

पुस्तकें

डा० एस० सी० नूना

पापुलेशन एण्ड डिप्लेपमेंट—**टुवार्ड दी फस्ट सेन्टरी** परिवार नियोजन प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, 1985 (प्रो० मूनिस रजा के संयुक्त सहयोग से)

पुस्तकों में अध्याय

डा० सी० बी० पद्मनाभन

एजुकेशन, साइंस एण्ड टेक्नोलौजी—**इन सेवेंथ प्लान प्रोस्पेक्टिव**, डा० मलकोलम एस अदिसेसिया द्वारा संपादित (प्रो० एम० जी० के० मेनन तथा डा० अमरीक सिंह के साथ)

सिस्टम अप्रौच टू एजुकेशनल प्लैनिंग इन इंडिया, **इन सिस्टम अप्रौच: इटस् अप्रिसिएशन इन एजुकेशन**, प्रो० मोती लाल शर्मा द्वारा संपादित

रिसर्च एरियाज इन फिनांनसिंग आफ इंडियन एजुकेशन इन **क्वालिटी कंट्रोल इन एजुकेशनल रिसर्च**, डा० एस० के० पाल तथा डा० पी० सी० सक्सेना द्वारा संपादित।

डा० सी० एल० सपरा

ट्रेनिंग आफ एजुकेशनल प्लैनर्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स इन एन्वारनमैंटल एजुकेशन (प्रकाशनाधीन)
प्रोमार्टिंग इक्यूटी थ्रो नौनारमल ऐजूकेशन एण्ड ओपन लर्निंग सिस्टम एण्ड एजुकेशनल एम्पलॉयमेंट इंटरफेस विथ स्पेशल रेफ्रेंस टुडे इम्पलेमेंटेशन ऑफ वोकेशनलायीजेशन ऐट +2 स्टेज, सी० एल० सपरा और वाई० पी० अग्रवाल (संपादन) एजुकेशन इन इण्डिया : सम क्रिटिकल इसूज (प्रेस में)

डा० एन० एम० भागिया

सेन्ट्रेलाइजेशन एण्ड डी सेन्ट्रेलाइजेशन इन एजूकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजूकेशन
डा० के एस० भट्ट तथा एस० रविशंकर द्वारा संपादित (सीना प्रकाशन)

न्यू वैल्यूज एण्ड एजुकेशन **इन ह्यूमन वैल्यूज एण्ड एजुकेशन** डा० एस० पी० रुहेला द्वारा संपादित, स्ट्रलिंग प्रकाशक

डा० ऊषा नायर

ब्रेन ड्रेन :: ब्रेन ड्रेन हाऊ टू रिवर्स इट शीर्षक से पुस्तक में ब्रेन ड्रेन के कारण, डा० एस० के० चोपड़ा,

तकनीकी तथा राष्ट्रीय विकास संघ, द्वारा मार्च, 1986 में संपादित ।
कल्चरल रूटस ऑफ ऑप्रेशन : 'पैटर्न आफ वुमैन एजुकेशन इन इंडिया : **वुमैन ऑपरेशन : पैटर्न एण्ड पर्सपेक्टिव**, सुशीला कौशिक द्वारा संपादित, शक्ति बुक्स 1985

डा० कुसुम प्रेमी

टेर्निंग आफ करीकूलम डब्लपरस इन **एनवाय रनमेंटल एजुकेशन** (यूनेस्को द्वारा प्रकाशनाधीन)

डा० सुषमा भागिया

एप्रोचिस इन वल्यू एजुकेशन **इन ह्यूमैन वैल्यूज एंड एजुकेशन**, एस० पी० रुहेला द्वारा संपादित, स्ट्रलिंग प्रकाशक, 1985

डा० जे० बी० जी० तिलक

"लांग टर्म एजुकेशन प्लैनिंग", इन्ट्रोडक्टरी ऑवरव्यू "एजुकेशन इन एन अनइक्यूल वर्ल्ड" एंड इन एजुकेशनल प्लैनिंग : अलांग पर्सपेक्टिव कॉनस्पेट, नई दिल्ली (प्रो० मूनिस रज़ा के साथ)

"प्लेनिंग टिचर्स एजुकेशन" इन **रिर्सोसबुक ऑन टिचर ऐजुकेशन** (नई दिल्ली, एन सी इ आर टी) (प्रकाशित होनी शेष है)

डा० एस० सी० नूना

फरेगमन्टेशन आफ पालिटिकल विहेवियर इन इंडिया : अ ज्योग्राफिकल एनेलिसिस आफ इलैक्ट्रोरल टेड" ए० वी० : मुखर्जी तथा ए अहमद ब (संपादन) इंडिया : कलचरल सोसाइटी एण्ड इकानमी : ज्योग्राफिकल ऐसेज, इंटर इंडिया, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1985
"इन्इक्यूटी इन द लिट्रसी लेविलस आफ पापुलेशन आफ महाराष्ट्र" मूनिस रजा (**एजुकेशनप्लैनिंग अ लांग टर्म परस्पैक्टिव**" नीपा, नई दिल्ली, 1985)

सुश्री जय श्री जलाली

"एजुकेशन इन नॉन-एलायिड कन्ट्रीज" डी आर गोयल द्वारा संपादित "**नान-एलायंडमेंट—प्रोस्पैक्ट एण्ड पर्सपैक्टिवस**" अजंता प्रकाशन, नई दिल्ली, फरवरी 27, 1986

अनुसंधान पत्र/प्रकाशित लेख

डा. आर. पी. सिंघल

"इन सर्च आफ न्यू मॉडलस ऑफ सैकडरी एजुकेशन" इन रिपोर्ट आफ द टास्क फोर्स मिटिंग आफ ए पी इ आर डी, यूनेस्को, बैंकोक, 1985

"एजुकेशन इन जापान" जरनल आफ इंडियन एजुकेशन में प्रकाशित खंड 10, नं० 2 एन सी इ आर टी

"रिफोर्मिंग यूनवर्सिटी एक्जामिनेशन सिस्टम" यूनिवर्सिटी न्यूज में प्रकाशित, ए आई यू, मई 8, 1985

"पापुलेशन एण्ड डिप्लपमैंट" डिप्लपमैंट पालिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में प्रकाशित, एसोसियेटिड प्रकाशन हाउस,

रिफार्मिंग यूनिवर्सिटी इक्नामिजेशन : अ सर्च फार इन ऑरटेनेटिव इन सन्गम, के वी एस

डा० सी० बी० पद्मनाभन

फिसकल इंक्यूलाईजेशन फोर एजुकेशन इन सैवेंथ प्लान" हिंदू में; जून 25, 1985

फनानसिंग एंड इक्वालिटी आफ ऑपरचुनिटी इन परस्पैक्टिव इन एजुकेशन", 1985 खंड 1 संख्या 3

फिनानसिंग आफ एजुकेशन इन सैवेंथ प्लान—"न्यू फ्रंटीयरस इन एजुकेशन" अप्रैल-जून, 1985

टुवार्डस अ रेशनल फिनानसिंग पालिसी इन योजना नवम्बर 1985 टुवार्डस अ रियलिस्टिक फिनानसिंग पालिसी फार इंडियन एजुकेशन-**एजुकेशन क्वाली**' ऑटम 1985, खंड XXXVII नं० 3

रिर्सोस कन्सट्रेंटस फार इंडियन एजुकेनार्टशन-जरनल आफ इंडियन सोशल **इन्सच्चूट सोशल एक्शन** खंड 36, जनवरी, मार्च 1986

फिनानसियल मैंनेजमैंट इन इंडियन एजुकेशन-अ फंकशनल अप्रोच **इन इन्डियन एजुकेशन रिव्यू** अक्टूबर, 1985

डा० एन० एम० भागिया

"सैक्स डिफरेंस इन दी एरियाज आफ स्कूल एडजस्टमैंट ऐट वैरियस लेवल आफ इंटैलिजेंस" **एजुकेशनल हैरल्ड** में, खंड 16, नं० 2 जुलाई सितम्बर, 1985

फ्यूचर आरियंटिल एजुकेशन फार टिचर्स" टुडे के आगामी अंक में प्रकाशित होने के लिए स्वीकृत।

डा० एम० मुखोपाध्याय

"एजुकेशन मैंनेजमेंट : चेलेंज सफोर प्रोफेशनलायीजेशन" **पर्सपैक्टिव इन एजुकेशन**' पत्रिका में प्रकाशित खंड 2 नं 2,1985

मैंनेजमैंट आफ एजुकेशनल टैक्नोलॉजी : न्यू चलेंजिस इन एजुकेशन" द **एजुकेशन क्वाटर्ली** : पत्रिका में, भारत सरकार, 1985

श्री एम० एम० कपूर

"गर्ल्स एजुकेशन एट एलिमेंट्री स्टेज इन इंडिया, एन ओवरव्यू फॉर कन्सीट्रेशन आफ यूनेस्को रिजीनल पैनल ऑन एजुकेशन

डा० जे० बी० जी० तिलक

"एजुकेशनल प्लैनिंग ऐट डिस्ट्रिक लेवल 17/3, अप्रैल, 1985
ग्रोथ आफ लिट्रेसी इन इंडिया', अ रिज्यार्डर इंडियन जरनल आफ आडिट एजुकेशन खंड नं० 46, नं० 8 अगस्त, 1985
पालिटकल इकान्मी आफ इन्वैस्टमैंट इन एजुकेशन : **अ रिप्लाई, इंटरनेशनल जरनल आफ एजुकेशनल डिप्लपमैंट (प्रेस में)**

डा० उषा नायर

"एजुकेशन एंड इम्प्लायमैंट फार वुमैन इन इंडिया" **टुवार्डस इक्यूल स्टेटस**, मदर टैरसा महिला विश्वविद्यालय कोडाई कैनाल, प्रकाशन 2
"ब्रेन ड्रेन : कोसिज कान्सिक्यूसिस एंड प्रपोज्ड सॉलूशन्स मैनस्ट्रीम, नई दिल्ली।
एजुकेशन आफ वुमैन इन साउथ एशिया पेट्रियाट, ट्रिबून तथा इंडिया न्यूज क्रोनिकल द्वारा प्रकाशित अंक प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया फीचर।
"कापरेटिव इन एजुकेशन अ पी टी आई फीचर, ट्रिबून में प्रकाशित, फरवरी, 12, 1986
"वूमैन एजुकेशन इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टु साइंस एजुकेशन" एसोसियशन आफ वुमैन साइंटिफिक वर्क्स के बुलेटिन में प्रकाशित फरवरी, 1986 अंक, खंड 15, नं० 2
एजुकेशन आफ वुमैन : अ मैजर पोजेयर फोर द कोमनवैल्थ" सी सी इ ए न्यूजलैटर में प्रकाशित खंड 6 नं० 6 सितम्बर, 1985
"एजुकेशन : चलैंज फार सार्क (ऐसोसियशन आफ साउथ एशियन रिजनल कॉपरेशन) बिजनिस स्टैंड्रड कलकत्ता, द्वारा प्रकाशित दिसम्बर 31, 1985

डा० कुसुम के० प्रेमी

"इक्यूलाइजेशन आन एजुकेशन औपरच्यूनिटिज इन इंडिया : रिव्यू आफ पौलिसी एण्ड डारेक्शन फार न्यूज पालिसी इन आई. ए. ई. पी. ए. बुलेटिन खंड 1 नं० 2, 1985
"एजुकेशन, इक्वालिटि एंड इक्नॉमिक आपरच्यूनिटीज **जरनल आफ हायर एजुकेशन** स्प्रिंग अंक में, 1984 (1985 में निकाला गया)

डा० सुषमा भागिया

"फोर्सल कॉलिग फोर इनोवेशन इन द प्रेजंट इंडियन एजुकेशन" द **इंडिया एजुकेशन मैगजीन : 35, नं० 3** व 4 जुलाई-सितम्बर, 1982

"मैनेजमेंट आफ इनोवेशन इन हायर एजुकेशन" न्यू फरंटियर इन एजुकेशन खंड 15 नं० 3, जुलाई-सितम्बर, 1985

"एडल्ट एजुकेशन इन आस्ट्रेलिया : इटस इम्पलीकेशन इन इंडिया" द उड़ीसा एजुकेशन मैगनीज, खंड 24 नं० 3, सितम्बर, 1985

"डिप्लपमैंट इन नॉन फोरमल एजुकेशन" द राजस्थान बोर्ड जरनल आफ एजुकेशनल, खंड 21, नं० 3 व 4 जुलाई-सितम्बर, 1985

"वैल्यू ऑरिंटिड एजुकेशन द राजस्थान बोर्ड जरनल आफ एजुकेशन, खंड 22 नं० 1, जनवरी, मार्च, 1986

डा० के० सुधाराव

"रोल आफ क्वालिटी इन यूनिवर्सिलाइजेशन ऑफ इलेमेट्री ऐजुकेशन" **एजुकेशन क्वार्टली** स्प्रिंग, संस्करण, 1985

सुश्री जयश्री जलाली

लिंकिंग वर्क विथ एजुकेशन : अ कम्पैरिटिव स्टडी एट द स्कूल लेवल अस्पटिड फार पब्लिकेशन इन द जरनल आफ इंडियन एसोसियशन आफ एजुकेशनल प्लैनरस एण्ड एडमिनिस्ट्रेरस

"सिटीजैन्स कान्सैन्स" आरटिकल पब्लिशड इन **बिजनिस स्टेंडर्ड** फिचर स्टोरी, सितम्बर 21, 1985

"एजुकेशन पालिसी—अ लांग शेडो आफ स्कूल संट्रेलाइजेशन" पब्लिश्ड वॉय **बिजनिस स्टेंडर्ड**, कलकत्ता फववरी 27, 1986

डा० आर० एस० शर्मा

ऐक्शन प्लान आफ द एजुकेशन आफ द हैंडीकैप्ड, पब्लिशड इन भारतीय आधुनिक शिक्षा एन सी. ई. आर. टी. द्वारा प्रयोजित एक जरनल, नई दिल्ली नं० 2, अक्टूबर, 1984

पुस्तक/पत्रों की समीक्षा

डा० सी० वी० पदमनाभन

"इम्प्लामैंट प्रॉब्लम आफ ग्रेजुएट" शीर्षक से प्रो० पारवाथमा द्वारा लिखित पुस्तक की समीक्षा।

डा० सी० एल० सपरा

"**इन्डियन एजुकेशन दी रिव्यू**" एनसीइआरटी के जरनल में" एजुकेशन बैस्टेज" पर दो अनुसंधान पत्रों की समीक्षा मई, 1985

डा० जे० बी० जी० तिलक

"अचीवमेंट आफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन" (जे० पुरवाइज एंड हल्स) एंड द सोशियोलॉजी आफ एजुकेशन (जे० बेलंनटाइन) ब्रिटिश जरनल आफ सोशियालॉजी/36/2 जून, 1985

इकानामिक आफ हायर एजुकेशन इन तमिजनाडु (पी० पी० जार्ज) काइक्लोम 30/2) (1985)

"एजुकेशन प्लैनिंग" (ओ इ सी डी) इन ऐट रचेंज जून 1985 (प्रेस में)

इन्स्टोलमेंट इन एजुकेशन एंड सोसल चास (ठी. मयूमहार) परस्पैक्टिव इन एजुकेशन 6/22/1 जनवरी, 1986

प्रबुद्ध व्यक्तियों की सभाओं को संबोधित किये जाने वाले व्याख्यान

प्रो० सत्य भूषण

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में समापन भाषण अप्रैल 30, 1985

लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया जुलाई 3-5; 1985

लाइओला कॉलिज मद्रास में "स्वायत्तता प्राप्त कॉलेजों में "मूल्यांकन तथा प्रशासन का नियोजन" पर संगोष्ठी तथा कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया, 31 अगस्त, 1985;

गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली में भारतीय शैक्षिक प्रौद्योगिक संघ द्वारा आयोजित शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का उद्घाटन, 2 दिसम्बर, 1985;

राष्ट्रीय रक्षा के लिए, नई दिल्ली में "भारत में शिक्षा तथा उसका प्रभाव तथा सामाजिक परिवर्तन" विषय पर पैनल चर्चा में भाग लिया, 2 जनवरी, 1986;

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, नई दिल्ली में भाग लेने वालों के लिए अंतक्षेत्रीय समन्वय विषय पर संबोधित एक व्याख्यान फरवरी, 12 से फरवरी 19, 1986;

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली में गैर-औपचारिक शिक्षा वार्षिक सम्मेलन को सम्बोधित किया, फरवरी 13, 1986;

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली में शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन में 'राष्ट्रीय शिक्षा तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी' विषय पर योजना सत्र में व्याख्यान दिया, फरवरी 21, 1986;

दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली के दिल्ली स्कूल टेलिविजन ब्रांच के प्रधानाचार्य तथा उपप्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिक में अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों को उद्घाटन भाषण द्वारा सम्बोधित किया मार्च 4, 1986;

दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए संस्थागत नियोजन पर कार्यशाला का उद्घाटन, मार्च 6, 1986;

भारतीय जनसंचार माध्यम संस्थान, नई दिल्ली में संचार के विकास पर आयोजित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों को ग्रामीण भारत में शिक्षा की भूमिका विषय पर सम्बोधित किया, दिसम्बर 25, 1985;

टाइम्स आफ इण्डिया अनुसंधान प्रतिष्ठान, टी आर एम स्कूल, पत्रकारिता स्कूल में 'शिक्षा में ग्रामीण शहरी विधि' विषय पर भाषण दिया, फरवरी 20, 1986;

आई आई ई पूणे में माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण विषय पर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित किया, मार्च 29-30, 1986;

डा० सी० बी० पदमनाभन

आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली में "मानव संसाधन नियोजन" विषय पर दो व्याख्यान दिए, दिसम्बर 3, 1985;

डा० सी० एल० सपरा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित ए पी ई आई डी यूनेस्को परियोजना के अंतर्गत "स्कूल छोड़ जाने वालों तथा कक्षा दोहराने वालों की समस्याओं से निपटने के लिए प्राथमिक शिक्षा कार्मिकों के पुनः प्रशिक्षण के लिए कुशल नीतियों के विकास की परियोजना में विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया। अगस्त 6-9 1985;

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा आयोजित वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में "मेज़र्जमेंट आफ एजुकेशनल वेस्टेज" विषय पर व्याख्यान दिया, 23 सितम्बर, 1985;
एस आई ई, दिल्ली में पर्ट तथा सी पी एम पर भाषण दिया, फरवरी, 26, 1986;

डा० एन० एम० भागिया

भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली में "इम्पेरेटिव इन एजुकेशन" शीर्षक से संगोष्ठी में शिक्षा की गुणात्मकता के आधुनिकीकरण तथा सुधार विषय पर व्याख्यान दिया अप्रैल, 27, 1985;
दिल्ली तमिल शैक्षिक संघ स्कूलों के अध्यापकों के लिए गुणवत्ता शिक्षा तथा विकास पर संगोष्ठी को संबोधित किया, मई 14, 1985;

ए ई सी प्रशिक्षण कालेज तथा केन्द्र, पंचमढ़ी द्वारा चलाए जाने वाले आवश्यकता पर आधारित विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना पर संगोष्ठी को सम्बोधित किया तथा उसमें भाग लिया मई 26-31 1985;

श्री महेश अध्यापक प्रशिक्षण कालेज के स्टाफ तथा विद्यार्थियों के लिए 'शिक्षा में गुणात्मक सुधार' विषय पर व्याख्यान दिया, जुलाई 1-2, 1985;

बंबई के अध्यापक प्रशिक्षण कालिज, बंबई के स्टाफ तथा विद्यार्थियों के लिए संगठनात्मक स्वास्थ्य पर व्याख्यान दिया, सितम्बर 14, 1985 राम (आर ए ए जी)

बम्बई में "शिक्षा में कम्प्यूटरों के प्रयोग" विषय पर भाषण दिया, सितम्बर 15, 1985;

राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान नई दिल्ली द्वारा प्राग्विद्यालय कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानों के लिए आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम में "प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रविधियां तथा विधियां" विषय पर भाषण दिया, सितम्बर 24, 1985;

राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली में अनुसंधान प्रणाली विज्ञान पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए साहित्य के सर्वेक्षण पर व्याख्यान दिया, दिसम्बर 4, 1985

अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त स्कूल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में नवयुवक कार्यकर्त्ताओं तथा विद्यार्थी संगठनों द्वारा विश्व शांति की प्राप्ति विषय पर व्याख्यान दिया, दिसम्बर 24, 1985;

राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों के मुख्य प्रशिक्षणार्थियों के लिए आयोजित कार्यशाला में 'केस विधि क्या है और उसकी अनुपयुक्तता' विषय पर एक व्याख्यान दिया तथा संकाय विकास के चिकित्सा कालेज में 'समुदाय औषधि' विषय पर भी भाषण दिया, मार्च 11, 1986;

डा० ब्रह्म प्रकाश

अनुप्रयुक्त मानव शक्ति संस्थान में "शिक्षा तथा रोजगार अनुबन्धन" पर दो व्याख्यान दिए, अप्रैल 22-28, 1985;

राज्य शिक्षा संस्थान, दिल्ली में 'पद्धति उपागम' पर व्याख्यान दिया, मार्च 6, 1981;

डी० जी० डी० शर्मा

गवर्नमेंट पोलिटेक्नीक चण्डीगढ़ में 'नियोजन तथा संगठन-प्रशासन की भूमिका' विषय पर व्याख्यान दिया, जून 14, 1985;

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में उप रजिस्ट्रारों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम में व्याख्यान दिया, दिसम्बर 3, 1985;

डा० एम० मुखोपाध्याय

भारतीय महिला उद्यमियों की परिषद नई दिल्ली में भाग लेने वालों के लिए "ग्रुप डिनेमिक्स" विषय पर व्याख्यान दिया, अप्रैल 9, 1985

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में "क्वालिटी एण्ड क्वांटिटी" विषय पर व्याख्यान मई 31, 1985;

गुरु हर कृष्ण पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली में "मैनेजमेंट आफ क्लासरूम" शीर्षक से व्याख्यान जून 6, 1985;

बाल भवन, नई दिल्ली में "फ्यूचर पर्सपैक्टिव ऑफ सोशल चैंज" शीर्षक पर व्याख्यान, जुलाई 6, 1985;

आई एस टी ई, नई दिल्ली तथा आर ई सी श्रीनगर, श्रीनगर में आयोजित संयुक्त कार्यक्रम में "लिकेज बिटवीन फॉरमल टेकनीकल एजुकेशन एण्ड इंडस्ट्री" शीर्षक से व्याख्यान, सितम्बर 6, 1985;

शिक्षा विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में "इम्रजिंग न्यू पालिसी आन एजुकेशन" शीर्षक से व्याख्यान अक्तूबर 8, 1986;

सेंट जैवियर स्कूल, नई दिल्ली में 'चैलेंज इन एजुकेशन-पालिसी पर्सपैक्टिव' शीर्षक से व्याख्यान, 1985;

यूके शिक्षा उन्नयन समिति, होराह में "पालिसी पर्सपैक्टिव इन एजुकेशन" शीर्षक से व्याख्यान, नवम्बर 11, 1985;

पी एस आई पी ए चण्डीगढ़ में 'मैनेजमेंट आफ एजुकेशन सिस्टम' शीर्षक से व्याख्यान, दिसम्बर 11, 1984;

इण्डिया इण्टरनेशनल सैन्टर, नई दिल्ली में 'गुणात्मक शिक्षा' शीर्षक से व्याख्यान, फरवरी 1, 1986;

पी एस आई पी ए, चण्डीगढ़ में 'इनोनेशन इन एजुकेशन सिस्टम' शीर्षक से व्याख्यान, फरवरी 11, 1986;

एन सी ई आर टी, नई दिल्ली में 'मैनेजमेंट ऑफ चेंज इन टीचर एजुकेशन' शीर्षक से व्याख्यान, फरवरी 12, 1986;

डा० ऊषा नायर

बाल भवन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित युवा सभा में "एजुकेशन एण्ड फ्यूचर" पर व्याख्यान दिया 27 अप्रैल, 1985

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विशेष संदर्भ सहित भारत में महिला शिक्षा पर (73 वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान पाठ्यक्रम) व्याख्यान दिया 2 जनवरी, 1986

डा० (श्रीमती) कुसुम के० प्रेमी

एन सी ई आर टी द्वारा प्रायोजित "डिव्लपमेंट ऑफ सिलैबाई फॉर की लेबल फंक्शनरीज आफ नॉन फार-मल एजुकेशन टु ओवरकम प्रोब्लम विच हिंडर एजुकेशन डिव्लपमेंट ऑफ एस सी एस" विषय पर कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया 18-20, 1986;

डा० सुषमा भागिया

श्री महेश अध्यापक प्रशिक्षण कालेज के स्टाफ तथा विद्यार्थियों को "क्वालिटी इन एजुकेशन एण्ड इनोवेशन" विषय पर सम्बोधित किया, 2-7, 1985;

बम्बई अध्यापक प्रशिक्षण कालेज, बम्बई के स्टाफ तथा विद्यार्थियों के लिए "पौपुलेशन एजुकेशन एज एन इनोवेशन" विषय पर व्याख्यान 14-9-1985;

डा० (सुश्री) के० सुधाराव

दिल्ली कर्नाटक सूचना केन्द्र में "रोल ऑफ फिल्मस् इन इनक्लकेटिंग वैल्यूज इन कॉमन प्यूपिल" शीर्षक सें व्याख्यान जून 23, 1985;

एन सी ई आर टी द्वारा संचालित अनुसंधानकर्त्ता दिवस संगोष्टी में "मैनेजमेंट इफैक्टिवनैस" विषय पर एक सत्र की अध्यक्षता, नवम्बर 7, 1985;

एम० एम० कपूर

मध्य प्रदेश के आदिवासी स्कूलों के मुख्याध्यक्षों तथा अधिकारियों के लिए 'संस्थागत नियोजन तथा मूल्यांकन' पर व्याख्यान परिचर्या : सितम्बर 11-15, 1985;

भारतीय केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा आयोजित 'अनुप्रयुक्त सांख्यकी में उन्नत प्रशिक्षण' पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों के लिए 'भारत में शैक्षिक प्रबन्ध पद्धतियों' विषय पर व्याख्यान, सितम्बर, 1985;

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हरिद्वार सें वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए आयोजित एक संगोष्ठी में 'संस्था-गत नियोजन' विषय पर व्याख्यान, जनवरी 29, 1986;

डा० जे० बी० जी० तिलक

आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली में "इंस्टिट्यूशनल प्लैनिंग इन इण्डिया" शीर्षक पर दो व्याख्यान, सितंबर 12, 1985;

'शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास' पर दो व्याख्यान (आन्ध्र विश्वविद्यालय वल्टियर, जून 25, 1985;

आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली में "ह्यूमैन रिर्सोसिज प्लेनिंग" पर दो व्याख्यान दिसम्बर 3, 1985;

डा० आर० एस० शर्मा

एन सी ई आर टी, नई दिल्ली में विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा से सम्बन्धित विशेषज्ञ व्यक्तियों के लिए तीन माह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में तीन व्याख्यान दिसम्बर, 1985;

एस सी इ आर टी, हरियाणा, गुड़गांव में हरियाणा राज्य के अधिकारियों के लिए आयोजित संगोष्ठी में 'आन एजुकेशन टैक्नोलोजी : द रोल ऑफ डी इ ओ' शीर्षक से व्याख्यान, जनवरी 20-28, 1986;

डा० वाई० पी० अग्रवाल

एस आई ई में 'संस्थागत नियोजन के संसूचकों' पर व्याख्यान, फरवरी 26, 1986;
अध्यापक टैक्नीकल प्रशिक्षण संस्थान चंडीगढ़ में 'शिक्षा तथा आर्थिक विकास' पर व्याख्यान, मार्च 14, 1986;

डा० एन० वी० वर्गीस

एस आई ई में 'संसाधन प्रबंध तथा संस्थागत नियोजन' विषय पर भाषण, फरवरी, 26, 1986;

सुश्री मीना श्रीवास्तव

इन्सच्यूटो कीओपरेटीओन यूनिवर्सिटिया, रोमा, इटली में इम्पोर्टेंस आफ ट्रेड एन अ फैक्टर आफ इक्नोमिक डिप्लवमेंट एण्ड लोकल सिस्टम आफ गवर्नमैंट इन इंडिया' शीर्षक से व्याख्यान।

रेडियो पर वार्ताएं

डा० एस० सी० नूना

आल इंडिया रेडियो जगदलपुर में 'मीट गैस्ट ऑफ द वीक' कार्यक्रम के अंतर्गत एक वार्ता अक्तूबर 1985;

अकादमिक सम्मान

डा० एस० एम० आई० ए० जैदी

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त समाज विज्ञान में वाचस्पति की उपाधि। शोध निबंध का विषय है : **'पोलिटिक्स पॉवर एंड लिडरशिप'—अस्टडी ऑफ अ विलेज इन द डिस्ट्रिक ऑफ बाराबंकी'**

डा० सुषमा भागिया

आस्ट्रेलिया में अनुवर्ती तकनीकी तथा दूर की शिक्षा विशेष संदर्भ में एडल्ट एजुकेशन कैनवारा (आस्ट्रेलिया) में एशियन साउथ पैसिफिक ब्यूरो द्वारा प्रदान की जाने वाली यात्रा अध्येतावृत्ति (अक्तूबर 1984-फरवरी 1985)।

अनुबंध चार

आगंतुक गण

विदेशों से

—श्री पीटर डी स्नैलसन, निदेशक, अध्येतावृत्ति तथा प्रशिक्षण।
(कामनवेल्थ फाउन्डेशन फॉर टेकनिकल कौंसिल) लंदन —ड० अली फकरों, शिक्षामंत्री वहरान।

—डा० अब्दुल मजीद, महानिदेशक, योजना, अदन, विश्वविद्यालय, यमन।

—श्री कांति विश्वास, शिक्षामंत्री (स्कूल शिक्षा) पश्चिम बंगाल।

—डा० इराज जइमैन, शैक्षिक प्रबंध परामर्शदाता, एशिया तथा पैसिफिक में यूनेस्को का क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकॉक।

—श्री विकास सान्याल, कार्यक्रम विशेषज्ञ, आई आई ई पी पेरिस।

—अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पाकिस्तान तथा निदेशक, शैक्षिक योजना संस्थान पाकिस्तान।

—श्री अब्दुल गफूर, कार्यक्रम विशेषज्ञ, पर्यावरण शिक्षा अनुभाग, विज्ञान, तकनीकी तथा पर्यावरण-शिक्षा विभाग, 7 प्लैस द फौनटेवॉय, रियू मिओलिस 75015 पेरिस।

—विभिन्न विकासशील देशों के अनुपयुक्त मानवशक्ति अनुसंधान संस्थान से तीन अधिकारियों का एक शिष्टमंडल।

भारत सरकार से

श्रीमती कृष्णासाही, राज्य शिक्षा मंत्री, भारत सरकार।

श्री अनिल बोर्डिया, अतिरिक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

श्री पी० के० पटनायक, संयुक्त सचिव (योजना) मानव संसाधन विकास, भारत सरकार।

श्री वी० एन० चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

प्रो० एम० वी० माथुर, सदस्य चतुर्थ वेतन आयोग।

श्री जे० वी० राघवन, शिक्षा परामर्शदाता, योजना आयोग, नई दिल्ली।

राज्य शिक्षा विभाग से

श्री आत्म प्रकाश, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
शिक्षा मंत्री, असम सरकार।
डा० एस० भरेली, निदेश, लोक शिक्षा, आसाम,
उच्चतर शिक्षा निदेशक, आसास सरकार।
श्री एम० के० राज, शिक्षा सचिव, हिमाचल प्रदेश।
श्री एल० एम० जैन, शिक्षा आयुक्त, हरियाणा।
श्री एम० सी० वर्मा, शिक्षा सचिव, दिल्ली।

विश्वविद्यालयों से

प्रो० यशपाल, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली।
प्रो० रईस अहमद, उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
प्रो० मूनिस रजा उपकुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय।
प्रो० मंजूर आलम, उपकुलपति, कश्मीर विश्वविद्यालय।
प्रो० इकबाल नारायण, आई सी एस एस आर, नई दिल्ली।
प्रो० जी रामा रेड्डी, उपकुलपति, इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय नई दिल्ली।

विदेशों से शिष्टमंडल

जनसंख्या शिक्षा पर चीन का शिष्टमंडल।
नेपाल के अनुसंधान अधिकारी।

अन्य

डा० अमरीक सिंह, भूतपूर्व सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली।
डा० आर० सी० शर्मा, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली।

परिशिष्ट

परिशिष्ट एक

परिषद के सदस्य

(31-3-1986)

अध्यक्ष

श्रीमती सुशीला रोहतगी
राज्य शिक्षा मंत्री
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली

उपाध्यक्ष

प्रोफेसर सत्यभूषण,
निदेशक,
नीपा, नई दिल्ली

पदेन सदस्य

प्रो० यशपाल	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
श्री आनन्द स्वरूप	सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली
श्री एल० एस० नारायणन	वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
श्री आर० परमेश्वर	कार्मिक तथा प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली

श्री जे० वीरराघवन	सलाहकार (शिक्षा) योजना आयोग, नई दिल्ली।
प्रो० पी० एल० मल्होत्रा	निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

शिक्षा सचिव

श्री ए० हलीम चौधरी	शिक्षा सचिव, मणिपुर सरकार, न्यू सैक्टेरियल, इम्फाल-795001
श्री ए० के० वासु	सचिव, स्कूल शिक्षा, शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, राइटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता
श्री जे० सी० पंत	सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, विधान भवन, लखनऊ
श्री पी० बी० माथुर	सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर-302-004
थिरू टी० डी० सुन्दरराज	शिक्षा आयुक्त तथा सचिव शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार का सचिवालय, मद्रास-600009
थिरू राकेश मेहता	शिक्षा सचिव, पांडिचेरी-605 001

शिक्षा निदेशक/जन शिक्षा निदेशक

श्री एस० भराली	उच्चतर शिक्षा निदेशक, असम सरकार, काहलीपाड़ा, गोहाटी
श्री आर० बी० मिश्रा	नया सचिवालय, बिहार सरकार, पटना-800015
श्री अनिल राजदान	लोक शिक्षा निदेशक, हरियाणा सरकार, 30 बे बिल्डिंग, सैक्टर-17, चण्डीगढ़-160 017
श्री वी० वी० चिपलूंकर	शिक्षा निदेशक (प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा) महाराष्ट्र सरकार, सैन्ट्रल बिल्डिंग, पुणे-411 001
श्री फिलिपोज़ थोमस	जन शिक्षा निदेशक, केरल सरकार, लोक शिक्षा निदेशक कार्यालय, वाजुहथाकांड, त्रिवेंद्रम-695 014
श्री डी० एस० बेगी	शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशक, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110 054

प्रतिष्ठित शिक्षाविद्

प्रो० एन० आर० सेठ	निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान, वस्त्रापुर, अहमदाबाद
प्रो० मंजूर आलम	उपकुलपति, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
प्रो० नितेश डे	निदेशक, पंजाब राज्य लोक प्रशासन संस्थान, 36 सैक्टर 5 ए, चंडीगढ़
डा० पी० बी० शुक्ला	भूतपूर्व-अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ए-14/15, बसंत बिहा, नई दिल्ली-110 057
डा० के० वेंकट सुब्रामनियम	उपकुलपति, पांडीचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय, 212 राम अंतर्राष्ट्रीय बिल्डिंग, अन्ना मलाई पांडीचेरी-1
प्रो० आबद अहमद	निदेशक, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

कार्यकारी समिति के सदस्य

श्री पी० के० पटनायक	संयुक्त सचिव (योजना) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) नई दिल्ली
डा० आर० पी० सिंघल	कार्यकारी निदेशक, नीपा, नई दिल्ली

संकाय सदस्य

प्रो० के० एम० बहाउद्दीन	डीन (अनुसंधान तथा प्रशिक्षण), नीपा, नई दिल्ली

सचिव

श्री आर० पी० सक्सेना	रजिस्ट्रार, नीपा, नई दिल्ली

परिशिष्ट दो

कार्यकारिणी समिति के सदस्य

(31-3-1986)

1. प्रोफेसर सत्य भूषण,
   निदेशक,
   नीपा,
   नई दिल्ली — **सभापति**

2. श्री एल० एस० नारायणन
   वित्तीय सलाहकार,
   शिक्षा मंत्रालय,
   शास्त्री भवन,
   नई दिल्ली

3. श्री० पी० के० पटनायक,
   संयुक्त सचिव (योजना)
   शिक्षा मंत्रालय,
   नई दिल्ली

4. श्री जे० सी० पंत,
   शिक्षा सचिव,
   उत्तर प्रदेश सरकार
   विधान भवन,
   लखनऊ-226001

5. प्रो० एन० आर सेठ,
   निदेशक,
   भारतीय प्रबंध संस्थान
   अहमदाबाद

6. श्री जे० वीरराघवन
   सलाहकार (शिक्षा)
   योजना आयोग,
   योजना भवन,
   नई दिल्ली

7. डा० आर० पी० सिंघल,
   कार्यकारी निदेशक,
   नीपा,
   नई दिल्ली

8. श्री आर० पी० सक्सेना,
   रजिस्ट्रार, **सचिव**
   नीपा,
   नई दिल्ली

परिशिष्ट तीन

वित्त समिति के सदस्य

(31-3-1986)

1. प्रो० सत्य भूषण — सभापति
   निदेशक,
   नीपा, नई दिल्ली

2. श्री एल० एस० नारायणन
   वित्तीय सलाहकार,
   शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन,
   नई दिल्ली

3. श्री पी० के० पटनायक,
   संयुक्त सचिव (योजना)
   शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन,
   नई दिल्ली

4. थीरू टी० डी० सुन्दर राज
   आयुक्त, सचिव,
   तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु सचिवालय,
   मद्रास-600001

5. डा० आर० पी० सिंघल
   कार्यकारी निदेशक,
   नीपा, नई दिल्ली

6. श्री आर० पी० सक्सेना — **सचिव**
   रजिस्ट्रार,
   नीपा, नई दिल्ली

परिशिष्ट चार

कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य

(31-3-1986)

1. प्रो० सत्य भूषण — सभापति
   निदेशक
   नीपा,
   नई दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

2. डा० टी० एन० धर, — सदस्य
   संयुक्त सचिव, (एस एण्ड आई)
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली

3. श्री पी० के० पटनायक — सदस्य
   संयुक्त सचिव (योजना)
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली

4. श्री वाई० एन० चतुर्वेदी — सदस्य
   संयुक्त सचिव,
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली

योजना आयोग

5. डा० (श्रीमती) आर० थमाराजेश्री — **सदस्य**
सलाहकार (एल ई एम)
योजना आयोग, योजना भवन,
नई दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

6. प्रो० एस० के० खन्ना — **सदस्य**
सचिव,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
नई दिल्ली

राज्य शिक्षा सचिव तथा लोक शिक्षा निदेशक

7. श्री वाई० पी० रामाराव — **सदस्य**
सचिव,
आन्ध्र प्रदेश सरकार,
हैदराबाद

8. श्री उज्जवल दीदार सिंह — **सदस्य**
लोक शिक्षा निदेशक
(उच्चतर शिक्षा)
पंजाब सरकार,
चण्डीगढ़

अकादमी सदस्य

9. प्रो० इकबाल नारायण — **सदस्य**
सदस्य सचिव,
आई सी एस एस आर
35 फिरोजशाह रोड,
नई दिल्ली

10. प्रो० वी० जी० कुलंदाईस्वामी — सदस्य
उपकुलपति
अन्ना विश्वविद्यालय,
सरदार पटेल रोड, गूंडी
मद्रास-600025

11. प्रो० शिव के० मित्रा — सदस्य
पहली मंजिल,
बी-4/139, सफदरजंग इन्क्लैव,
नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद

12. प्रो० ए० के० जलालुद्दीन — सदस्य
संयुक्त निदेशक
एन सी ई आर टी
नई दिल्ली

कार्यकारी निदेशक

13. डा० आर० पी० सिंघल, — सदस्य
कार्यकारी निदेशक,
नीपा, नई दिल्ली

संकाय सदस्य

14. प्रो० के० एम० बहाउद्दीन — सदस्य
डीन (अनुसंधान तथा प्रशिक्षण)
नीपा, नई दिल्ली

15. डा० सी० एल० सपरा — सदस्य
वरिष्ठ अध्येता,
नीपा, नई दिल्ली

रजिस्ट्रार

16. श्री आर० पी० सक्सेना — सचिव
रजिस्ट्रार
नीपा, नई दिल्ली

परिशिष्ट पाँच

प्रकाशन सलाहकार समिति के सदस्य

(31-3-1986)

1. प्रो० सत्य भूषण — सभापति
   निदेशक
   नीपा, नई दिल्ली

2. डा० आर० पी० सिंघल
   कार्यकारी निदेशक
   नीपा, नई दिल्ली

3. डा० (श्रीमती) एस० सरस्वती
   निदेशक (प्रकाशन)
   आई सी एस एस आर
   नई दिल्ली

4. श्री सैम्युअल इजराइल
   प्रकाशन सलाहकार,
   बुक शेल्फ
   29, सुन्दर नगर मार्किट
   नई दिल्ली

5. डा० एम० मुखोपाध्याय
   वरिष्ठ अध्येता
   नीपा, नई दिल्ली

6. श्री एम० एम० कपूर
   अध्येता
   नीपा
   नई दिल्ली

7. डा० (श्रीमती) कुसुम प्रेमी **सदस्य**
अध्येता
नीपा
नई दिल्ली

8. श्री बी० सैल्वराज **सदस्य सचिव**
प्रकाशन अधिकारी
नीपा
नई दिल्ली

(9 और 10) मिटिंग के कार्य विवरण के अनुसार निदेशक द्वारा दो सदस्यों को सहयोगी के रूप में लिया जाना।

परिशिष्ठ-छः

संकाय और प्रशासनिक स्टाफ

(31-3-1986)

सत्य भूषण	निदेशक
आर० पी० सिंघल	कार्यकारी निदेशक
के० एम० बहाउद्दीन	डीन (अनुसंधान और प्रशिक्षण)

शैक्षिक प्रशासन एकक

एन० एम० भागिया	वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
एम० मुखोपाध्याय	वरिष्ठ अध्येता
के० जी० विरमानी	वरिष्ठ अध्येता
सी मेहता	सह अध्येता
के० सुधा राव	सह अध्येता

शैक्षिक वित्त एकक

सी० बी० पद्मनाभन	वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
जे० बी० जी० तिलक	अध्येता
वाई जोसफीन,	वरिष्ठ तकनीकी सहायक

शैक्षिक योजना एकक

ब्रह्मप्रकाश	वरिष्ठ अध्येता तथा अध्यक्ष,
वाई० पी० अग्रवाल	सह अध्येता
एन० वी० वरगीज	सह अध्येता
एल० एस० गणेश	सह अध्येता

शैक्षिक नीति एकक

कुसुम के० प्रेमी	अध्येता तथा अध्यक्ष
के० सुजाता	सह अध्येता
एस० सी० नूना	सह अध्येता
एस० एम० आई० ए० जैदी	वरिष्ठ तकनीकी सहायक

उच्चतर शिक्षा एकक

जी० डी० शर्मा	वरिष्ठ अध्येता तथा अध्यक्ष
शक्ति आर अहमद	वरिष्ठ अध्येता
एम० एम० रहमान	वरिष्ठ तकनीकी सहायक

अन्तर्राष्ट्रीय एकक

उषा नायर	अध्येता और अध्यक्ष
अंजना मंगलागिरी	सह अध्येता

स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा एकक

सी० एल० सपरा	वरिष्ठ अध्येता तथा अध्यक्ष
एस० एस० दुदानी	अध्येता
सुषमा भागिया	अध्येता
टी० के० डी० नायर	अध्येता
जुबैदा हबीब	वरिष्ठ तकनीकी सहायक
रशमी दीवान	वरिष्ठ तकनीकी सहायक

उप राष्ट्रीय पद्धतियां तथा प्रलेखन एकक

एम० एम० कपूर	अध्येता तथा अध्यक्ष
आर० एस० शर्मा	सह अध्येता
एन० डी० कांडपाल	प्रलेखन अधिकारी

मानचित्र कक्ष

पी० एन० त्यागी	वरिष्ठ तकनीकी सहायक

समन्वय

मंजु नरूला	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (तदर्थ)

(मीना श्रीवास्तव वरिष्ठ तकनीकी सहायक, समन्वय प्रशिक्षण पर)

अनुसंधान परियोजना स्टाफ

जी० खुराना	परियोजना अध्येता
जयश्री जलाली	परियोजना सह अध्येता
ए० मैथ्यू	परियोजना सह अध्येता
अब्दुल अजीज	परियोजना सह अध्येता
एस० क्यू० ए० नक्वी	परियोजना सह अध्येता
अरुण सी० मेहता	परियोजना सह अध्येता
नलनी जुनैजा	परियोजना सहअध्येता
एम० एम० खान	परियोजना प्रोग्रामर
इफ्तिकार अहमद	परियोजना सहायक
सी० आर० के० मूर्ति	परियोजना सहायक
सुनीता चुग	परियोजना सहायक
प्रौमिला मैनन	परियोजना सहायक
सरोज पांडे	परियोजना सहायक
सतपाल सिंह खताना	परियोजना सहायक
एस० सी० बराल	परियोजना सहायक
जय प्रकाश,	परियोजना सहायक
मंजू रूडोला	परियोजना सहायक
वी० ए० राव	परियोजना सहायक
ओ० डी० त्यागी	परियोजना सहायक
कौसर विजारत	परियोजना सहायक

इलैक्ट्रानिक डाटा प्रौसेसिंग एण्ड रिप्रोग्राफिक एकक

वी० मुरलीधर	कम्प्यूटर प्रोग्रामर

प्रकाशन एकक

बी० सेल्वाराज	प्रकाशन अधिकारी
एम० एम० अजवानी	वरिष्ठ प्रकाशन सहायक

हिन्दी कक्ष

एस० बी० राय	हिन्दी संपादक
रामकिशन	हिंदी अनुवादक

पुस्तकालय

निर्मल मल्होत्रा	पुस्तकाध्यक्ष
दीपक मकौल	कनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष

कार्यालय प्रशासन

आर० पी० सक्सेना	रजिस्ट्रार,
एस० सुंदरराजन	वित्त अधिकारी,
के० एल० दुआ	प्रशासनिक अधिकारी
जी० एस० भारद्वाज	अनुभाग अधिकारी
टी० आर० ध्यानी	कार्यालय अधीक्षक
एम० एल० शर्मा	कार्यालय अधीक्षक
चैरियन थॉमस	लेखापाल

वार्षिक लेखा और अंकेक्षण रिपोर्ट

परिशिष्ट सात

1-4-85 से 31-3-1986 की अवधि का प्राप्ति लेखा

	प्राप्ति	
अर्थ शेष		
हस्तगत रोकड़	25,258.86	
अग्रदाय	2,127.50	
यूनेस्को कूपन	54.00	
बैंक में रोकड़	8,19,929.73	8,47,369.69
भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान		
योजनेतर	60,41,000.00	
योजनागत	25,17,000·00	85,58,000·00
कार्यालय प्राप्तियां		
लाइसेंस शुल्क	42,220·50	
पानी-बिजली प्रभार	3,451·65	
के. स. स्वा. योजना की वसूलियां	78.00	
ई. डी. पी. आर. प्राप्तिया	2,527·00	
अन्य प्राप्तियां	6,486.25	
स्वत्व-शुल्क (रायल्टी)	10,080·00	
कार्यक्रम प्राप्ति	1,58,531·21	
कर्मचारियों के अ. भ. नि. के		
अपवर्तित शेयर	1,20,631·00	
अवकाश वेतन और पेंशन का अंशदान	9,963·80	
पेंशन के लाभों की पूंजी		
का मूल्य	15,853·85	

1-4-85 से 31-3-86 की अवधि को भुगतान लेखा

	भुगतान	
संस्थागत व्यय		
वेतन		
योजनेतर	32,98,820·15	
पेंशन और उपादान	17,206·00	
भविष्य निधि (अ. भ. नि. का नियोक्ता अंश तथा सं. भ. नि.)		
पर ब्याज तथा प्रोत्साहन बोनस	1,33,380·65	
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	31,469·20	
यात्रा व्यय	22,880·80	35,03,756·80
कार्यालव व्यय (अन्य खर्चे)		
योजनेतर	11,00,000.00	
योजनागत	1,69,709.40	12,69,709·40
छात्रावास (योजनेतर)		
आवर्ती व्यय	2,11,062·00	
फर्नीचर और उपस्कर (पूंजीकृत)	70,381·70	2,81,443·70
अकादमिक गतिविधियां		
कार्यक्रम व्यय	10,68,004·96	
अनुसंधान अध्ययन	2,96,798·00	
आंकड़े बैंक	3,400·00	
अंतर्राष्ट्रीय दौरे	63,809·00	
कार्यक्रम शुल्क	1,600·00	
पुस्तकालय की पुस्तकें		
(पूंजीकृत)	1,77,704·45	
प्रकाशन	36,225.70	16,47,542.11

प्राप्ति		
अप्रयोज्य (बेकार) भण्डार की बिक्री से आय	32,376·75	4,02,200.01
छात्रावास		
छात्रावास किराया		2,06,325.00
ब्याज		
ब्याज वाली पेशगियों पर ब्याज	461·65	
अल्पकालीन जमा राशि पर ब्याज	8,882·22	
बचत बैंक लेखा पर ब्याज	9,477·79	
निवेश पर ब्याज	94,109.32	1,12,930·98
प्रायोजित कार्यक्रम और अध्ययन		
कार्यक्रम और अध्ययन प्राप्तियां		18,46,795·41
जमा		
उचंत लेखा	9,816·70	
प्रतिशत जमा	1,500·00	
कश्मीर विश्वविद्यालय	3,000·00	
स्टाफ कार	10,000·00	24,316·70
वसूली योग्य पेशगियां		
साइकिल पेशगी	2,175·00	
त्योहार पेशगी	14,220·00	
मकान निर्माण पेशगी	50,348·00	
मोटर कार पेशगी	7,764·00	
पंखा पेशगी	200·00	
विविध पेशगी-एन. सी. टी. II	110·50	74,817·50
प्रेषण		
प्रतिनियुक्तियों का अंशदायी भ· नि.		1,350·00
		1,20,74,105.29

हस्ताक्षर
(एस. सुंदरराजन)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान

भुगतान		
पूंजी व्यय		
टाइपलेखन की मशीन	6,176·50	
फर्नीचर और उपस्कर	37,485·15	
अन्य कार्यालय उपस्कर	2,07,837·75	
स्टाफ कार	87,569·40	3,39,068.80
प्रायोजित कार्यक्रम और अध्ययन		
कार्यक्रम और अध्ययन व्यय		17,25,073.11
जमा (योजनागत)		
के. लो. नि. वि. के पास जमा	16,85,667.00	
उचंत लेखा	25,358.46	
सुरक्षा	18,600·00	
कश्मीर विश्वविद्यालय	1,343·00	17,30,968·46
वसूली योग्य पेशगियां (योजनेतर)		
साइकिल पेशगी	1,350·00	
त्यौहार पेशगी	26,000·00	
मकान निर्माण पेशगी	83,110·00	
पंखा पेशगी	200·00	
मोटरकार पेशगी	39,600·00	
विविध पेशगी	27,289·50	1,77,549.50
अंतशेष		
हस्तगत रोकड़	1,833·20	
अग्रदाय	2,750·00	
बैंक में रोकड़	13,94,410·21	13,98,993.41
	कुल	1,20,74,105·29

हस्ताक्षर
(आर. पी. सिंघल)
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(सत्यभूषण)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान,
नई दिल्ली

31 मार्च, 1986 को अंतशेष का विवरण

क्रम सं०	व्यय का शीर्ष	अर्थशेष	प्राप्तियां	कुलयोग
1.	योजनेतर	2,53,647.51	68,48,662.99	71,02,310.50
2.	योजनागत	2,782.14	25,17,000.00	25,19,782.14
3.	प्रायोजित कार्यक्रम और अध्ययन	5,52,259.68	18,46,905.91	23,99,165.59
4.	उचंत लेखा	33,092.06	12,816.70	45,908.76
5.	प्रेषण	5,588.30	1,350,00	6,938.30
	कुल	8,47,369.69	1,12,26,735.60	1,20,74,105.29

हस्ताक्षर
(एस० सुंदरराजन)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

भुगतान	शेष
65,81,350.00	5,20,960.50
23,41,987.31	1,77,794.83
17,25,073.11	6,74,092.48
26,701.46	19,207.30
	6,938.30
1,06,75,111.88	13,98,993.41

हस्ताक्षर
(आर० पी० सिंघल)
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान

हस्ताक्षर
(सत्य भूषण)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान

वर्ष 1985-86 के लिए आय और व्यय

व्यय	
स्थापना व्यय	35,03,756.80
कार्यालय व्यय	12,69,709.40
छात्रावास व्यय	2,11,062.00
अकादमिक गतिविधियां	14,69,837.66
व्यय से अधिक आय	22,37,935.18
	86,92,301.04

हस्ताक्षर
(एस० सुन्दरराजन)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान

आय व्यय का लेखा

आय

सहायता अनुदान		85,58,000,00	
घटाएं : पंजीकृत अनुदान			
कार्यालय वस्तुएं	3,39,068.80		
पुस्तकालय की पुस्तकें	1,77,704.45		
छात्रावास की वस्तुएं	70,381.70	5,87,154.95	79,70,845.05
कार्यालय प्राप्तियां			4,02,200.01
छात्रावास प्राप्तियां			2,06,325.00
ब्याज			1,12,930.98
		कुल	86,92,301.04

हस्ताक्षर
(आर० पी० सिंघल)
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान

हस्ताक्षर
(सत्यभूषण)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान

31 मार्च, 1986 को तुलन-पत्र

देयताएं		
पूंजीकृत अनुदान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	1,01,15,539.50	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	5,87,154.95	
घटाएं : पूंजी निवेश घट्टे खाते में	1,84,672.03	
घटाएं समायोजन द्वारा	6,744.83	1,05,11,277.59
प्रायोजित कार्यक्रम प्राप्तियां		
पूंजीकृत प्राप्तियां		2,91,204.00
व्यय से अधिक आय		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	57,67,609.89	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	22,37,935.18	
समायोजन द्वारा परिवर्धन	6,744.83	80,12,289.90
निर्धारित कार्यक्रम और अध्ययन		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	7,44,296.27	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	18,46,795.41	
घटाएं : वर्ष के दौरान व्यय	17,25,073.11	8,66,018.57
भविष्य निधि		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	9,37,819.02	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	6,27,842.98	
घटाएं : वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	4,26,411.00	11,39,251.00
उचंत लेखा		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	33,092.06	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	12,816.70	
घटाएं : वर्ष के दौरान समाशोधन	26,701.46	19,207.30

परिसंपत्तियां		
भूमि और भवन		
उपस्कर और मशीनें, फर्नीचर और जुड़नार, स्टाफ कार सहित गाड़ियां, टाइपराइटर आदि		55,88,382.51
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	32,21,764.74	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	7,00,654.50	
घटाएं : परिसंपतियों के मूल्य को हानि	1,83,740.51	37,38,678.73
पुस्तकालय की पुस्तकें		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	12,99,557.64	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,77,704.45	
घटाएं : मूल्य की हानि	931.52	14,76,330.87
भविष्य निधि का निवेश		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	6,98,822.50	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,50,000,00	9,48,822.50
जमा		
प्रतिभूति जमा		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	41,540.00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	18,600.00	
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस की गई	11,500.00	48,640.00
के० लो० वि० वि० के पास जमा	50,97,079.57	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	16,85,667.00	67,82,746.57
वसूली योग्य पेशगियां		
मोटर कार पेशगी	31,836.00	
मकान निर्माण पेशगी	3,67,866.05	
त्योहार पेशगी	17,280.00	
साइकिल पेशगी	1,265.00	
विविध पेशगी		
नीपा	57,915.25	
एन० सी० टी०-II	1,91,926.09	6,68,088.39

उपहार और दान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	910.52	910.52
जमा		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	2,500.00	2,500.00
प्रेषण		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	5,588.30	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,350.00	6,938.30
		2,08,49,597.18

हस्ताक्षर
एस० सुन्दरराजन
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

विविध कर्जदार		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	8,485.70	8,485.70
रोकड़ शेष		
हस्तगत	1,833.20	
अग्रदाय	2,750.00	
चालू खाता	13,94,410.21	
सा० भ० नि०/अ० भ० नि० खाता	1,90,428.50	15,89,421.91
		2,08,49,597.18

हस्ताक्षर
(आर० पी० सिंघल)
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान

हस्ताक्षर
(सत्यभूषण)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान

वर्ष 1985-86 के लिए निर्धारित कार्यक्रमों के अध्ययन के लिये लेखा

क्रम सं०	कार्यक्रम/अध्ययन का नाम	अर्थशेष	वर्ष की अवधि में प्राप्ति
1	2	3	4
गृह मंत्रालय (भारत सरकार)			
1. अनुसंधान परियोजनाएं :		(—) 21,869.45	1304.50
(i) आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययन और			
(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण के साक्षात्कार			
2. अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास का अध्ययन एकक		(—) 95,105.20	—
3. शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) नमूना अध्ययन : शैक्षिक रूप से पिछड़े और उन्नत राज्यों में निरीक्षण पद्धति और व्यवहार का प्रारूप		1,322.05	—
4. जनसंख्या शिक्षा परियोजना (एन० सी० ई० आर० टी०)		12,362.45	—
5. राष्ट्रीय अध्यापक आयोग II			
(i) केन्द्रीय तकनीकी एकक			
(ii) आयोग की यात्राओं का आयोजन		2,64,898.56	—
6. अनौपचारिक शिक्षा के एक मूल्यांकन अध्ययन के लिए प्रायोगिक परियोजना		—,884.50	8,52,000.00
7. योजना आयोग, भारत सरकार शिक्षा और रोजगार के लाभकारी संबंधों पर अध्ययन		16,258.20	—

कुल	जोड़व्यय	अंतशेष
5	6	7
(—)20,564.95	172.80	(—)20,737.75
(—)95,105.20	(—)	(—)95,105.20
1,322·05	1,322.05	कुछ नहीं
12,362.45	—	12,362.45
2,64,898.56	4,916.60	2,59,981.96
8,51,115.50	8,26,446.70	24,668.80
16,258.20	666.10	15,592.10

8. इंजीनियरिंग कालेजों के प्रबंध का कार्यक्रम (आई० एस० टी० ई) आई० सी० एस० एस० आर० नई दिल्ली	2,206.70	9,102.60
9. राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रो० एस० सी० दुबें	(—) 14,001.16	—
10. वरिष्ठ अध्येतावृत्ति डॉ० जे० एस० आजाद	1,432.90	—
11. वरिष्ठ अध्येतावृत्ति डॉ० जे० एन० कौल	9,176.85	—
12. भारत में समाज विज्ञान अनुसंधान के लिए अनुसंधान परियोजना को वित्त व्यवस्था के अधीन किए गए आंकड़ों के आधार पर विश्लेषणात्मक मोनोग्राफ को तैयार करना	9,269.60	—
13. भारत में समान शिक्षा और समान अवसर के आधार पर समानता के विशेष संदर्भ के साथ वित्त प्रबंध की शिक्षा पर अध्ययन—केरल और उत्तर प्रदेश की स्कूल शिक्षा से संबंधित मामलों पर एक अध्ययन	(—) 12,700.95	17,475.00
अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और अध्ययन		
14. शिक्षा के लिए स्थानीय सहयोग का प्रबंध	4,549.90	—
15. दो राज्यों में शैक्षिक वित्त व्यवस्था तथा क्षमता पर अध्ययन	(—) 46.41	46.41
16. वैकल्पिक भविष्य और शिक्षा पर अध्ययन	555.42	—
17. भारत में शैक्षिक प्रबंध में नैदानिक अध्ययन पर राष्ट्रीय कार्य बल	7,570.67	8,036.30

11,309.30	11,309.30	कुछ नहीं
(—) 14,001.16	—	(—) 14,001.16
1,432.90	927.95	504.95
9,176.85	9,176.85	कुछ नहीं
9,269.60	—	9,269.60
4,774.05	2,260.00	2,514.05
4,549.90	4,549.90	कुछ नहीं
—	—	कुछ नहीं
555,42	555.42	कुछ नहीं
15,606.97	5,088.50	10,518.47

18. जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कार्य अभिलाषा पर अध्ययन		3,640.55	—
19. बंगला देश शिक्षा अधिकारियों का अध्ययन दौरे		(—)15,089.80	—
20. शैशिक प्रबंध में अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरे		(—)971.55	—
21. स्कूल नामांकन परियोजना के लिए पद्धति पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण सेमिनार		12,107.51	—
22. ग्रामीण विकास परियोजना पर शैक्षिक अवयव पर राष्ट्रीय बुहु अनुशासनिक कार्यशाला		27,522.02	—
23. श्रीलंका के शिक्षा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (1982-83)		7,111.17	—
24. श्रीलंका के शिक्षा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (1983-84)		38,158.52	—
25. श्रीलंका के क्षेत्रीय योजनाकार और प्रशासकों के लिए शैक्षिक प्रबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम		32,398.20	—
26. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन में उपाधि-पत्र-जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए 6 मास का पूर्व आगमन कार्यक्रम			
(i) श्री लंका		5,574.42	—
(ii) भूटान		8,827.75	—
(iii) मारिशस		3, 921.92	—
27 अफगानिस्तान के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	(—)	1,457.90	1457.90
28. फिलिपिंस के ओ. पी. एस. स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम		9, 766.75	—
29. एशिया और पैसिफिक के शैक्षिक योजनाकार और प्रशासकों के लिए प्रथम क्षेत्रीय संगोष्ठी		56,317.95	—
30. शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय उपाधि-पत्र		2,81, 495.84	7,71,707.89

3,640.55	3,640.55	कुछ नहीं
(—) 15,089.80	89.70	(—) 15,179.50
(—) 971.55	—	(—) 971.55
12,107.51	12,107.51	कुछ नहीं
27,522.02	4,040.90	234,81.12
7,111.17	7.111.17	कुछ नहीं
38,158.52	38,158.52	कुछ नहीं
32,398.20	32,398.10	कुछ नहीं
5,574.42	5,574.42	कुछ नहीं
8,827.75	8,827.75	कुछ नहीं
3,921.92	3.921.92	कुछ नहीं
—	—	कुछ नहीं
9766.75	9766.75	कुछ नहीं
56,317.95	—	56,317,95
10,53,203.73	5,52,684.65	5,00,519.08

31. दीर्घकालीन शैक्षिक योजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (थाईलैंड)	(—) 131.00	27,600.00
32. एशिया और पैसिफिक में उपक्षेत्रीय संगोष्ठी	76.40	—
33. उच्च शिक्षा की ग्रंथ सूची के विकास के लिए उच्च शिक्षा में ए. पी. ई. आई. डी. क्षेत्रीय सहकारी कार्यक्रम	(—) 3105.00	5,004.40
34. उच्च शिक्षा में प्रणाली विज्ञान के लिए क्षेत्रीय सहकारी कार्यक्रम	6457.50	—
35. यू. पी. ई. के योजना और प्रबंध पर राष्ट्रीय कार्यशाला	3946.53	—
36. पर्यावरणीय शिक्षा पर परामर्शी बैठक	40,207.76	—
37. भूटान के एक अधिकारी के लिए कार्यालय प्रबंध पर उच्चतर प्रशिक्षण कार्यक्रम	42525.10	—
38. दक्षिण एशिया में महिला शिक्षा की योजना और प्रबंध पर क्षेत्रीय कार्यशाला	—	1,27,459.70
39. अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के बीच अनुपूरक और समन्वित योजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला	—	17,775.00
40. मालदीव के एक अधिकारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	—	5,400.00

27,469.00	27,469.00	कुछ नहीं
76.40	76.40	कुछ नहीं
1899.40	1.899.40	कुछ नहीं
6457.50	300.00	6157.50
3946.53	598.00	3348.53
40,207.76	22,456.35	17,751,41
42,525.10	27,215,30	15,309.80
1,27,459.70	26.70	1,27,433.00
1,7775.00	23, 495.65	(—) 5,720.65
5,400.00	5,400.00	कुछ नहीं

41. माइक्रो लेवल शैक्षिक योजना पर क्षेत्रीय विकास कार्यशाला	—	—
42. शिक्षा के बाह्य वित्त प्रबंध का संगठन	—	—
43. विकेंद्रीकरण के लिए माइक्रो लेवल शैक्षिक योजना और प्रबंध एक मानदण्ड—लेखक का संविदा	—	2,425.71
योग	7,44,296.27	18,46,795.41

हस्ताक्षर
(एस. सुंदरराजन)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान

—	67,99.10	(—) 67,990.10
—	2,432.00	(—) 2432.00
2,425.81	—	2425.71
25,91,091.68	17,25,073.11	8,66,018.57

हस्ताक्षर
(आर· पी. सिंघल)
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(सत्यभूषण)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

वर्ष 1985-86 के लिए सा. भ. नि./अ. भ. नि. की प्राप्ति और भुगतान का लेखा

अर्थ शेष		2,38,996.52
अंशदायी पेशगियों की वसूली		4,94,462.33
ब्याज का स्थानांतरण, नियोक्ताओं का अंशदान, आई. बी. इत्यादि	1,32,696.37	
शेष ब्याज/वर्ष 1984-85 नियोक्ताओं के लिए नियोक्ताओं का अंशदान	684.28	1,33,380.65
कुल योग		8,66,839.50

हस्ताक्षर
(एस. सुंदरराजन)
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

1985-86 के लिए सा. भ. नि/अ. भ. नि. की प्राप्ति और भुगतान का लेखा	
पेशगियां और निकासी	3,05,780.00
नियोक्ताओं द्वारा अंशदान की निकासी	1,20,631.00
जमा किया गया निवेश	2,50.000,00
अंतशेष	1,90,428.50
कुल योग	8,66,839.50

हस्ताक्षर
(आर. पी. सिंघल)
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(सत्यभूषण)
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे और तुलन-पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर दिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा संस्थान की बहियों में दर्शाये गए लेखों के अनुसार ये लेखे और तुलन-पत्र उपर्युक्त रूप से तैयार किए गए हैं तथा कार्यकलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

हस्ताक्षर
निदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली
26-11-1986

लेखा परीक्षा रिपोर्ट
(वर्ष 1985-86 के लिए)

1. सामान्य

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान का प्रमुख वित्तीय स्रोत भारत सरकार है। वर्ष 1985-86 के दौरान इसकी अनुदान की राशि 85.58 लाख रुपये थी जिसमें 60.41 लाख योजनेत्तर और 25.17 लाख योजना के अन्तर्गत था।

2. लेखा सम्बन्धी टिप्पणियां

2.1 परिसंपत्तियां : संस्थान के पास 31 मार्च, 1986 में स्थाई परिसम्पत्तियां 108.03 लाख थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

	(रु० लाख में)
(i) भूमि और भवन	55.88
(ii) उपकरण, मशीनें, फर्नीचर तथा वाहन आदि	37.39
(iii) पुस्तकालय की पुस्तकें	14.76
योग	108.03

संस्थान ने सभी परिसम्पत्तियों के ब्यौरेवार विवरण वाले संपत्ति रजिस्टर तथा स्टाफ रजिस्टर पूरे नहीं किए हैं। इसके फलस्वरूप खाते में दिखाई गई परिसंपत्तियों का मूल्य सत्यापित नहीं किया जा सका।

2.2 भौतिक सत्यापन

1979-80 के बाद के स्टोर तथा स्टाक आदि का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका (इसमें छात्रावास का तथा पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन क्रमश: 1984-85 तथा 1985-86 में किया गया है)। छात्रावास तथा पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन तैयार नहीं था और इसी कारण लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सका केवल खोई हुई पुस्तकों, जो 10,698+87.486+83.795 की थी, की सूची प्रस्तुत की गई। इन पुस्तकों को खोजने का कार्य अथवा इस हानि को बट्टे खाते में डाल दिए जाने के विषय में कार्य किया जाना शेष है। संस्थान ने बताया (नवम्बर, 1986) की स्टेशनरी, फर्नीचर तथा साज-सज्जा, कार्यालय उपकरण तथा छात्रावास का भौतिक सत्यापन पूरा किया जा चुका है और इनकी रिपोर्टों की जांच की जार ही है।

2.3 सी० पी० डब्ल्यू० डी० से अग्रिम राशियों के विषय में समझौता न होना

(क) संस्थान के तुलन-पत्र में यह दर्शाया गया है कि संस्थान ने 31 मार्च, 1986 को 67.83 लाख की राशि अग्रिम के रूप में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए सी० पी० डब्ल्यू० डी० को दी है। वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	राशि लाखों में
1979-80	7.33
1980-81	
1981-82	11.69
1982-83	0.73
1983-84	11.82
1984-85	19.39
1985-86	16.87
योग	67.83

इसके प्रतिकूल अग्रिमों के रजिस्टरों (राज्यीय अनुभाग) में इतिशेष 91.41 लाख दर्शाया गया है। इस विषय में समझौतों तथा लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है।

(ख) 1982-83 में 34.28 लाख रुपये की लागत से टाइप I से V तक स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, परन्तु 27.01 लाख की अग्रिम राशि का ही समावोजन किया गया था।

3. नीपा के कार्यक्रमों की समीक्षा

संघ के ज्ञापन के 41 वें नियम तथा संस्थान नियमावली में समय-समय पर संस्थान के कार्यों की समीक्षा करने की व्यवस्था है। सरकार ने संस्थान की स्थापना के 15 वर्ष पूरे हो जाने पर भी इसकी कार्य प्रणाली तथा प्रगति की कोई समीक्षा नहीं की है। इस विषय में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है (सितम्बर, 1986)

हस्ताक्षर
निदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व-1

नई दिल्ली
26-11-86

नीपा के अंकेक्षण रिपोर्ट पर अनुच्छेदवार टिप्पणियां : वर्ष 1985-86

पैराग्राफ-1 सामान्य : कोई टिप्पणी नहीं

अनुच्छेद 2.1 परिसम्पत्तियां

संस्थान के प्रारम्भ से ही खरीदी गई। प्राप्त की गई परिसम्पत्तियों के स्टाक रजिस्टर नियमानुसार रखे गए हैं। तथापि संस्थान सामान्य वित्तीय नियमों 1962 में दिये गए नियम के अनुसार परिसंपत्तियों का रजिस्टर नहीं रख रहा था। संस्थान ने लेखा परीक्षा के इच्छानुसार इस कार्य की भी हाथ में लिया है तथा वर्ष 1982-83 तक की प्रविष्टियां पूरी कर ली गई हैं। शेष वर्षों की प्रवष्टियां भी पूरी कर ली जाएंगी तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक रजिस्टर को अद्यतन कर लिया जाएगा और अगले लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुच्छेद 2.2 भौतिक सत्यापन

स्टोरों, स्टाकों तथा पुस्तकालय का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया गया है। स्टेशनरी मदों, फर्नीचर तथा साज-सज्जा तथा कार्यालय उपकरणों से संबंधित सत्यापन रिपोर्टों की पहले ही जांच कर ली गई है। छात्रावास मदों तथा पुस्तकालय की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं और वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त से पहले इनकी जाँच कर ली जाएगी तथा सभी औपचारिकतायें पूरी कर ली जाएगीं। इसे अगले लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुच्छेद 2.3 सी० पी० डब्ल्यू० डी० से अग्रिम राशि के विषय में समझौता न होना

सी० पी० डब्ल्यू० डी० प्राधिकारियों से निर्माण तथा अनुरक्षण कार्य से सम्बन्धित जमा राशियों का लेखा प्रस्तुत करने के लिए पहले ही अनुरोध किया जा चुका है। इस मामले पर अन्तर्विभागीय समिति की बैठक, जो महीने में एक बार आयोजित की जाती है, में भी विचार किया गया। इसके फलस्वरूप सिविल निर्माण अनुभाग से लेखे प्राप्त हो चुके हैं। तथापि विद्युतीय निर्माण अनुभाग तथा सिविल और वि्तीय अनुरक्षण अनुभागों से लेखे के विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस मामले को सी० पी० डब्ल्यू० डी० प्राधिकारियों के समक्ष दृढ़तापूर्वक उठाया गया है। जैसे ही लेखा विवरण प्राप्त होंगे आवश्यक संशोधन करके उन्हें लेखा परीक्षा के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

सी० पी० डब्ल्यू० डी० को निर्माण कार्य के लिए जमा की गई राशि का वर्षवार विवरण इस प्रकार है—

वर्ष	राशि
1979-80	1575912.63
1980-81	1751851.00
1981-82	1522566.00
1982-83	1137596.00
1983-84	1233140.20
1984-85	1939043.00
1985-86	1685667.00
योग	10845775.83

उपरोक्त जमा राशियों में से वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 की अवधियों में 40,63,029,29.26 लाख रुपये का समायोजन किया जा चुका है। इस प्रकार 67,82,746.57 का इतिशेष, जिसका समायोजन अभी शेष है, तुलन-पत्र में परिवर्तित है।

इस विषय में यह प्रमाणित किया जा सकता है कि जमा निधियों के रजिस्टर में दिए गए विवरणों में वार्षिक सिविल तथा विद्युतीय अनुरक्षणों के लिए सी० पी० डब्ल्यू० डी० के वर्षवार भुगतान भी सम्मलित हैं। वार्षिकों के लिए सी० पी० डब्ल्यू डी० को किए जाने वाले भुगतान की राशि कार्यालय खर्चों में दी गई

और जमा निधियों के रजिस्टर द्वारा इनकी निकासी पर कड़ी दृष्टि रखी जाती है। अत: कोई भी विसंगति नहीं है और इसे लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

5-1-87 को वित्त तथा कार्यकारी समितियों की पिछली बैठकों में यह निर्णय लिया गया कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० से जमा निधियों के वर्षवार लेखा विवरण शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन वकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की सहायता प्राप्त की जा सकती है।

अनुच्छेद-3 नीपा के कार्यक्रमों की समीक्षा

संस्थान अपने कार्य तथा क्रियाकलापों की प्रगति का संक्षेप से मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक आधार पर नियमित रूप से केन्द्र सरकार को भेजता है। संस्थान प्रधानमंत्री के द्वारा अपने कार्य निष्पादन की समीक्षा के लिए एक अन्य मासिक रिपोर्ट नियमित रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजता है। कार्यकारी समिति ने जून 26, 1985 को आयोजित अपनी एक बैठक में समस्त प्राथमिकताओं के अन्तर्गत सातवीं पंच-वर्षीय योजना के संदर्भ में संस्थान के प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा अन्य क्रियाकलापों का विहंगावलोकन तथा गहन अध्ययन करने के लिए तथा सिफारशें प्रस्तुत करने के लिए स्वयं एक समिति नियुक्त की है। फरकरी 6,1986 को आयोजित कार्यक्रम समीक्षा समिति के कार्यक्रम की एक प्रति कार्यकारी समिति के सम्मुख प्रस्तुत की गई है।

राष्ट्रीय शैक्षिक नीति तथा क्रिया कार्यक्रम में शैक्षिक योजना तथा प्रबन्ध के क्षेत्रों में नए प्रतिबलों की पहचान की गई है। शैक्षिक नियोजकों तथा प्रबन्धकों के शिक्षण के लिए प्रस्तावित राज्य स्तरीय केन्द्रों तथा शिक्षा और प्रशिक्षण के जिला संस्थानों ने नीपा के संक्रियात्मक क्षेत्रों में नए आयामों का योगदान किया है। इस संदर्भ में कार्यकारी समिति संस्थान की संरचना तथा कार्यों सें उचित परिवर्तनों का सुझाव देने के विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने पर विचार कर सकती है जिससे संस्थान शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में तय कार्यों को अधिक प्रमाणिकता से पूरा कर सके।

5-1-1987 को आयोजित वित्त तथा कार्यकारी समितियों की पिछली बैठक में यह निर्माण लिया गया कि नीपा के कार्यक्रमों की समीक्षा के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा (आडिट) द्वारा किए गए प्रेक्षणों को मानव संसाधनों विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के नोटिस में लाया जाए जिससे संस्थान के कार्य की समीक्षा करने तथा उसकी संरचना और कार्यों में उचित परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए यदि आवश्यक हो तो नीपा के निदेशक की सलाह से, विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए जिसमें संस्थान शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में नए कार्यों को अधिक प्रभावित से पूरा कर सके।

LIBRARY & DOCUMENTATION UNIT
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D. 9366
Date 5-12-96

NIEPA DC
D09366